नीलंबूर अमर शहीदों को लाल-लाल सलाम!

उत्पीड़ित जनता के साहसिक नेता

कॉमरेड कुप्पु देवराज एवं

शहरी आंदोलन की आदर्श जन नेत्री

कॉमरेड कावेरी को

भावभीनी श्रद्धांजली!

रामागूडा अमर शहीदों को लाल-लालसलाम

ऊपरी श्रेणी में पार्टी व पीएलजीए के शहीदों की तसवीरें. इनके नाम जीवनियों में दिए गए.

दूसरी श्रेणी में मृत ग्रामीणों की तसवीरें. इनके नाम – बायें से श्यामला, कोमलु, जोम्मि, लक्ष्मण, कमला, जयराम, सिंदे

रामागुडा शहीदों में से कुछ की तसवीरें. इनमें से कुछ शहीदों की फाइल फोटो भी ऊपर की दो श्रेणियों में छपी हैं.

दुखद बात यह है कि सभी शहीदों की फाइल फोटो हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं.

प्रभात

अंदर के पन्नों में...

★ नीलंबूर शहीदों की जीवनियां 2
★ रामगूडा शहीदों की जीवनियां 6
★ नोटबंदी 19
★ प्रेस विज्ञप्तियां 25
★ नस्लीय भेदभाव व उत्पीड़न 28
★ फर्जी मुठभेड़ें 34
★ पीएलजीए प्रतिरोध 36

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

वर्ष-28 अंक-4 अक्टूबर-दिसंबर 2016 सहयोग राशि-15 रुपए

देश की उत्पीड़ित जनता के साहसिक नेता कॉमरेड कुप्पु देवराज को लाल–लाल सलाम!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड कुप्पु देवराज (रमेश/योगेश/रायन्ना) और पश्चिम घाटी की स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्या कॉमरेड अजिता (कावेरी) जब एक छोटी टीम के साथ केरल राज्य के पदुक्का फारेस्ट रेंज के मलप्पुरम जिले के नीलंबूर के करुलाय के पास ठहरे थे, पुलिस ने उन पर हमला किया. इस हमले में कॉमरेड देवराज (62) और कॉमरेड अजिता (52) की शहादत हुई. जबकि सोमन नामक एक कॉमरेड इस हमले में घायल हुए. वर्तमान में, केंद्र में सत्तारूढ़ ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी मोदी सरकार और केरल की सामाजिक फासीवादी सीपीआई(एम) की सरकार के नेतृत्व में माओवादी पार्टी के खात्मे के लिए केरल सरकार द्वारा गठित विशेष बल – थंडर बोल्ट्स ने 24 नवंबर, 2016 को इस आतंकी हमले को अंजाम दिया. कॉमरेड देवराज और कावेरी तीव्र डायबिटिज से जूझ रहे थे. इसी वजह मुठभेड़ के वक्त अन्य कॉमरेडों के साथ रिट्रीट नहीं कर पाए. पक्का समाचार के साथ ही हमारे कॉमरेड़ों के ऊपर हमला करके बीमारी की वजह से न हिल पाने की अवस्था में हमारे दोनों कॉमरेडों की हत्या की गई. कॉमरेड देवराज पत्नी, बच्चों, भाईयों व बहनों को अपने पीछे छोड़ गए हैं.

लंबे समय तक क्रांतिकारी आंदोलन की सेवा करने वाले कॉमरेड कुप्पु देवराज और अजिता को दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी एवं 'प्रभात' पत्रिका विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं और शहीदों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व सहानुभूति प्रकट करती हैं. इन दोनों प्यारे कॉमरेडों द्वारा स्थापित आदर्श और मूल्यों को ऊंचा उठाने, उनके आशयों को आगे बढ़ाने पार्टी, पीएलजीए, जनता ना सरकार और जन संगठनों की तमाम कतारों का आह्वान करती हैं.

कॉमरेड देवराज का क्रांतिकारी सफर करीबन चालीस वर्ष तक अविश्रांत जारी रहा. कॉमरेड देवराज शहरी गरीब एवं उत्पीड़ित दलित वर्ग से आये थे. उनके पूर्वज तमिलनाडु से बेंगुलूर गए थे. वे एक कंपनी में मजदूरी किया करते थे. जब से वे कार्यकर्ता बने थे, तब से उनका घर क्रांतिकारी क्रियाकलापों का केंद्र बन गया था.

1960 के दशक में नक्सलबाड़ी के सशस्त्र किसान संघर्ष की प्रेरणा से कर्नाटक राज्य के किसान और बुद्धिजीवियों ने जनता के बीच में काम करना शुरू किया था, जिनमें सिरहट्टी गांव के कोगानूरु गोनप्पा एक थे. नक्सलबाड़ी संघर्ष की राजनीती से वे गरीब जनता को लैस करने लगे थे. जमींदारों के गुंडों ने उनकी हत्या की थी.

उसके बाद दस वर्ष तक वहां कोई आंदोलन नहीं रहा. बाद में भाकपा (मा–ले)(पीपुल्सवार) का गठन हुआ था. देश भर के क्रांतिकारी कार्यकर्ता एवं लोग पार्टी के बैनर तले इकट्ठे होने लगे थे. इस तरह 1980 में कॉमरेड देवराज भी पार्टी के संपर्क में आए. कर्नाटक में क्रमशः अंशकालिक कार्यकर्ता विकसित होकर पार्टी सेल्स में संगठित हुए थे. उनमें से कॉमरेड देवराज एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उभरकर आए थे. कॉमरेड देवराज ने अन्य कॉमरेडों के साथ मिलकर छात्रों, मजदूरों, युवाओं के बीच राजनीतिक व सांगठनिक काम शुरू किया था. दरअसल पार्टी से परिचित होने के पहले से ही कॉमरेड देवराज ने अन्य कुछ लोगों के साथ मिलकर सर्वहारा वर्ग के बीच क्रांतिकारी राजनीतिक कार्य शुरु किया था.

1980–85 के बीच पार्टी सेल्स सक्रिय हो गए थे. शहीद कॉमरेड चेरुकूरी राजकुमार (आजाद) जिन्हें कर्नाटक राज्य में पार्टी के सांगठनिक कार्य के लिए भेज दिया गया था, के नेतृत्व में देवराज जल्द ही पेशेवर क्रांतिकारी बन गए थे. 1985 तक आठ कार्यकर्ता पेशेवर क्रांतिकारी बने थे जिनमें कॉमरेड देवराज अग्रिम पंक्ति में थे. ये पूर्णकालीन कार्यकर्ता बेंगलूर, कोलार व मैसूर नगरों में मजदूर, छात्र एवं युवाओं के बीच काम करते हुए उनकी विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन छेड़ रहे थे. उन्होंने एक सांस्कृतिक संस्था का भी गठन किया था.

इस सांस्कृतिक संस्था, पार्टी व जन संगठन के कार्यकर्ताओं ने दीर्घकालीन जन युद्ध और आंध्र प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के आंदोलनों के बारे में विस्तृत राजनीतिक प्रचार किया था. इस क्रम में 1985 तक कॉमरेड आजाद के

नेतृत्व में सैद्धांतिक व राजनीतिक एकता के साथ एक नेतृत्वकारी टीम गठित हुई थी, जिसमें कॉमरेड देवराज महत्वपूर्ण व्यक्ति थे.

केंद्रीय कमेटी में 1985 में उत्पन्न संकट के समय में कर्नाटक के इस नेतृत्वकारी दल ने सीसी में मौजूद अवसरवादी व विघटनकारी गुट के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई. कॉमरेड आजाद के नेतृत्व में कॉमरेड देवराज एवं साकेत राजन ने इस आंतरिक संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हालांकि इन्हें वर्ग संघर्ष का अनुभव ज्यादा नहीं था, लेकिन वे मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद के सिद्धांत, पार्टी की बुनियादी दस्तावेजों, हमारे देश व दुनिया के क्रांतिकारी इतिहास के अध्ययन से लैस होकर सैद्धांतिक व राजनीतिक रूप से मजबूत थे. पार्टी की दीर्घकालीन जन युद्ध की दिशा के साथ डटे हुए थे. सशस्त्र संघर्ष की राजनीति के रास्ते पार्टी के आगे बढ़ने में उन लोगों का योगदान रहा. उन लोगों के अध्ययन व विघटनकारी गुट के खिलाफ उनके सैद्धांतिक संघर्ष ने राज्य में भविष्य के पार्टी निर्माण के लिए सैद्धांतिक नींव डाली. बाद में उसी नींव ने इस टीम के राज्य कमेटी के रूप में विकसित होने में भी मदद की. इस टीम ने दमन के दौर में आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी का साथ दिया था. इस नेतृत्वकारी टीम की मदद से आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी कुछ महत्वपूर्ण कार्यभारों को सफलतापूर्वक संचालित कर सकी.

1987 में संपन्न पहले राज्य अधिवेशन में कॉमरेड आजाद कर्नाटक राज्य कमेटी सचिव के रूप में चुने गए थे, जबकि कॉमरेड साकेत राजन व कुप्पु देवराज इस कमेटी के सदस्य. इस अधिवेशन ने कृषि क्रांति के परिप्रेक्ष्य की रूपकल्पना की. उन्होंने राज्य के असमान सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर कर्नाटक के उत्तरी मैदानी इलाके जो आंध्र प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, में आंदोलन शुरू किया. आंदोलन को आगे बढ़ाने में नेतृत्व की प्रत्यक्ष भागीदारी के महत्व को कॉमरेड देवराज ने सटीक समझा था, इसीलिए राज्य कमेटी सदस्य के तौर पर इस देहाती आंदोलन की जिम्मेदारी उन्होंने ली. इस इलाके में एक जमींदार को सजा देकर उसकी जमीन पर कब्जा किया गया था. यहां के संघर्ष दो वर्ष तक जारी रहा. इस दौरान छात्र भी उल्लेखनीय संख्या में सक्रिय हुए थे.

बीदर, रायचूर जिलों के किसानों के बीच भी उन लोगों ने काम किया. किसानों को इकट्ठा करके, किसान संगठन का निर्माण कर सामंती विरोधी व राज्य विरोधी संघर्षों का नेतृत्व किया. उसी वक्त कैगा परमाणु केंद्र के खिलाफ संघर्ष सामने आया. उस संघर्ष के जरिए उन्होंने छात्र क्षेत्र में अपने काम का विस्तार किया और बीदर, रायचूर, चित्रदुर्गा, शिमोगा व धार्वाड जिलों में छात्र संगठन बना लिया. कैगा में संघर्ष एवं छात्रों के बीच काम के चलते पार्टी राज्य भर में जनता को परिचित हो गई.

1985–87 में, पार्टी में आए संकट के चलते केंद्रीय कमेटी कुछ समय के लिए स्थगित हो गई. राज्यों के आंदोलनों के संचालन के लिए कोई केंद्र नहीं रह गया था. उस समय आजाद और योगेश ने मिलकर कैडरों को मजबूती से बनाए रखने के लिए काफी प्रयास किया. तमिलनाडु के कैडरों को पार्टी के साथ बनाए रखने में भी कॉमरेड देवराज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

1990 में पार्टी ने दूसरे राज्य अधिवेशन का आयोजन किया. इस अधिवेशन में आंदोलनों की समीक्षा की गई. अधिवेशन ने यह महसूस किया था कि सामंती विरोधी आंदोलन में जुझारुपन से संबंधित कुछ कमियां हैं. इस अनुभव से सबक लेकर पार्टी को संगठित करने और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष नेतृत्व देने का उन्होंने निर्णय लिया. पार्टी में मौजूद गैर सर्वहारा रुझानों को सुधारने के लिए 1993 में राज्य प्लीनम आयोजित की गई. इस प्लीनम में यह कार्यभार लिया गया था कि पार्टी को विकसित करने व आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जनता की समस्याओं को लेकर उन्हें गोलबंद किया जाए.

कर्नाटक में जब राष्ट्रीयता की समस्या सामने आई, पार्टी ने कन्नडिगों के मुद्धे पर लड़ने की आवश्यकता को समझ लिया था और इसके लिए एक संगठन बनाया था.

1991 में अखिल भारतीय स्तर में पार्टी में दूसरा संकट सामने आया था. इस दौरान कर्नाटक राज्य कमेटी ने अल्पमत गुट के गलत रुझानों का पर्दाफाश करते हुए एक दस्तावेज लिखी थी. उस अवसरवादी गुट के खिलाफ संघर्ष करने 1992 में सभी कैडरों का आह्वान किया था. उस आह्वान का मकसद था, पार्टी के सभी कैडर विघटनकारी गुट के बारे में समझें और वैचारिक संघर्ष करें.

1995 में संपन्न अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन के पहले आयोजित कर्नाटक राज्य अधिवेशन में देवराज ने राज्य कमेटी के सचिव की जिम्मेदारी ली. अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन में कॉमरेड देवराज केंद्रीय कमेटी के वैकल्पिक सदस्य चुने गए थे. 1997 में वे पूर्णकालीन सीसी सदस्य बने थे. उसी समय से पार्टी की कर्नाटक राज्य इकाई में आंतरिक संघर्ष शुरू हुआ था जिसके चलते आंदोलन के आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न हुई.

2001 में आयोजित पूर्व की पीपुल्सवार पार्टी की 9वीं कांग्रेस में कॉमरेड देवराज फिर से सीसी सदस्य चुने गए थे. उस समय सीसी ने दक्षिण–पश्चिम रीजनल ब्यूरो (एसडब्ल्यूआरबी) गठित किया, जिसका कॉमरेड देवराज सदस्य बने थे. उसी समय परस्पेक्टिव इलाके को बदलने

का प्रस्ताव राज्य कमेटी ने सीसी के सामने रखा था. उस प्रस्ताव का अनुमोदन करनेवाली सीसी ने एक पक्की योजना बनायी. पहले कमेटी ने उस इलाके की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया. कॉमरेड साकेत राजन के साथ कॉमरेड कुप्पु देवराज ने 21 वीं सदी की शुरुआत में इस परस्पेक्टिव इलाके में आंदोलन को आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी.

जब परस्पेक्टिव इलाके में काम की शुरुआत हुई थी, दक्षिणपंथी अवसरवादियों ने यह कहते हुए कि यह सफल नहीं होगा, उस पर पत्थर फेंकना शुरू किया था. दो पार्टियों के विलय और सीपीआई (माओवादी) की स्थापना के वे खिलाफ थे. ऐसी हालत में कॉमरेड साकेत राजन दुश्मन के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हुए थे. उनकी शहादत के बाद कॉमरेड देवराज ने रीजनल ब्यूरो की मदद से उस दक्षिणपंथी गुट के खिलाफ संघर्ष जारी रखा. बहुसंख्यक कॉमरेड्स पार्टी दिशा के पक्ष में खड़े हो गए. आखिर 2006 में संपन्न राज्य अधिवेशन में उक्त संकट का हल हुआ और अवसरवादी गुट पार्टी छोड़कर चला गया था.

उन अवसरवादियों का सामने करने के लिए एक दस्तावेज जिसका नाम 'अवसरवादी कभी क्रांतिकारी द्वंद्वात्मकता को नहीं समझ सकते हैं' को जारी किया गया था. उस दस्तावेज की रचना में कॉमरेड देवराज की महत्वपूर्ण भूमिका रही. उसी समय तमिलनाडु के मधुरई और उसके इर्द–गिर्द के जिलों में सशस्त्र गुरिल्ला दस्तों का कामकाज शुरू हो गया था. सशस्त्र संघर्ष के लिए परस्पेक्टिव और कैडरों को तैयार करने में कॉमरेड योगेश ने प्रमुख जिम्मेदारी निभायी.

2004 में माओवादी पार्टी की सथापना हुई. सीसी सदस्य के तौर पर नयी पार्टी की स्थापना में कॉमरेड योगेश का योगदान रहा. उसके बाद वे एसडब्ल्यूआरबी का सदस्य बने थे.

2007 में पार्टी ने एकता कांग्रेस–9वीं कांग्रेस का आयोजन किया. जिसमें उन्होंने सैद्धांतिक व राजनीतिक योगदान दिया. कांग्रेस ने कॉमरेड देवराज को सीसी में चुना था. वे एसडब्ल्यूआरबी का सदस्य बने थे. उस वर्ष की आखिरी में और बाद के वर्ष में रीजनल ब्यूरो के अन्य सदस्यों में से कुछ गिरफ्तार हो गए और कुछ शहीद हो गए. कॉमरेड देवराज ने तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल तीनों राज्यों के उत्तरदायित्व अपनाए. उस कठिन हालात में अडिग रहकर उन्होंने कैडरों को क्रांतिकारी आन्दोलन में मजबूती से बनाए रखने में उनकी मदद की.

2011 में एसडब्ल्यूआरबी ने अपने अधिकांश आत्मगत शक्तियों को ट्राईजंक्शन एरिया जोकि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के सरहदी जंगली क्षेत्र है, में केंद्रित करके काम करने का निर्णय लिया था. देश के इस हिस्से में युद्ध क्षेत्र खोलने के लिए कॉमरेड देवराज सदैव उत्सुक रहते थे. इन तीन राज्यों के विभिन्न इलाकों के बारे में वे निरंतर अध्ययन करते थे. इस तरह ट्राईजंक्शन क्षेत्र में आंदोलन को प्रारंभ करने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया. जल्द ही इस क्षेत्र के परंपरागत आदिवासी जन समुदायों के बीच पार्टी लोकप्रिय हो गई. पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए ने राजनीतिक–सैनिक अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया. गुरिल्ला दस्तों ने जनता में गहरी पैठ जमायी. इन तीनों राज्यों की सरकारें सतर्क हो गयीं. ट्राईजंक्शन का वर्तमान आंदोलन संशोधनवादियों खासकर केरल के संशोधनवादियों के लिए जबर्दस्त आघात है. पार्टी ने वहां सही दिशा दिखाई जिसमें कॉमरेड देवराज का सक्रिय योगदान रहा.

जब एसडब्ल्यूआरबी में नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम (एलटीपी) संचालित किया गया, कॉमरेड देवराज ने उसका दायित्व अपने ऊपर लिया और प्रशिक्षण शिविरों को संचालित किया. उस प्रशिक्षण द्वारा कैडर अच्छी तरह शिक्षित हुए और आंदोलन की विभिन्न समस्याओं के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित कर सके थे. इस तरह कॉमरेड देवराज ने पार्टी कैडरों की राजनीतिक समझदारी बढ़ाने में योगदान दिया.

अन्य क्रांतिकारी कम्युनिस्टों के साथ एकता के लिए कॉमरेड देवराज ने सक्रिय योगदान दिया. सीसी की तरफ से उन्होंने नक्सलबाड़ी ग्रुप के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी ली थी जिसके फलस्वरूप नक्सलबाड़ी ग्रुप का पार्टी में विलय हो गया. इसके पहले उन्होंने जनशक्ति ग्रुप के साथ बातचीत का संचालन किया और कुछ कॉमरेडों को सही दिशा की ओर लाने में सफल हुए.

पार्टी और जन संगठनों की पत्रिकाओं के संचालन के प्रति कॉमरेड देवराज बहुत ध्यान देते थे. बदलते हालात के विश्लेषण से युक्त लेखन के प्रति वे गंभीर रहा करते थे. इस तरह के लेखन के जरिए वे हमेशा संबंधित कमेटियों की मदद करते थे

कॉमरेड देवराज के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात है. वर्तमान जन युद्ध के लिए हथियार व गोला बारूद की आपूर्ती करने में उनकी मुख्य भूमिका थी. ग्रेनेड उत्पादन कार्य के संचालन में भी उनका योगदान रहा.

देश के क्रांतिकारी आंदोलन को एक नया अनुभव देने की क्षमता पश्चिम घाटी में मौजूद है. इसीलिए केंद्र व राज्य सरकारों ने साजिश रच कर कॉमरेड अजिता सहित कॉमरेड देवराज की निर्मम हत्या की.

कॉमरेड देवराज को खोना ट्राईजंक्शन में जनता को संगठित करने के कार्य में लगी पार्टी के लिए बहुत बड़ा

शहरी आंदोलन की आदर्श जन नेत्री कॉमरेड कावेरी को लाल–लाल सलाम!

करीबन तीस वर्षों से क्रांति की सेवा करनेवाली कॉमरेड अजिता (कावेरी) अंबत्तूर की थी. वे दलित परिवार में पैदा हुई थी. उनके पिता परंधामन भारतीय रेल्वे के सेवा निवृत्त अधिकारी थे. 1980 के दशक में जब कॉमरेड कावेरी चेन्नई के सिटी कॉलेज में पढ़ती थीं, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति आकर्षित हो गई. उन्होंने महिला व नागरिक अधिकार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया. पेशे से वे वकील थीं. वे नजर की समस्या से पीड़ित थी. इसके बावजूद क्रांति के लिए उन्होंने अविश्रांत मेहनत की.

उन्होंने तमिलनाडु के शहरी आंदोलन का नेतृत्व किया. पार्टी के आग्रह के अनुसार वे भूमिगत हो गई थीं. बाद में वे पश्चिम घाटी की स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्या बनीं. तमलनाडु की पार्टी में जब राजनीतिक गलत रूझान उत्पन्न हुई थी, वे सही पार्टी दिशा पर अडिग रहीं. उनके जीवन साथी के गलत रूझान के प्रभाव में जाने के बावजूद कॉमरेड कावेरी एक सच्ची कम्युनिस्ट कार्यकर्ता के तौर पर राजनीतिक रूप से अडिग रहीं. अपने आदर्शनीय व्यक्तित्व, प्रतिबद्धता, अथक मेहनत के साथ एक अद्भुत जन नेत्री के तौर पर उभरी कॉमरेड अजिता भारतीय क्रांति में अमिट छाप छोड़ गयी. कॉमरेड अजिता को खोना शहरी आंदोलन के लिए एक बड़ी क्षति है.

कॉमरेड देवराज और अजिता ने पश्चिम घाटी में लाल झंडे को ऊंचा उठाए रखा था. दमन में जितनी भी बढ़ोत्तरी हो जाए, जितने भी नुक्सान हो जाए, क्रांतिकारी आंदोलन आगे बढ़ कर शोषक वर्गों का उन्मूलन अवश्य करेगा, जनता की राज्यसत्ता हासिल करेगा, नव जनवादी राज्य की स्थापना करेगा, समाजवाद फिर साम्यवाद की ओर अग्रसर होगा.

नुक्सान है. केरल की धरती पर 50 वर्ष पहले शहीद होने वाले वर्गेश और उनकी कुरबानी को जनता कभी भूली नहीं. वह उनके आशयों को जारी रखना चाहती थी. इसीलिए जब पार्टी वहां गयी तब वह सक्रिय रूप से आन्दोलन में भाग लेने लगी थी. अब वह कॉमरेड देवराज को कभी नहीं भूलेगी.

कॉमरेड देवराज उत्पीड़ित वर्ग एवं उत्पीड़ित दलित जाति के थे. वे अंग्रेजी, मलयालम, तमिल, कन्नड व तेलुगु और स्थानीय आदीवासी भाषाएं बोलने में कुशल थे. भारत की क्रांति ने एक होनहार नेता खोया है. उन्होंने वैचारिक व सैद्धांतिक रूप से तीखा आंतरिक संघर्ष किया. उस संघर्ष में वे मजबूत हो गए थे. कम आत्मगत शक्तियों और अपेक्षाकृत कम अनुभव के साथ उन्होंने काफी हिम्मत व दृढ़ संकल्प के साथ क्रांतिकारी आन्दोलन का नेतृत्व किया था. सभी के साथ वे मिल जुलकर रहते थे. कैडर और जनता में जनवादी माहौल विकसित कर कॉमरेड देवराज ने उनका विश्वास जीता. इस तरह कॉमरेड देवराज उनके मन में सदा जीवित रहेंगे.

कॉमरेड देवराज एक कलाकार और सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे. 1980 के दशक की आखिरी में वे अखिल भारतीय क्रांतिकारी सांस्कृतिक समिति के कार्यकारिणी सदस्य थे.

वे निस्वार्थ व्यक्तित्व के धनी थे. कमेटी द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता था, उसे वे अपना कार्यभार मान लेते थे. भारत की क्रांति में खासकर पश्चिम घाटी और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं दंडकारण्य में वे चिरस्मरणीय रहेंगे. उनके आदर्श सदा जीवित रहेंगे. उनकी प्रतिबद्धता, कठिन मेहनत, बलिदान जरूर पार्टी को आगे बढ़ायेंगी. लक्ष्य के प्रति कॉमरेड देवराज की अडिग वचनबद्धता वर्तमान नुकसान से उभरने में कैडर की मदद करेगी. प्रवाह के खिलाफ तैरना कैडरों को उनसे सीखना चाहिए.

उनकी कार्यशैली, इरादा, समर्पण की भावना, हिम्मत पार्टी के सभी कैडरों के लिए आदर्श हैं. कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल राज्यों की पार्टी कतारें उनकी महान स्फूर्ति से लैस होकर उनके अधूरे कार्यभार को स्वीकार कर उनके जैसा काम जरूर जारी रखेंगे. उनके द्वारा बनाई राह पर चलकर अच्छे कम्युनिस्ट कार्यकर्ता बनेंगे. यही उस महान शहीद के प्रति सही श्रद्धांजलि होगी.

जनता के लिए अपनी अनमोल जानें न्योछावर करने वाले
रामागूड़ा अमर शहीदों को लालसलाम

एओबी स्पेशल जोन के मलकनगिरी जिले के कटॉफ एरिया के रामागूडा गांव के पास आंध्रप्रदेश ग्रेहाउंड्स और ओडिशा के एसओजी हत्यारे बलों द्वारा 24–27 अक्टूबर, 2016 को किए गए एक पाशविक व क्रूर हमले में 31 कॉमरेड्स शहीद हो गए. जिनमें उत्पीड़ित जनता के लिए अपनी जिंदगियां समर्पित करने वाले भाकपा(माओवादी) के 22 योद्धा हैं, जबकि 9 लोग आम ग्रामीण हैं.

शहीदों के विवरण

एसजेड़सी सदस्य

1. *कॉमरेड बाकूरी वेंकट रमणा 2. कॉमरेड चामला किस्टैया,*

डीवीसी सदस्य

3. कॉमरेड प्रभाकर, 4. कॉमरेड सुवर्णा राजू,

एसी व पीपीसी सदस्य

5. कॉमरेड पृथ्वी, 6. कॉमरेड सिंहाचलम, 7. कॉमरेड दासु,

8. कॉमरेड भारती, 9. कॉमरेड बोट्टु कुन्दना, 10. कॉमरेड केशव राव,

11. कॉमरेड रव्वा नंगाल, 12. कॉमरेड सोड़ी बुदरी,

13. कॉमरेड मंजुला, 14. कॉमरेड सोमलू,15. कॉमरेड गौतम,

पार्टी सदस्य

16. कॉमरेड ज्योती, 17. कॉमरेड रजिता, 18. दासूराम (पीएम)

19. कॉमरेड गंगाल, 20. कॉमरेड लक्की, 21. कॉमरेड नरेश,

22. कॉमरेड पाइके,

साधारण आदिवासी जनता

1. श्यामला 2. कोमलु 3. जोम्मि 4. लक्ष्मण 5. कमला 6. जयराम 7. सिंदे 8. लोयकल 9. लच्चा मोदली

इन सारे वीर शहीदों को दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी और प्रभात भावभीनी श्राद्धांजलि अर्पित करता है.

इन शहीदों में कुछ ने इस हमले का डट कर मुकाबला करते हुए, अन्य कॉमरेडों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त किया. जबकि कुछेक कॉमरेडों को पुलिस गुंडों ने घायल अवस्था में पकड़ कर कई यातनाएं देकर उनकी निर्मम हत्या की. मृत कॉमरेडों की लाशों ने पुलिस के क्रूर व नीच हथकंडों को उजागर किया. निहत्थे ग्रामीणों की जिंदा पकड़ कर हत्या की गई. इस दौरान पुलिस तीन दिन तक आतंक मचाती रही.

भाकपा(माओवादी) के इतिहास में एक ही घटना में 31 कॉमरेडों का शहीद होना अभूतपूर्व है.

दुशमन ने इस इलाके में इतने बड़े हमले को क्यों अंजाम दिया?

साम्राज्यवादियों की सेवा करने वाले भारत के लुटेरे शासक वर्ग हमारे देश के जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को देशी–विदेशी कॉर्पोरेट घरानों के हवाले करने की कोशिश में व्यस्त हैं. लेकिन उनकी कोशिश में इसलिए अड़चन आ रही है क्योंकि देश की जनता खासकर आदिवासी जनता, जो इस धरती की सारी संपत्ति का हकदार है, शोषक–शासक वर्गों के खिलाफ जुझारू संघर्ष कर रही है. भाकपा(माओवादी) इस संघर्ष का कई जगहों में नेतृत्व कर रही है. इसीलिए जनता, खासकर आदिवासी जनता पर और भाकपा(माओवादी) के नेतृत्व में चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन पर लुटेरे शासक वर्गों द्वारा देशव्यापी युद्ध थोपा गया है. आंध्रा–ओडिशा के सीमावर्ती इलाके में अकूत खनिज संसाधन हैं. सिर्फ आंध्रप्रदेश में ही 500 मिलियन टनों का बक्साइट है. यह देश के कुल बाक्साइट डिपाजिटों का पांचवां हिस्सा है. ओडिशा भी संसाधनभरा राज्य है. इस संपत्ति पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नजर पड़ी है. इसे उनके हवाले करने के लिए वहां की राज्य सरकारें भी प्रतिबद्ध हैं. लेकिन भाकपा(माओवादी) के नेतृत्व में गोलबंद वहां की जनता अपने जुझारू आंदोलन के जरिये आंध्रप्रदेश और ओडिशा सरकारों की कोशिशों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है.

इसी तरह कटॉफ एरिया भी एक लड़ाकू इलाका है. यह मलकनगिरी जिले के गुम्मा विकासखंड में है. गुम्मा विकासखंड में नौ पंचायत हैं, जिनमें सात को कटॉफ एरिया कहा जाता है. सीलेरु नदी जो ओडिशा में बहती है, इन सात पंचायत वाले इलाके को पूरे राज्य से अलग करती है. इसीलिए इसे कटॉफ एरिया कहा जाता है. सरकारों की तथाकथित विकास योजनाओं के चलते विस्थापित कई गांवों की जनता इस इलाके में आकर गांव बसा कर रह रही है. लेकिन लोगों की तकलीफें इधर भी

जारी हैं. सीलेरु नदी पर निर्मित बलिमेला जलाशय हर साल सैकड़ों एकड़ की फसलों को डुबोता है. लेकिन जनता की तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है. यह एरिया ओडिशा सरकार द्वारा पूरी तरह उपेक्षित है. यहां की जनता के लिए सरकार का मतलब है सिर्फ वन विभाग और उसकी लूट. इसी परिप्रेक्ष्य में 2009 में भाकपा(माओवादी) ने इस इलाके में कदम रखा, जिसका समस्याओं से जूझ रही जनता ने बढ़–चढ़कर स्वागत किया. जनता जल्द ही गोलबंद होकर सरकार के खिलाफ अपने संघर्ष शुरू किए. इस इलाके के जमींदारों व जन विरोधी आदिवासी मुखियाओं के विरोध में भी आवाज उठाई. इसी क्रम में कटॉफ एरिया एक क्रांतिकारी गढ़ बन गया. और इसीलिए यह सरकार की आंख की किरकिरी बन गया. यह है, कटॉफ एरिया में इतने बड़े हमले के पीछे का परिप्रेक्ष्य.

इस हमले के जरिये सरकार चाहती है कि क्रांतिकारी आंदोलन को बड़ा धक्का पहुचे और कटॉफ एरिया की जनता में आतंक पैदा हो ताकि क्रांति से दूर हो जाए. लेकिन नतीजा इसका उल्टा निकला. इस हमले ने लुटेरी सरकार के खिलाफ जनाक्रोश को और बढ़ाया. इस हमले से सुरक्षित या घायल होकर निकले कॉमरेडों को जनता ने बचाया और उनकी पुरी मदद की.

इस हमले के विरोध में देश भर में आवाज बुलंद हुई. दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन किया गया. शहीदों के अंतिम संस्कारों में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे. कई जगहों में शहीदों की स्मारक सभाएं आयोजित की गई. देश के कई नागरिक अधिकार व मानवाधिकार संगठनों, कई विश्वविद्यालयों के छात्र–छात्राओं, बुद्धिजीवियों ने घटना का जायजा लेने इस इलाके का दौरा किया. कई जांच रिपोर्ट व लेख प्रकाश्ति किए गए. उनके जरिए सिर्फ सरकार के अपराध को ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन द्वारा उस इलाके की जनता में बढ़ रही चेतना को भी उजागर किया. इन संगठनों के सामने जनता ने सरकार के आतंक के विरोध में अपना आक्रोश जताया. टीवी चैनलों में कई चर्चाएं चलाई गई.

एक ही घटना में इतनी बड़ी तादाद में, वह भी कई माइनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कॉमरेडों को खोना एओबी आंदोलन के लिए अपूरणीय क्षति है. लेकिन इन शहीदों की कुरबानियां इनके द्वारा स्थापित आदर्श जनता को हमेशा क्रांति के लिए प्रेरित करते रहेंगे. उस प्रेरणा से नई ताकतें उभर कर आएंगी और क्रांति को विजय की तरफ आगे ले जाएंगी.

आईये, इन शहीदों की जीवनियां जानेंगे.

शहीदों की बलिदानी विरासत को ऊंचा उठाएंगे! बोल्शेविक स्फूर्ति के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे!

कॉमरेड बाकूरी वेंकट रमणा राजु

आंध्रप्रदेश राज्य, विशाखपट्णम जिला, हुकुमपेटा मंडल, बाकूरु गांव के एक मध्यम वर्गीय आदिवासी परिवार में करीब 45 वर्ष पहले कॉ बाकूरी वेंकटरमणा राजू (गणेश, प्रसाद)का जन्म हुआ. उनकी एक बड़ी बहन और दो छोटे भाई हैं.

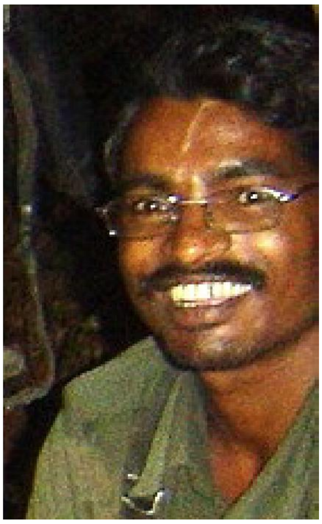

'मन्यम पितूरी' के नाम पर लोकप्रिय महान विद्रोह, उस इलाके में 1922–24 में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था. जिसकी छाप जनता के हृदयों में आज भी अमिट है. उस विद्रोह की विरासत को आगे ले जाते हुए फिर वहां सीपीआई (माओवादी) के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है. उस इलाके के कई युवा क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए थे, जिनमें कॉमरेड बाकूरी वेंकट रमणा राजू एक हैं.

जब वे कॉलेज में पढ़ रहे थे, रॉडिकल छात्र संगठन में शामिल होकर छात्र आंदोलन के कार्यकर्ता बने. स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के बाद 'आदिवासी अधिकार रक्षा संगठन' में जो क्रांतिकारी आंदोलन के नेतृत्व में काम करता था, में सक्रिय भागीदार रहे. 1992 में पूर्व की सीपीआई (एम–एल) (पीपुल्सवार) और उसके संबद्ध संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया था. उस दौरान 'आदिवासी अधिकार रक्षा संगठन' पर भी प्रतिबंध लगाया गया. इसके बाद वह संगठन निष्क्रिय हो गया. बाद में कर्मचारियों और छात्रों के बीच में काम करने एक सेल का गठन हुआ था, जिसके तीन सदस्यों में कॉ प्रसाद एक थे. उस दौरान कर्मचारियों और छात्रों को संगठित करने में कॉ प्रसाद का योगदान महत्वपूर्ण रहा. स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने चंद वक्त के लिए पत्रकार की नौकरी की.

1996 में कॉ. प्रसाद पूर्णकालीन कार्यकर्ता के तौर पर गुरिल्ला दस्ते में भर्ती हो गए थे. पहले उन्होंने अरकु दस्ते जो पूर्व गोदावरी डिविजन का हिस्सा रहा, में काम किया. उसी दस्ते में काम करते हुए 1999 में वे एसी सदस्य बने थे. उसके बाद उनके क्रियाकलाप कोरुकोंडा एरिया में जारी रहे. वहीं काम करते हुए उन्होंने एसी सचिव की जिम्मेदारी उठाई. 2001 में पूर्व गोदावरी के डिविजनल कमेटी सदस्य बने. कुछ वक्त के बाद डिविजनल कमेटी के सचिवालय के सदस्य बने. कोरुकोंडा एरिया में काम करते हुए उन्होंने वहां की समस्याओं के हल के लिए जनता को

गोलबंद किया. कई जुझारू आंदोलनों का नेतृत्व किया.

2006 में आयोजित एओबी के दूसरे अधिवेशन में उन्हें एसजेडसी में लिया गया. इस अधिवेशन में अपनाई गई कार्यनीति के तहत पूर्व गोदावरी डिविजन से आधे भाग को अलग करके विशाखा डिविजन बनाया गया, जिसके सचिव की जिम्मेदारी कॉ. प्रसाद ने उठायी. 2008 में पूर्व गोदावरी डिविजन के सचिव घायल होने की वजह से दोनों डिविजनों की जिम्मेदारी प्रसाद ने निभाई. इस तरह कॉ. प्रसाद की क्रांतिकारी जिंदगी पूर्व गोदावरी डिविजन से जुड़ गयी. लंबे समय तक वहां काम करते हुए वे जनता में अत्यंत लोकप्रिय हो गए. उस डिविजन में संगठन को मजबूत करते हुए उन्होंने कई लड़ाकू आंदोलनों का नेतृत्व किया. उस इलाके में निक्षिप्त बाक्साइट के खनन के लिए सरकार की कोशिशें जोरों पर जारी हैं. इसके खिलाफ कॉ. प्रसाद के नेतृत्व में जुझारू आंदोलन चलाया गया. इस आंदोलन को कुचलने सरकार द्वारा तीव्र दमन चलाया जा रहा है. इसके बावजूद आंदोलन पीछे नहीं हटा. उनके नेतृत्व में संचालित महत्वपूर्ण संघर्षों में कॉफी आंदोलन भी शामिल था, जिसके चलते सैकड़ों एकड़ की सरकारी कॉफी बगीचे जनता के कब्जे में आ गई. आंदोलनों के जरिए हासिल इन विजयों के चलते तीव्र दमन के बावजूद जनता क्रांतिकारी आंदोलन में डटी रही. 2013 तक उन्होंने पूर्व व विशाखा की संयुक्त डिविजनल कमेटी का नेतृत्व किया.

2013 में आयोजित एओबी एसजेडसी प्लीनम के बाद उन्हें जन संगठनों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई. चूंकि वे सैनिक क्षेत्र में भी सक्षम थे, इसलिए जोन मिलिटरी कमिशन के सदस्य भी रहे. कई सैनिक कार्यवाहियों में उनकी भागीदारी थी. तीव्र दमन में उन्होंने दुश्मन के कई हमलों का डट कर मुकाबला किया. एसजेडसी द्वारा उन्हें सांस्कृतिक क्षेत्र की जिम्मेदारी भी दी गई. उनके नेतृत्व में एक सास्कृतिक कार्यशाला भी आयोजित की गई. उन्होंने संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व भी किया.

कॉ. प्रसाद एक लेखक भी थे. बाक्सइट संघर्ष एवं क्रांतिकारी इलाके में जारी सरकारी दमन को उजागर करते हुए उन्होंने कई लेख लिखे, जो बाहरी पत्रिकाओं में छपे थे. एओबी जोन की पत्रिका बोल्शेविक के लिए भी उन्होंने कई रचनाएं की.

इस तरह कॉ. प्रसाद ने क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरतों के मुताबिक कई जिम्मेदारियां निभाई.

साथी कॉमरेडों को प्यार, स्नेह, आत्मीयता बांटने में कॉमरेड प्रसाद आदर्शवान थे.

कॉमरेड प्रसाद शादीशुदा थे. उनकी पत्नी भी क्रांतिकारी आंदोलन में थी. लेकिन कुछ वर्ष पहले वह गिरफ्तार होकर जेल गई थी. जेल से रिहा होने के बाद घर में ही रही.

एक आदिवासी प्ररिप्रेक्ष्य से, प्राथमिक स्तर से उभरकर आंदोलन के राणनीतिक नेतृत्व के स्तर तक विकसित होने वाले कॉ. प्रसाद को खोना एओबी आंदोलन के लिए अपूरणीय क्षति है. लेकिन मन्यम इलाके का क्रांतिकारी आंदोलन इस क्षति से उभरकर अवश्य आगे बढ़ेगा.

कॉमरेड वेंकट रमणा अमर रहे!

कॉमरेड चामला किष्टैया

कॉमरेड चामला किष्टैया (दया, भास्कर, पूर्णो, रामु) तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले के वलिगोंडा मंडल के दासिरेड्डिगूडेम गांव के एक गरीब परिवार में करीबन 45 वर्ष पहले पैदा हुऐ थे. उनके मां–बाप चंद्रम्मा और रामैया थे.

जब वे स्नातक पढ़ाई कर रहे थे, तभी रैडिकल छात्र संगठन (आरएसयू) के क्रियाकलापों के प्रति आकर्षित हो गये थे. उनका गांव क्रांतिकारी आंदोलन के इलाके के दायरे में है. इसलिए वे पार्टी गतिविधियों से प्रभावित होकर 1990 में पेशेवर क्रांतिकारी बन गए. नलगोंडा जिले के राचकोंडा और कृष्णपटि्ट दस्तों में लगभग चार साल तक उन्होंने काम किया. बाद में कुछ समय तक नल्लमला में उन्होंने काम किया. 1994 में उनका तबादला श्रीकाकुलम डिविजन में हुआ था, जहां उनका नाम भास्कर था. चंद महीने बाद उन्होंने उसी डिविजन के उद्दानम दस्ते के डिप्युटी कमांडर बने थे. 1996 में उन्हें उसी दस्ते के कमांडर की जिम्मेदारी दी गई थी.

उद्दानम इलाका नारियल और काजू के लिए प्रख्यात है. जोतने वालों को जमीन के नारे को ऊंचा उठाते हुए वहां की जनता को गोलबंद करके कई जमीन कब्जा संघर्षों का उन्होंने नेतृत्व किया. उसके नतीजे में पंजाब सिंह नाम के एक जमींदार के सौ एकड़ के नारियल बाग़ जनता के कब्जे में आ गया. कई गांवो के हजारों एकड़ की सरकारी काजू बगीचे पर जनता का अधिकार कायम हुआ.

काजू व नारियल जैसे कृषि उत्पादों, इमली और अन्य वनोपजों के समर्थन मूल्य बढ़ाने और उन्हें व्यापारियों द्वारा नहीं बल्कि सरकार द्वारा खरीदे जाने, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए गोदामों का निर्माण करने की मांगों को लेकर कॉमरेड भास्कर के नेतृत्व में कई सफल संघर्षों का आयोजन किया गया था.

1998 में कोपरडंग जंगलों में जब डिविजनल प्लीनल संचालित हो रहा था, तभी पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर एक बड़ा हमला किया था जिसमें 13 कॉमरेड्स शहीद हो गए. इस नुकसान ने श्रीकाकुलम आंदोलन को बुरी तरह प्रभावित किया. इस पृष्ठभूमि में कॉमरेड भास्कर का तबादला नागावली एरिया में किया गया, जहां उन्होंने दया के नाम पर काम किया था. नागावली एरिया में उनके नेतृत्व में गोट्टा, मुकुंदापुरम, पांड्रतला जैसे गांवों में भूकि कब्जा संघर्ष किए गए. विश्वा नामक एक जमींदार के खिलाफ संघर्ष कर 600 एकड़ जमीन जनता के बीच बांटा गया.

निरंतर वर्ग संघर्ष में क्रांति की जरूरतों के अनुरूप सांगठनिक, राजनीतिक, सैनिक व सैद्धांतिक रूप से विकसित होते हुए सन् 2000 में कॉमरेड दया डिविजन कमेटी सदस्य बने. बाद में डिविजन कमेटी के सचिव की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने कंधों पर उठायी. 2006 में संपन्न एओबी अधिवेशन में कॉमरेड दया एसजेडसी सदस्य के रूप में चुने गए. एसजेडसीएम की हैसियत से उन्होंने श्रीकाकुलम डिविजन सचिव की जिम्मेदारी भी निभायी.

1995 से 2003 तक सत्तारूढ़ तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबु के शासनकाल में आंध्रप्रदेश में दमन तीव्र रूप में था. अमेरिका साम्राज्यवादियों के नेतृत्व में और सांठ–गांठ से दमन चलाया गया. क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने न सिर्फ पुलिस बल का सहारा लिया बल्कि झूठे सुधार कार्यक्रमों पर भी जोर दिया. इस दमन को हराने सही समय में सही कार्यनीति न अपनाने के चलते आंध्रप्रदेश का आंदोलन धीरे–धीरे भाटा की स्थिति में चला गया. उस कठिन परिस्थिति में कॉमरेड दया ने श्रीकाकुलम आंदोलन का नेतृत्व किया. जनाधार को बनाए रखने के लिए उनके नेतृत्व में कई प्रयास किए गए.

बाद में क्रांतिकारी आंदोलन को बचाने के लिए अपनाई गई कार्यनीती के तहत श्रीकाकुलम डिविजन की आत्मगत शक्तियों को ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले में रिट्रीट किया गया था. इस परिप्रेक्ष में श्रीकाकुलम–कोरापुट संयुक्त डिविजनल कमेटी गठित हुई. इसके सचिव की जिम्मेदारी कॉमरेड दया ने संभाली. कोरापुट डिविजन में वे पूर्णो के नाम से लोकप्रिय हो गए. इसी वक्त कोरापुट जिले में ऐतिहासिक नारयणपट्णा जमीन आंदोलन का उभार आया, जिसमें कॉमरेड दया का योगदान महत्वपूर्ण रहा. नारायणपट्णा में जनता पर सोंडी जाति के जमींदारों के शोषण बड़े पैमाने पर हुआ करता था. उन्होंने दारू बनाकर आदिवासी लोगों को खूब पिलाकर, उन्हें नशे में डुबोकर उनकी जमीनें हड़प ली. आदिवासियों को खाना–कपड़ा–मकान से वंचित कर लिया. सोंडी जमींदारों के खिलाफ मोर्चा खोलने के मकसद से वहां शराबबंदी आंदोलन छेड़ा गया, जो बाद में एतिहासिक जमीन आंदोलन का रूप ले लिया. जमींदारों के कब्जे में रही सैकड़ों एकड़ जमीन पर जनता का अधिकार पुनरस्थपित हुआ.

गेरिल्ला जोन के बाहरी इलाके में भी विस्थापन की समस्या को लेकर उन्होंने माली, देवमाली जैसे कई आंदोलनों का नेतृत्व किया.

जन संगठनों और मिलिशिया में, जमीन कब्जा आंदोलन, शराबबंदी आंदोलन, फसल व वनोपजों के समर्थन मूल्य बढ़ाने के आंदोलनों में किसानों, मजदूरों और महिलाओं को बड़े पैमाने पर गोलबंद करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी.

सैनिक मार्चे पर भी कॉमरेड दया का योगदान महत्वपूर्ण रहा. 1994 में श्रीकाकुलम जिले के नीलाभद्रा गांव के गन्ना एरैया नाम के एक बड़े जमींदार की सुरक्षा के लिए तैनात पांच पुलिस जवानों पर हमला करके दो लोगों को खतम करके, तीन लोगों को घायल करके पांच .303 रायफल और 200 कारतूस जब्त किए गए.

उद्दानम इलाके के पलासा शहर में काशीबुग्गा कस्बे में रहने वाले एसआईबी जवान एमएन दास मुखबीर नेटवर्क बनाने में और जनता पर दमन चलाने में आक्रामक था. उसे काशीबुग्गा में बीच सड़क पर जनता की आंखों के सामने ही खतम किया गया. 1998 में बुडिगड्डा और बोडिपडा पुलिस थानों के ऊपर एक ही बार हमले किए गए. उपरोक्त सभी कार्रवाइयों में कॉमरेड दया का योगदान महत्वपूर्ण रहा. 2005 में नागावली एरिया में कूंबिंग करके वापस जा रहे पुलिस बलों पर कॉमरेड दया के नेतृत्व में आपर्चुनिटी एंबुश की गई, जिसमें एक आरक्षक मारा गया. 2009 में किए गए नाल्को हमले में कॉमरेड दया की भूमिका महत्वपूर्ण रही. 2004 में किए गए कोरापुट हमले में हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन परोक्ष रूप से उनकी भूमिका थी.

रामागुडा की अपनी आखिरी लड़ाई में जब दुश्मन गुरिल्ला कैंप को घेर रहा था, इसका अंदाजा लगने के तुरंत बाद कॉमरेड दया, जो उस कैंप के कमांडर की जिम्मेदारी निभा रहे थे, ने प्रतिरोध शुरू किया. दुश्मन के घेराव को तोड़ने के प्रयास में उन्होंने अपनी जान कुरबान की.

कॉमरेड दया की जीवन संगिनी कॉमरेड स्वर्णा 2009 में हुई एक मुठभेड़ में शहीद हुई. इस दर्द को उन्होंने चेतनापूर्वक सहन किया.

कॉमरेड दया का क्रांतिकारी जीवन श्रीकाकुलम और कोरापुट आंदोलनों के साथ गुंथा हुआ था. शहादत के चंद दिनों के पहले उन्होंने नए इलाके की जिम्मेदारी स्वीकार की थी.

हमेशा मुस्कराने वाले कॉमरेड दया ने अपने प्रेमिल,

सरल व मिलनसार स्वाभाव के साथ जनता, पार्टी व पीएलजीए कतारों के हृदयों में अमिट छाप छोड़ा था.

क्रांतिकारी आंदोलन के आज की कठिन परिस्थिति में कॉमरेड दया को खोना एओबी आंदोलन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. इस नुकसान से क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने की शपथ लेंगे. यही वीर शहीदों को देने वाली सही श्रद्धांजलि होगी.

कॉमरेड दया अमर रहे!

कॉमरेड प्रभाकर

करीबन 45 वर्ष पहले कॉमरेड प्रभाकर (अरविंद, गंगाधर, गंगाल, हरि) का जन्म हैदराबाद के याप्राल कस्बे के एक दलित परिवार में हुआ था.

उन्होंने सिविल इंजनियरिंग करके कुछ समय तक नौकरी भी की थी. सामाजिक चेतना से लैस कॉमरेड प्रभाकर स्वाभाविक रूप से ही क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति आकर्षित हुए थे. वे एक कलाकार थे. सामाजिक बदलाव के लिए हो रहे आंदोलन में वे कला को माध्यम बना लिया. सामंती व साम्राज्यवादी संस्कृति से जनता व जन संस्कृति को बचाने और नव जनवादी संस्कृति का निर्माण करने के लक्ष्य से बने 'प्रजा कला मंडली' नाम के सांस्कृतिक संगठन में वे सक्रिय रूप से काम करते हुए उसके राज्य स्तर के नेता बने थे. लगभग 20 वर्ष तक उन्होंने उस संगठन में अपना योगदान दिया. वे गायक थे. ढोलकिया थे. नाटक व नृत्य कलाकार थे. वे शिक्षक भी थे. कई जन संगठनों के कार्यकर्ताओं को उन्होंने सांस्कृतिक प्रशिक्षण भी दिया था. वे एक लेखक भी थे. उन्होंने कई गाने व नाटक के आलावा कई लेख लिखे थे. उन्होंने न सिर्फ सांस्कृतिक लड़ाई लड़ी थी, बल्कि जनता की कई मूलभूत समस्याओं को लेकर अन्य जन संगठनों से कंधे से कंधा मिलाकर जन आंदोलनों में आगे रहे थे. कई जनवादी संगठनों व महिला संगठनों के साथ उन्होंने स्नेह संबंध बना लिया. इस तरह तत्कालीन आंध्रप्रदेश में एक राज्य स्तर के जन नेता के तौर पर वे उभरे थे.

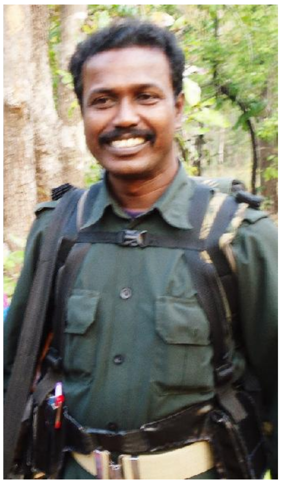

पृथक तेलंगाना आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा. सिर्फ पृथक तेलंगाना नहीं वे जनवादी तेलंगाना के पक्षधर थे.

वे शादी–शुदा थे. 'चैतन्या महिला संगम' नामक महिला संगठन की नेत्री कॉमरेड देवेंद्रा से उन्होंने प्रेम विवाह किया. दोनों ने भी क्रांतिकारी जन आंदोलनों में कंधे से कंधा मिलाकर सक्रिय रूप से काम किया था. बाद में कॉमरेड प्रभाकर अपने कार्याचरण का विस्तार करते हुए 2014 में गुरिल्ला जीवन को अपना लिया था. एओबी में डिविजनल कमेटी स्तर की हैसियत से उन्होंने अपना योगदान दिया. लूटेरी सरकार के विकास नमूने को चुनौती देते हुए वैकल्पिक विकास नमूने का निर्माण करने में वे भागीदार रहे. आदिवासियों की सिंचाई के लिए अपनी इंजनियरिंग पढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने चेक डैम आदि निर्माणों का नेतृत्व किया. उन्होंने कई क्रांतिकारी जन संगठनों का मार्गदर्शन किया.

महानगर में पलने–बढ़ने व उच्च शिक्षा हासिल करने के बावजूद कॉमरेड प्रभाकर अनपढ़ आदिवासी जनता व कॉमरेडों के साथ मिल–जुल कर काम करते थे. जनता को उन्होंने अपना शिक्षक मानकर उनके साथ व्यवहार किया.

रामागूडा हमले के दौरान पुलिस ने घायल अवस्था में अपने हाथ लगे कॉमरेड प्रभाकर को कई यातनाएं देकर उनकी हत्या की.

कई किस्म के सामर्थ्यों व सांगठनिक क्षमता के धनी कॉमरेड प्रभाकर को खोना क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है.

कॉमरेड प्रभाकर अमर रहे!

कॉमरेड कोंडामंचिली सुवर्ण राजु

कॉमरेड सुवर्ण राजु (किरण, रमेश) आंध्रप्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में करीब 30 साल पहले एक दलित परिवार में पैदा हुआ था. इसी मुठभेड में शहीद होने वाले कॉमरेड दासु किरण के न सिर्फ मामा थे बल्कि उनकी बड़ी बहन के पति भी थे. कॉमरेड किरण के बचपन में ही उसकी बहन और उनके पति दोनों ही क्रांतिकारी आंदोलन के साथ जुड़ गए थे. जब किरण किशोर अवस्था में था, अपनी बहन को देखने श्रीकाकुलम डिविजन में गया था. वहां की जनता और आंदोलन को देख कर उत्तेजित होने वाला किरण वहीं पर रुक गया. उस वक्त उम्र कम होने की वजह से उसे दस्ते में भर्ती नहीं किया गया था. क्रांतिकारी जरूरतों के मुताबिक छोटे–छोटे काम करते हुए एक बार वह पुलिस के हाथ लग गया. चूंकि उसके पास चिट्ठी मिली थी, इसलिए उसे खूब यातनाएं दी गई. लेकिन पुलिस उससे दस्ते की कोई सूचना उगलवा नहीं सकी. लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ टाडा के तहत

मामला दर्ज किया गया था. आंध्रप्रदेश राज्य में शायद किसी नाबालिग पर पहली बार टाडा के तहत केस दायर किया गया था. इससे राज्य में हडकंप मच गया था. दो साल के बाद कॉमरेड किरण जेल से रिहा होकर क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुआ.

पहले उसे गार्ड की जिम्मेदारी दी गई. अनुशासन के साथ उसने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सैनिक, राजनीतिक व सांगठनिक रूप से विकसित होने के लिए खूब मेहनत की. अध्ययन में वह बहुत दिलचस्पी रखता था.

2006 में विजयनगरम जिले में एसजेडसी कॉमरेड पर फायरिंग की घटना में किरण ने पहलकदमी दिखा कर दुश्मन पर फायरिंग किया जिससे न सिर्फ दुश्मन पीछे हटा बल्कि अन्य कॉमरेडों को रिट्रीट होने का मौका भी मिल गया था.

गार्ड की जिम्मेदारी पूरी होने के बाद वह प्रधान बल में शामिल हुआ. आंध्रा–ओडिशा राज्यों में पीएलजीए द्वारा की गई कई कार्रवाइयों में शामिल हुआ था. इस क्रम में उसे सीआरसी कंपनी–3 के कमांडर की जिम्मेदारी दी गई. इस जिम्मेदारी को निभाते हुए उसने कई प्रतिरोध कार्रवाइयों में सक्रिय भूमिका निभाई. शहादत के वक्त वह डिविजन कमेटी सदस्य की हैसियत से सांगठनिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा था.

कॉमरेड किरण की शादी 2010 में एक साथी कॉमरेड के साथ हुई.

एक नव जवान डीवीसीएम को खोना एओबी आंदोलन के लिए बड़ा नुकसान है.

कॉमरेड किरण अमर रहे!

कॉमरेड पृथ्वी

कॉमरेड पृथ्वी (मुन्ना) कॉमरेड्स शिरीषा–अक्किराजु हरगोपाल का इकलौता बेटा था. करीब 25 वर्ष पहले उसका जन्म हुआ था. आंध्रप्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले के आलकूरुपाडु उनकी ननिहाल है. अपने बाप के भूमिगत जिंदगी में होने की वजह से अकेली मां के संरक्षण में ही पृथ्वी पला–बढ़ा. उसने इंटरमीडियेट (12वीं) तक की पढ़ाई की. पिताजी कहां रहते हैं? क्या करते हैं? हमेशा उसके साथ क्यों नहीं रहते हैं, जैसे अन्य बच्चों के बाप की तरह. .. पृथ्वी को इन सवालों ने पूरे बचपन में सताए रखा. इनका समाधान उसके बड़े होने के बाद ही मिला. लेकिन उन सवालों ने कुछ और सवालों को पैदा किया. हालांकि अब ये सवाल व्यक्ति संबंधित न होकर सामाजिक थे. पृथ्वी ने इस विश्वास के साथ कि इन सवालों के समाधान उसी मार्ग में मिलेंगे, जिस पर उसके बाप चल रहे हैं, उसी मार्ग पर कदम रखा. मां का प्यार उसे नहीं रोक सका.

2008 में अपने यौवन की शुरुआत में जब उसने दंडकारण्य में कदम रखा था, तभी उसका क्रांतिकारी प्रस्थान प्रारंभ हो गया. पृथ्वी मुन्ना बन गया. दंडकारण्य में सलवा जुडुम के बीभत्स और उसके खिलाफ जनता द्वारा किए गए प्रतिरोध के बारे में उसने कई गाथाएं सुनी थी. जनता द्वारा निर्मित हो रहे इतिहास ने उसे और प्रेरणा दी.

कॉमरेड मुन्ना की प्रतिभा, होशियारी, तकनीकी ज्ञान, दिलचस्पी को ध्यान में रख कर उसे सैनिक खुफिया विभाग में नियुक्त किया गया. एक वर्ष काम करने के बाद क्रांतिकारी जरूरतों के अनुरूप उसका तबादला एओबी में हुआ था.

2009 में एओबी के कोरापुट–श्रीकाकुलम डिविजन के नारायणपट्णा में एक्शन टीम (सैनिक कार्रवाई दस्ता) में काम करते हुए सीआरसी तीसरी कंपनी का सदस्य बना. कुछ समय के लिए जन मिलिशिया कमांडर की जिम्मेदारी निभाई. कम समय में ही उसने वहां की कुवी और ओडिया भाषाएं सीख ली. सामूहिक अध्ययन के संचालन, पार्टी की राजनीतिक बोधन एवं मिलिटरी प्रशिक्षण देने में उसने निपुणता हासिल की. मिलिशिया सदस्यों के बीच मुन्ना द्वारा किए गए राजनीतिक प्रयास के चलते दस से ज्यादा मिलिशिया सदस्य पेशेवर क्रांतिकारी बन गए थे.

राजनीतिक चेतना, अनुशासन व सामर्थ्य के आधार पर कामरेड मुन्ना को 2013 में पीपीसी में लिया गया. पीपीसी सदस्य की हैसियत से सैनिक खुफिया विभाग की जिम्मेदारी निभाते हुए वह कई सैनिक कर्यवाहियों में भाग लिया. कुछ कार्रवाइयों का उसने नेतृत्व किया. 2014 जून में माचखंड में कामरेड मुन्ना के नेतृत्व में किए गए हमले में पुलिस का एक असिस्टेंट कमांडेंट मारा गया और एक घायल हो गया.

2014 में उसका तबादला एमकेबी डिविजन के कटॉफ एरिया के एलजीएस में हुआ था. उस में काम करते हुए एक आर्गनाइजर की भूमिका भी उसने निभायी और जनता में अमिट छाप छोड़ा. ओडिया भाषा में दिए गए अपने भाषणों के जरिए वह जनता में लोकप्रिय हो गया.

शहर में पढ़ने के बावजूद कामरेड मुन्ना आदिवासी कॉमरेडों के साथ घुल–मिलकर रहता था. एक अग्रणी नेता के बेटे के रूप में उसने किसी भी तरह की विशेषता या इमेज को नहीं चाहा था. उसके स्तर के सभी कॉमरेडों की ही तरह उसने किचेन, संतरी आदि सभी कार्य किया और बोझा ढोया. गैर सर्वहारा रूझान के साथ लड़ते हुए स्वयं को एक सर्वहारा वर्ग के उत्तम बेटे के रूप में स्वयं को

तब्दील किया.

दुश्मन द्वारा किए गए रामागूडा हमले में अपने पिताजी सहित, अन्य नेतृत्वकारी कॉमरेडों को बचाने के लिए अत्यंत साहस व हिम्मत के साथ लड़ते हुए कॉमरेड मुन्ना ने अपनी जान कुरबान की.

प्रतियोगिता परीक्षाएं, स्नातक–स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्रियां, रैंक, कॅरियर, सॉफ्वेयर नौकरियां, विदेशों में कॅरियर के मौकें,.... कुल मिलाकर व्यक्ति हितों को ही सर्वोच्च स्थान देते हुए आशाओं की पालकी में सैर करने वाली आज की पीढ़ी के अत्यधिक युवाओं से भिन्न समाज व सामूहिक हित व शक्ति के प्रतीक बने विवेक, श्रुति, सागर, सूर्यम, आजाद और अब मुन्ना भोर का तारा बनकर पूरब की ओर प्रस्थान कर गए हैं.

कॉमरेड मुन्ना अमर रहे!

कॉमरेड सिंहाचलम

आंध्रप्रदेश के विजयनगरम जिले के बोब्बिलि मंडल के चिन्ना नंदवला गांव में गरीब किसान परिवार में करीबन 55 वर्ष पहले कॉमरेड एनमलापल्लि सिंहाचलम (रंजिम, मुरली, हरि) का जन्म हुआ था. उन्होंने 5वीं तक पढ़ाई की थी. जब अपने बचपन में ही उनकी मां का देहांत हुआ था, तब से वे पढ़ाई छोड़ कर घर का बोझ उठाने मजबूर हो गए थे. अपनी 18 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई थी. उनके तीन बच्चे – एक बेटी एवं दो बेटे हैं.

आंदोलनरत इलाका होने की वजह कॉमरेड सिंहाचलम क्रांति के प्रति आकर्षित हुए थे. पहले वे सीपीआई (एम–एल)(पार्टी यूनिटी) में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे. शहीद कॉमरेड गंटि प्रसादम के नेतृत्व में वे कई आंदोलनों में भाग लिये थे. चूंकि संस्कृतिक क्षेत्र में उनकी दिलचस्पी थी इसलिए जन नट्य मंडली (जेएनएम) में उन्होंने काम किया. जेएनएम में काम करते हुए देश भर में वे कई कर्यक्रमों में शामिल हुए थे.

सीपीआई (एम–एल)(पार्टी यूनिटी) और सीपीआई (एम–एल)(पीपुल्सवार) का विलय होने के बाद कॉमरेड सिंहाचलम ने पूर्व घाटी में कदम रखा था. कॉमरेड मुरली के नाम पर वहां की जनता में लोकप्रिय हुए थे. वे अपने बेटे को भी क्रांति में लाए थे. बाप और बेटा दोनों ने साथ में जेएनएम में काम किया. लेकिन कुछ दिन के बाद उनका बेटा पार्टी छोड़ कर चला गया था. इससे कॉमरेड मुरली जरूर नाराज तो हुए थे लेकिन उनके क्रांतिकारी संकल्प पर उसका कोई असर नहीं पड़ा.

कुछ अरसे के बाद उनका तबादला कृषि विभाग में हुआ था. पूर्व गोदावरी डिविजन की जनता को कई किस्म की नई फसलों से परिचय कराने, तालाब और चेक डैम आदि का निर्माण कराने, जमीन समतलीकरण कराने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा.

जब नारायणपट्ना का आंदोलन उभरा कॉमरेड मुरली का तबादला उस इलाके में हुआ था. वहां हरि के नाम पर वे जनता में लोकप्रिय हो गए. वहां भी उन्होंने कृषि विभाग में ही अपना योगदान दिया. वहां क्रांतिकारी कृषि सुधार कार्यक्रमों के अमल में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण रही. उसी तरह उन्होंने ताता के नाम से नंदापुर और रवि के नाम से कटाफ इलाकों में भी अपना योगदान दिया.

नारायणपट्ण में काम करते समय वहां की कामरेड के साथ उन्होंने पुनरविवाह किया.

कॉमरेड सिंहाचलम एक निस्वार्थ, प्रेमिल स्वभाव एवं सेवाभाव वाले कॉमरेड थे. उन्होंने जहां भी काम किया वहां अपने प्रेम व सेवा भावना से जनता के हृदयों में जगह बना ली. चूंकि आयुर्वेद चिकित्सा में उन्हें प्रवेश था इसलिए एक आयुर्वेद वैद्य के तौर पर भी वे जनता की सेवा की.

कुछ सैनिक कार्यवाहियों में भी उनकी भागीदारी थी.

उम्रदराज होने की वजह से उनके कामकाज में सीमितता आयी. लेकिन क्रांति के प्रति अटूट विश्वास के साथ वे आखरी दम तक जनता की सेवा करते रहे.

रामागूडा हमले में वे निहत्थे थे. घायल अवस्था में वे पुलिस के हाथ लग गए थे. हत्यारी पुलिस ने कई तरह की यातनाएं देकर उनकी हत्या की थी.

कॉमरेड सिंहाचलम अमर रहे!

कॉमरेड दासु

पश्चिम गोदावरी जिले के पल्लंटला गांव में एक गरीब दलित परिवार में पैदा होने वाले कॉमरेड दासु (मधु) न सिर्फ गरीबी बल्कि भेदभाव को भी झेला था. इसलिए जब उनके गांव में दलित युवा संगठन बना था, कॉमरेड मधु उसमें शामिल हो गए. कम्मा जाति के जमींदारों का सामना करने के लिए युवाओं को कर्रासामु सिखाने वाले शिक्षक बने थे. एक ही हाथ से कुदाल को लकड़ी जैसे घुमाते हुए उन्होंने स्थानीय दुश्मनों में डर पैदा किया. इस तरह अन्याय के खिलाफ विद्रोह करने वाले मधु को स्थानीय

जमींदारों ने कई बार गिरफ्तार करवाया, यातनाएं दिलवायी, उन्हें हमेशा परेशान करते थे. इसी क्रम में क्रांतिकारी आंदोलन के साथ उनकी भेंट हुई थी. कुछ वक्त के बाद उन्होंने अपनी क्रांतिकारी चेतना बढ़ा कर क्रांति के लिए अपने पूरे जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया. अपने मन की बात जब उन्होंने अपनी पत्नी को सुनाई, तब उनकी पत्नी भी पति के साथ आंदोलन में शामिल होने तैयार हो गई. इस प्रकार पति–पत्नी अपने दोनों बच्चों को परिजनों को सौंपकर भूमिगत हो गए थे. श्रीकाकुलम डिविजन में पहले उन दोनों ने काम किया. लेकिन बच्चों को छोड़ कर नहीं रह पाने की स्थिति में उनकी पत्नी ने आंदोलन छोड़ा था. इसके बावजूद कॉमरेड मधु क्रांति में डटे रहे.

बड़ी उम्र में गुरिल्ला जिंदगी में प्रवेश करने के बावजूद युवाओं के साथ मिलकर उन्होंने सब कुछ सीख लिया. गरीब व दलित होने की वजह से बचपन में वे पढ़ाई से वंचित थे. गुरिल्ला बनने के बाद ही वे छात्र बन कर पढ़ाई सीख ली. शहीद कॉमरेड मस्तान राव के गर्ड की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई. करीबन 20 वर्ष की उनकी क्रांतिकारी जिंदगी का ज्यादा समय तकनीकी क्षेत्र में गुजरा. ग्रेनेड्स व हथियार बनाने में उन्होंने निपुणता हासिल की थी. उनके कान की समस्या थी. इसलिए इयर मशीन के बिना वे नहीं सुन पाते थे. बढ़ते दमन के चलते बीवी व बच्चों से समय–समय पर मिलने में आने वाली दिक्कतों को उन्होंने सटीक समझ लिया था. क्रांतिकारी आंदोलन में आने वाले उतार–चढ़ावों के दौरान कॉमरेड मधु अडिग रहे. वे सभी कॉमरेडों के साथ घुल–मिलकर रहते थे. युवा कॉमरेडों के साथ उनका आत्मीय संबंध रहता था. अपने निस्वार्थ, स्नेहिल, मेहनती व अनुशासित स्वभाव के साथ कॉमरेड मधु एक आदर्श नमूना बन गए थे.

कॉमरेड मधु अमर रहे!

कॉमरेड भारती

कॉमरेड भारती (लता) तेलंगाना के मेदक जिले के उल्ली तम्माईपेल्ली गांव में करीब 45 वर्ष पहले पैदा हुई थीं. उनके बाप की रेलवे में नौकरी के चलते वे लोग हैदराबाद में रहते थे. ऐसे में कॉमरेड भारती का बचपन कुछ हद तक हैदराबाद में ही गुजरा था. जब वे सिर्फ 11 वर्ष की थी उनकी शादी हुई. शादी के बाद वो अपनी ससुराल मेदक जिले के चट्ला नर्समपल्ली चली गई थी. जब वे 15 वर्ष की थीं तभी मां बन गई. लेकिन इसके पहले ही उनके जीवनसाथी क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति आकर्षित हो गए थे. बेटा पैदा होने के बाद वे भूमिगत हो गए. कॉमरेड भारती की दुनिया हिल गई थी. वे खूब रोईं. लेकिन क्रांति की जरूरत के बारे में उनके जीवनसाथी के समझाने के बाद वे थोड़ी शांत हो गईं. बेटा के पालन–पोषन के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की. बीडी बनायी. कारखानों में काम किया. सेल्स वुमन बनीं. नर्स बनीं.

अपने जीवनसाथी के प्रति कॉमरेड भारती के प्यार ने धीरे–धीरे उन्हें क्रांति की ओर खींचा. बेटे के बड़े होने तक वे क्रांति की हमदर्द की भूमिका निभाई. धीरे–धीरे वे सक्रिय हो गईं. महिला चेतना नाम के संगठन में सक्रिय भाग लेते हुए वे उस संगठन की अध्यक्षा बनीं. लेकिन बाहरी सांगठनिक काम से वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पायी. वे और आगे बढ़ना चाहती थीं. इसलिए माओवादी महिला बनकर 2011 में भूमिगत हो गईं. एओबी के मलकनगिरी जिले में गुरिल्ला डाक्टर बनकर पार्टी, पीएलजीए व जनता की सेवा की. एओबी में उनका नाम लता था. लगभग 40 वर्ष की उम्र में गुरिल्ला जिंदगी की शुरुआत करना कोई आसान बात नहीं बल्कि साहसिक कदम है. उस साहस को कॉमरेड लता ने आसानी से किया. कॉमरेड लता अपने बेटे को भी जन संगठन में लाईं. उनकी चेतना व कार्य क्षमता को ध्यान में रख कर पार्टी ने उन्हें एसी सदस्यता दी.

कॉमरेड लता एक स्नेहिल व मिलनसार स्वभाव की थी. महिला–पुरुष, छोटे–बड़े, नये–पुराने आदि बिना किसी प्रकार के भेदभाव के वो सभी के साथ मिल–जुलकर रहती थी.

रामागूडा में जब दुश्मन का हमला हुआ था, तब कॉमरेड लता निहत्थे थी. इसके बावजूद उस भीषण हमले में उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई. हमले से नेतृत्व कॉमरेड्स को बचाने अपने शरीर को कवच बनाने की कोशिश करके एक साहसिक नारी के तौर पर क्रांति के इतिहास में अपनी जगह बनायीं.

इस हमले में अपने हाथ लगी कॉमरेड लता को पुलिस बलों ने क्रूर यातनाएं देकर उनकी निर्मम हत्या की.

कॉमरेड लता अमर हरे!

कॉमरेड बोड्डु कुंदना

लड़ाई का पर्याय माने जाने वाले श्रीकाकुलम जिले के मंदसा मंडल, उद्दानम इलाका, नल्ला बोड्डूरु गांव के गरीब खेतिहर परिवार में करीब 45 वर्ष पहले कॉमरेड कुंदना (ममता) का जन्म हुआ था.

भारत वर्ष में एम–एल पार्टियों के जितने ग्रूप हैं, उतने उद्दानम इलाके में मौजूद हैं. इस प्रकार लिनपियाओ ग्रूप भी हुआ करता था, जिसके नेता सालिना माधव राव अपने लोकतांत्रिक विचारों के चलते युवाओं में लोकप्रिय हो गए थे. सालिना माधव राव के प्रभाव से 13 वर्ष की उम्र में कॉमरेड ममता लिनपियाओ ग्रूप से जुड़ी थी. उस पार्टी के

नेतृत्व में किए गए कई आंदोलनों में कॉमरेड ममता भी शामिल हुई थीं. चंद समय बाद कॉमरेड सालिना माधव राव उस पार्टी से अलग होकर तत्कालीन सीपीआई (एम–एल) (पीपुल्सवार) में शामिल हो गए थे. कॉमरेड ममता ने भी उनका अनुसरण किया था. कुछ वक्त के बाद जमींदारों ने कॉमरेड माधव राव की हत्या की. इससे विचलित कॉमरेड ममता कॉमरेड माधव राव की प्रेरणा से 1989 में पेशेवर क्रांतिकारी बन गई थीं.

पार्टी आदेश के मुताबिक विशाखा नगर में बिस्कुट कंपनी में काम करते हुए श्रमिक महिलाओं को संगठित करने में उन्होंने अपना योगदान दिया. उसी वक्त उनकी शादी तकनीकी विभाग में काम करने वाले एक कॉमरेड के साथ हुई थी. लेकिन दो वर्ष के बाद बीमारी से उनका निधन हो गया था. उस दुःखद समय में शहर में अकेली न रह सकने वाली कॉमरेड ममता 1992 में ग्रामीण इलाके में आ गई. उस समय उद्दानम एरिया में सक्रिय कोंडाबारेडु दस्ते की वे सदस्या बनी थीं. कुछ दिन के बाद अस्वस्थाता के चलते वे घर गई थीं. बाहर के महिला संगठनों में काम करते हुए 1996 में फिर भूमिगत हो गई थीं. फिर कोंडाबारेडु दस्ते में ही काम करते हुए 1998 में एसी सदस्या बनी थीं. 1999 में उनकी शादी हुई थी. सैनिक क्षेत्र में भी उन्होंने निपुणता हासिल की. कुछ वक्त के लिए एलजीएस में भी काम किया. कोरापुट एवं नालको हमलों के अलावा कई सैनिक कार्यवाहियों में वे शामिल हुई थी. तकनीकी विभाग में भी उन्होंने काम किया.

लगभग 25 वर्ष की अपनी क्रांतिकारी जिंदगी में कॉमरेड ममता जन संगठन, एलओएस, एलजीएस, तकनीकी विभाग, सीआरसी कंपनी–3 में अपना योगदान दिया.

हालांकि राजनीतिक रूप से विकास होने में, आगे बढ़ने में उन्होंने कुछ सीमितता का सामना किया. लेकिन क्रांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मजबूत रही. बढ़ती उम्र में भी युवा साथियों के साथ मिल कर वे संतरी, किचेन आदि सभी काम करती थीं.

रामागूडा हमले के वक्त वे निहत्थे थीं. इसके बावजूद दुश्मन से डट कर लड़ने के लिए साथी कॉमरेडों को प्रोत्साहित करती रहीं. हमले में वे घायल अवस्था में दुश्मन के हाथ लग गयी थीं. दुश्मन ने कई यातनाएं देकर उनकी निर्मम हत्या की.

कॉमरेड ममता अमर रहे!

कॉमरेड केशव राव

कॉमरेड गेम्मिलि केशव राव (बिर्सु) आंध्रप्रदेश के विशाखा जिले के ताडिपालेम गांव निवासी था. बाद में आजीविका तालाशते हुए विशाखा जिले के गालिकोंडा एरिया के गरिकिबंदी में आया था. उसके दो छोटे भाई हैं. क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित गांव के रहवासी होने की वजह से वह पार्टी के संपर्क में आ गया. उसे दारू पीने की लत थी. मना करने के बावजूद नहीं सुनता था. लेकिन पार्टी की कई तरह मदद करता था.

इस क्रम में उसकी चेतना बढ़ कर 2006 में पूर्णकालीन कार्यकर्ता के तौर पर उसकी भर्ती हुई. हालांकि कुछ लोगों ने उस पर विश्वास नहीं रखा. उनका मानना था कि चूंकि उसे दारू की लत थी, इसलिए उसका आंदोलन में बने रहना मुश्किल था. लेकिन क्रांति के प्रति बिर्सु में जो अथाह विश्वास था, उसने न सिर्फ उसे पूरी तरह दारू से दूर किया बल्कि उसे एक अच्छे कार्यकर्ता का रूप दिया.

गालिकोंडा एरिया में काम करते हुए स्थानीय जनता के साथ जुड़ गया. चंद समय उसने एसजेडसी कॉमरेड के गार्ड की जिम्मेदारी निभाई. बाद में उसका तबादला सीआरसी–1 कंपनी में हुआ था. वह अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाते हुए पीपीसी स्तर तक विकसित हुआ. बाद में सेक्शन कमांडर की जिम्मेदारी उठाई.

कंपनी द्वारा जोन में किए गए कई हमलों में वह शामिल हुआ था. सैनिक कार्यवाहियों में हिम्मत व साहस दिखाता था. एक अनुशासित और मेहनती कॉमरेड के रूप में उभरा कॉमरेड बिर्सु को खोना कंपनी–1 और पूर्व गोदावरी डिविजन आंदोलन के लिए बड़ा ही नुकसान है.

कॉमरेड नंगाल रव्वा

कॉमरेड नंगाल (एर्राल) का जन्म दक्षिण बस्तर डिविजन के पामेड़ एरिया के एर्रापल्ली (एर्रम) गांव, जिसे क्रांतिकारी गढ़ माना जाता है, में 25 वर्ष पहले हुआ था. क्रांतिकारी माहौल में जन्म होने, पलने–बढ़ने की वजह से कॉमरेड नंगाल ने छोटी उम्र में ही क्रांति का रास्ता चुन लिया. मिलिशिया में काम करते हुए जनता ना सरकार की रक्षा करने में योगदान दिया. सीएनएम में शामिल होकर नाच–गाने के जरिए जनता की चेतना बढ़ाने में योगदान दिया. 2009 में वह पेशेवर क्रांतिकारी बना. शुरुआत में एक साल तक उसने पामेड़ और पुव्वर्ति एलओएस दायरे के गांवों में आर्गनाइजर रहा. इसके बाद एक साल पामेड़ एलओएस में काम किया. बाद में उसका तबादला 9वीं पलटन में हुआ था. वहां चार वर्ष काम करने के बाद 2015 जून में उसका तबादला एओबी जोन के प्रधान बल में हुआ था. एओबी की कतारों एवं जनता को वह एर्राल के नाम से परिचय हुआ. शहादत के वक्त वह सीआरसी पलटन में पीपीसी सदस्य की हैसियत से काम कर रहा था. एओबी में लगभग एक साल काम करके उसने वहां की पार्टी, पीएलजीए, जनता का विश्वास जीता.

आठ वर्षों के अपने क्रांतिकारी जीवन में वह कई सैनिक कार्रवाइयों में बहादुराना ढंग से शामिल हुआ था.

2010 ऊसूर–आवापल्ली की सड़क पर पुलिस पार्टी के ऊपर की गई एंबुश में पीएलजीए के योद्धा कॉमरेड्स बुदराम और हड़माल शहीद हुए थे. उनकी लाशों को लाने में कॉमरेड एर्राल का योगदान रहा. 2011 में इसी सड़क पर जब 9वीं पलटन ने पुलिस के ऊपर हमला किया, पलटन कमांडर कॉमरेड हिड़माल शहीद हो गया. इसके बावजूद कॉमरेड एर्राल उस कार्रवाई में बहादुराना तरीके से लड़ा. पामेड़ थाने के नजदीक, हेलिपैड़ की सुरक्षा में तैनात पुलिस बल पर किए गए हमले, जिसमें एक जवान मारा गया, दो जवान घायल हुए और एक एसएलआर जब्त की गई, में भी वह भाग लिया. पामेड एवं जेगरगुंडा इलाकों में की गई कई सैनिक कार्रवाइयों में उसकी भागीदारी थी. क्रांतिकारी बनने के बाद ही पढ़ाई–लिखाई सीखने वाले कॉमरेड एर्राल ने पार्टी का साहित्य पढ़ते हुए राजनीतिक व सैनिक रूप में विकसित होने के लिए बहुत मेहनत की. इस अनुशासित व लड़ाकू कॉमरेड ने अपने नव यौवन को क्रांति के लिए समर्पित किया.

कॉमरेड एर्राल अमर रहे!

कॉमरेड बुदरी

कॉमरेड बुदरी छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले के गंगालूर एरिया के गोरनम गांव में 27 वर्ष पहले पैदा हुई थी. उसने अपने पीछे दो बहन व तीन भाईयों और पूरे परिवार को छोड़ गयी. पहले उसके परिवार कट्टेकल्याण एरिया में रहता था. वहां के जमींदारों की लूट व शोषण को सहन न कर पाने वाले उसके परिजन गोरनम गांव में आये थे. उन्होंने वहीं मजदूरी करते हुए कुछ जमीन खरीदी.

क्रांतिकारी गतिविधियों वाले गांव होने की वजह से कॉमरेड बुदरी मिलिशिया में भर्ती हुई थी. मिलिशिया में काम करते हुए वह खेती काम में मां–बाप का हाथ बंटाती थी. इस क्रम में उसके बाप को गिरफ्तार किया गया. अपनी मां को हिम्मत देते हुए उसने खेती काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली. 2005 के सलवा जुडुम में जुडुम गुंडों ने कॉमरेड बुदरी के काका की निर्मम हत्या की. जिसे देख कर दुश्मन के प्रति कॉमरेड बुदरी का क्रोध और बढ़ा. जुडुम के बीभत्स को देख कर विचलित होने वाली कॉमरेड बुदरी के परिजनों ने सोच लिया कि वे गांव छोड़ कर जाएंगे. लेकिन बुदरी गांव छोड़ने के लिए बिलकुल तैयार नहीं थी. इसलिए उसके परिजन भी रुक गए. मिलिशिया में कॉमरेड बुदरी की बढ़ती भूमिका देख घबराकर उसके मां–बाप ने उसकी शादी करने की कोशिश की. लेकिन बुदरी नहीं मानी. बुदरी के प्रभाव से उसकी छोटी बहन बाल संगठन में एवं छोटा भाई मिलिशिया में भर्ती हो गए.

दिसंबर 2009 में कॉमरेड बुदरी ने क्रांतिकारी आंदोलन में पेशेवर कार्यकर्ता के तौर पर कदम रखा था. मार्च 2010 में उसका तबादला क्रांतिकारी जरूरतों के मुताबिक एओबी में हुआ था. वहां सीआरसी की तीसरी कंपनी में उसकी नियुक्ति हुई. हर काम वह जिम्मेदाराना ढंग से करती थी. जोन में की गयी कई सैनिक कार्यवाहियों में और जन दुश्मनों को सजा देने में उसकी भागीदारी थी. एसजेडसी बैठक आदि विशेष कार्यक्रमों के दौरान संचालित बड़े कैंपों में वह किचेन की जिम्मेदारी सटीक संभालती थी.

2012 में उसके बाप को गिरफ्तार किया गया. 2015 में उसकी छोटी बहन और छोटे भाई जो एक महीने के बाद गुरिल्ला दस्ते में भर्ती होने वाले थे, गिरफ्तार किए गए. जनवरी 2016 में मद्देड एरिया में काम करने वाला उसका छोटा भाई शहीद हो गया. इन सभी तकलीफों को झेलने के बावजूद हिम्मत न हारने वाली बुदरी क्रांतिकारी आंदोलन में आगे कदम बढ़ाती गयी.

मई, 2014 में उसका तबादला पीएस–1 में हुआ था जहां उसने कुछ समय संतरी जिम्मेदारी और कुछ समय किचेन जिम्मेदारी संभाली. नेतृत्वकारी कॉमरेडों की सुरक्षा के प्रति वह हर वक्त सतर्क रहती थी. जनवरी 2015 में पीएस की डिप्यूटी कमांडर बनी. 2015 अक्टूबर यानी शहादत के कुछ दिन पहले उसे एसी सदस्यता दी गई.

रामागूडा में नेतृत्वकारी कॉमरेडों को बचाने हिम्मत व साहस के साथ दुश्मन से लोहा लेते हुए कॉमरेड बुदरी ने वीर गति को प्राप्त किया.

कॉमरेड बुदरी अमर रहे!

कॉमरेड उंगी

कॉमरेड उंगी (मंजुला) दंडकारण्य के दरभा डिविजन के मलिंगेर एरिया के बर्रेगूडेम गांव के एक गरीब आदिवासी परिवार में 23 वर्ष पहले पैदा हुई थी. उसकी एक बड़ी बहन व तीन छोटी बहन हैं. बाप की अकाल मृत्यु की वजह अकेली मां ने बच्चियों का पालन–पोषण किया. मां एवं बेटियां मिल कर खेती–बाड़ी करती थी. मंजुला की बड़ी बहन की शादी के बाद मंजुला ने खेती का अधिक बोझ उठाया. इसी समय क्रांतिकारी आंदोलन से मंजुला का परिचय हुआ था. क्रांतिकारी क्रियाकलापों में भाग लेते हुए वह मिलिशिया में भर्ती हुई थी. इस से मां नाराज हो गई. लेकिन मंजुला ने मां को आश्वासन दिया था कि वह घर छोड़ कर नहीं जाएगी, घर की जिम्मेदारी निभाते ही मिलिशिया में काम करेगी. ऐसे ही कुछ वक्त तक उसने काम किया. तीन साल मिलिशिया में काम करने के बाद उसकी नियुक्ति केएएमएस में की गई थी. उसमें एक साल काम करने के बाद पेशेवर क्रांतिकारी

के तौर पर पीएलजीए में भर्ती होने का फैसला उसने पार्टी के सामने रखा था. जुलाई, 2011 में उसकी भर्ती हुई थी. पहले उसे इन्स्ट्रक्टर टीम में नियुक्त किया गया. एक साल वहां काम करने के बाद 2012 में उसका तबादला एओबी में हुआ था. एओबी में पीएस–2 में सदस्या बन कर डाक्टर की जिम्मेदारी निभाई. वह सभी कामों में सक्रिय भाग लेती थी. उसके सामर्थ्य, व्यवहार व अनुसाशन को ध्यान में रख कर 2016 में उसे एसी में लिया गया.

रामागूडा में दुश्मन के साथ हिम्मत से लड़ते हुए उसने शहादत को पाया.

कॉमरेड मंजुला अमर रहे!

कॉमरेड सोमलू

कॉमरेड सोमलू (राजेश) दंडकारण्य में करीबन 25 वर्ष पहले पैदा हुआ था. उनका परिवार दरभा डिविजन के कट्टेकल्याण एरिया से पलायन करके पश्चिम बस्तर डिविजन के भैरांगढ़ एरिया के कोत्रपाल आया था.

कोत्रपाल उन गांवों में शामिल है जिन्होंने सलवा जुडुम के खिलाफ जुझारू लड़ाई लड़ी थी. सलवा जुडुम के वक्त कॉमरेड राजेश सिर्फ 13 साल का लड़का था. सलवा जुडुम के अत्याचारों के खिलाफ उसमें पैदा हुई नफरत ने उसे क्रांति की तरफ खींचा. उस वक्त उसने गुरिल्ला दस्ते में भर्ती होने की अपनी इच्छा जताई. लेकिन छोटी उम्र के होने की वजह उसे कुछ समय मिलिशिया में काम करने का सुझाव दिया गया था. उसे मानकर उसने मिलिशिया में भर्ती होकर सलवा जुडुम को हराने में अपना योगदान दिया. वह उस महत्वपूर्ण कार्रवाई, जिसमें 17 सलवा जुडुम गुंडों को खतम किया गया था, में भी भाग लिया.

2006 में पेशेवर क्रांतिकारी बन कर वह पीएलजीए में भर्ती हुआ. मद्देड पलटन में काम करते हुए कई सैनिक कार्रवाइयों में भाग लिया. 2007 मार्च में किए गए ऐतिहासिक रानिबोदिली हमले में भी वह शामिल हुआ. 2007 में उसका तबादला एओबी में हुआ था. वहां सीआरसी की कंपनी–1 में उसने काम किया. एओबी के पूर्व डिविजन में कंपनी द्वारा किए गए सभी हमलों में उसकी भागीदारी थी. नयागढ़ हमले में और गुनकुराई एंबुश में वह अस्साल्ट पार्टी में रह कर अपना योगदान दिया था. वह हिम्मत व साहस से दुश्मन के साथ लोहा लेता था. कुछ मुठभेड़ों में घायल साथियों को रिट्रीट कराने में उसकी मुख्य भागीदारी थी. एक मुठभेड़ में वह घायल होने के बावजूद फाइरिंग करते हुए रिट्रीट हुआ था.

उसकी सैनिक क्षमता के मुताबिक 2012 में उसे पीपीसी में लिया गया.

एक उभरते हुए सैनिक कमांडर को खोना क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बड़ा ही नुकसान है.

कॉमरेड राजेश अमर रहे!

कॉमरेड सुर्जित दर्रो

दंडकारण्य के उत्तर बस्तर डिविजन के रावघाट एरिया के कंदाडी गांव के एक आदिवासी मध्यम वर्गीय किसान परिवार में लगभग 40 वर्ष पहले कॉमरेड सुर्जित दर्रो (गौतम) का जन्म हुआ था. उन्होंने छठवीं तक पढ़ाई की थी. कंदाडी एक क्रांतिकारी गांव है. उनकी मां केएएमएस में सक्रिय भाग लेते हुए जनता ना सरकार में शामिल हुई थीं. उनके सक्रिय क्रियाकलापों के जरिए बाद में वे जनता ना सरकार की अध्याक्षा बनी. 2013 में बीमारी के चलते वे शहीद हो गई थीं. परिवार और गांव की क्रांतिकारी विरासत को आगे ले जाते हुए कॉमरेड गौतम ने पहले डीएकेएमएस में काम किया था. उसी वक्त उनकी शादी हुई थी. 2000 में अपनी 23 वर्ष की उम्र में वे पेशेवर क्रांतिकारी बन गए. साथ में उनकी जीवनसंगिनी भी पार्टी में भर्ती हुई थी. कॉमरेड गौतम की पढ़ाई व तकनीकी ज्ञान के मद्देनजर 2001 में उत्तर बस्तर डिविजन के तकनीकी विभाग में उनकी नियुक्ति हुई थी. उस काम में उन्होंने निपुणता हासिल की. कुछ दिन के बाद किसी समस्या से उनकी पत्नी ने आत्महत्या की. उस दर्द से उभरने वाले कॉमरेड गौतम फिर अपनी जिम्मेदारियों में निमग्न हो गए. कुछ साल के बाद उन्होंने फिर शादी की.

कॉमरेड गौतम की क्षमता को ध्यान में रख कर उन्हें जोन तकनीकी विभाग में भेजा गया. दो साल वहां काम करने के बाद उनका तबादला सेंट्रल तकनीकी विभाग की भोपाल इकाई में हुआ था. वहां उन्होंने उस विभाग से संबंधित कई काम सीख कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जनवरी, 2007 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी. दो साल जेल में बिताने के बाद 2009 में वे रिहा हो गए. बाद में उनका तबादला एओबी तकनीकी यूनिट में हुआ था. वहां उन्होंने तकनीकी यूनिट के कमांडर की जिम्मेदारी संभाली. यूनिट के सदस्यों को तकनीकी ज्ञान पहुंचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया. हथियारों के अलावा इलक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन संबंधित ज्ञान भी उन्होंने हासिल किया. जोन की जरूरतों को पूरा करने उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी. जरूरत के अनुसार सभी डिविजनों में वे जाते थे.

इस प्रकार कॉमरेड गौतम उत्तर बस्तर डिविजन, डीके जोन, सेंट्रल तकनीकी विभाग, एओबी तकनीकी विभाग आदि कई जगहों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया. कई सैनिक कार्यवाहियों में भी वे शामिल हुए थे. पार्टी की जरूरतों के मुताबिक वे विकास हुए थे. ऐसे में उनकी शहादत सिर्फ एओबी के लिए नहीं बल्कि पूरे क्रांतिकारी आंदोलन के लिए ही बड़ा नुकसान है.

कॉमरेड गौतम अमर रहे!

कॉमरेड ज्योती

आंध्रप्रदेश राज्य, विशाखा जिला, पेदाबयलु एरिया, इंजेरि पंचायत, गुनलोवा गांव के एक गरीब आदिवासी परिवार में 18 वर्ष पहले कॉमरेड ज्योती का जन्म हुआ था. शराबी मां–बाप परिवार पर ध्यान न देने की वजह ज्योती को ही परिवार का बोझ उठाना पड़ा. साथी लड़कियों के साथ वह मजदूरी करती थी. क्रांतिकारी आंदोलन के प्रभाव वाले गांव में पलने–बढ़ने की वजह से छोटी उम्र में ही वह पार्टी के परिचय में आ गई.

क्रांति की आवश्यकता के बारे में अपने स्वानुभव से समझनेवाली कॉमरेड ज्योती 2013 में पूर्णकालीन क्रांतिकारी बनी. उसकी नियुक्ति पेदाबयलु दस्ते में हुई थी. दस्ते के सभी कामों में लगन के साथ शामिल होती थी. पढ़ाई सीखने में ध्यान देती थी.

2015 में उसका तबादला पार्टी जरूरतों के मुताबिक कटॉफ एरिया में हुआ था. वहां की भाषा सीख कर वह जनता के साथ जुड़ गई. गांवों की किशोरी लड़कियों के साथ घनिष्ट संबंध बना कर उन्हें क्रांतिकरी राजनीति से लैस किया करती थी.

कॉमरेड ज्योती अमर रहे!

कॉमरेड रजिता

आंध्रप्रदेश राज्य के विशाखा जिले के पेदाबयलु एरिया के इंजेरी पंचायत के नानाबरी गांव में कॉमरेड रजिता पैदा हुई थी. बचपन में ही मां–बाप को खोनेवाली कॉमरेड रजिता रश्तेदारों के यहां पली–बढ़ी थी. बचपन में ही मां–बाप के प्यार से वंचित कॉमरेड रजिता को गुरिल्ला कॉमरेड्स के पास प्यार मिला. इस प्रकार वह क्रांति के नजदीक आई. क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगी. लेकिन बचपन से ही वह फिट्स की समस्या से पीड़ित थी. इसके बावजूद उसने गुरिल्ला दस्ते में भर्ती होने का अपना इरादा पार्टी के सामने व्यक्त किया था. पार्टी ने उसकी तबियत के बारे में समझाते हुए उसे घर में रह कर काम करने का आग्रह किया. लेकिन उसने नहीं माना. गेरिल्ला दस्ते में ही दम तोड़ने का अपना इरादा व्यक्त किया.

ऐसा 2013 में पेदाबयलु दस्ते में भर्ती हुई थी. वह गुरिल्ला दस्ते के दैनंदिन क्रियाकलापों में अच्छी तरह शामिल होती थी. अस्वस्थता के बावजूद बोझा उठाने में, घंटों चलने में पीछे नहीं रहती थी. अनुशासन का सटीक पालन करती थी. किसी में भी अनुशासन हीनता दिखने से वह आलोचना करती थी.

2015 में उसका तबादला कटॉफ एरिया में हुआ था. ओडिया सीख कर वहां की जनता से जुड़ने की उसने कोशिश की. उसी जनता के बीच में वह शहीद हो गई.

कॉमरेड रजिता अमर रहे!

कॉमरेड दासूराम

आंध्रप्रदेश राज्य के विशाखा जिले के जी.माडुगुला मंडल के बोइतल पंचायत के वाकपल्ली गांव के एक गरीब आदिवासी परिवार में 22 वर्ष पहले कॉमरेड दासूराम का जन्म हुआ. वाकपल्ली वही गांव है जिसकी 11 महिलाओं ने पुलिस के अत्याचार के खिलाफ जुझारू आंदोलन किया था. कॉमरेड दासूराम की दो बड़ी बहन हैं. कॉमरेड दासूराम 10 वीं तक पढ़ाई की.

समाज में मौजूद असमानता के खिलाफ उसमें पैदा हुए सोच–विचार ने उसे क्रांतिकारी बना लिया. 2014 में पूर्णकालीन कार्यकर्ता के तौर पर वह क्रांतिकारी आंदोलन में कदम रखा था. पेदाबयलु दस्ते में उसने डॉक्टर की जिम्मेदारी निभायी. डिविजन में संचालित मिलिटरी कैंप में शामिल होने के बाद सैनिक मामलों में उसकी पकड़ बढ़ी. इसलिए 2016 में उसका तबादला सीआरसी पलटन में हुई थी. वह साथी कॉमरेडों को पढ़ाता था. वह एक कलाकर भी था. नाच–गाने के साथ जनता में राजनीतिक प्रचार करता था. जनता, मिलिशिया व पार्टी कतारों के साथ दोस्ती करता था.

एक युवा कॉमरेड को खोना पूर्व गोदावरी आंदोलन के लिए बड़ा ही नुकसान है.

कॉमरेड दासूराम अमर रहे!

कॉमरेड गंगाल

कॉमरेड गंगाल ओडिशा राज्य के मलकनगिरि जिले के कलिमेला एरिया के कोर्रुबु गांव के एक आदिवासी गरीब परिवार में करीब 20 वर्ष पहले पैदा हुआ था. कोर्रुबु गांव में किसान मजदूर संगठन, महिला संगठन व बालक संगठन मजबूत थे. पार्टी के नेतृत्व में कलिमेला एरिया में कई जन समस्याओं को लेकर आंदोलन किया गया. कई जमींदारों को सजा दी गयी. इस इलाके में भूमिहीन व गरीब किसानों को जमीन बांटी गई. क्रांतिकारी सुधार कार्यक्रमों को अमल किया गया. इन सबके असर से कॉ गंगाल बाल संगठन में भर्ता हुआ था. जबकि कॉमरेड गंगाल के बड़े भाई और छोटा भाई भी क्रांतिकारी जन

संगठनों के कार्यकर्ता हैं.

बाल संगठन में काम करने के बाद कॉ. गंगाल की भर्ती मिलिशिया में हुई थी. 2014 में अपने 18 वर्ष की उम्र में वह पूर्णकालीन क्रांतिकारी बना था.

एक साल तक उसने स्थानीय कलिमेला दस्ते में काम किया. सैनिक निपुणता हासिल करते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए उसने नेतृत्वकारी कॉमरेडों का विश्वास जीता. उसके सकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रख कर 2015 में उसे सीसी कॉमरेड के गार्ड की जिम्मेदारी दी गई. नेतृत्वकारी कॉमरेडों की सुरक्षा के प्रति अत्यंत सतर्क रहते हुए वह सभी कामों में शामिल होता था. कमांडर के कॉशन का कड़ाई से पालन करता था. वह एक साहसिक गुरिल्ला था. वह हंसमुख था और हमेशा मुस्कराता रहता था.

हमले के समय में कॉ. गंगाल संतरी में था. दुश्मन का हमला शुरू होने के तुरंत बाद वह अपने कमांडर को बचाने के मकसद से भाग कर डेरा में आ गया. लेकिन इसके पहले ही डेरा से सारे कॉमरेड्स रिट्रीट कर गए थे और डेरा दुश्मन के कब्जे में चला गया था. डेरा में ही दुश्मन ने गंगाल को पकड़ कर कई यातनाएं देकर उसकी निर्मम हत्या की.

इस तरह अपनी जान की परवाह न करते हुए नेतृत्व को बचाने की कोशिश करने वाला कॉ. गंगाल एक आदर्श गार्ड का नमूना बन गया.

कॉमरेड गंगाल अमर रहे!

कॉमरेड माडिवि लक्के

दंडकारण्य के दक्षिण बस्तर डिविजन के हलिगोंडा गांव के एक गरीब आदिवासी परिवार में 19 वर्ष पहले कॉमरेड लक्के (कमला) पैदा हुई थी. उसके दो छोटे भाई और एक छोटी बहन हैं. बचपन में ही कॉमरेड कमला ने मां–बाप को खोया. पहले कॉमरेड कमला के परिजन दरभा इलाके में रहते थे. आजीविका की तलाश में आए अपने दादा–दादी के साथ ये बच्चे भी हलिगोंडा में आ गये थे. कुछ जमीन हासिल कर खेती किया करते थे. मां–बाप न होने की वजह कॉमरेड कमला ने बचपन में ही परिवार की जिम्मेदारी उठाई. घर व खेतों में पसीना बहाते हुए उसने छोटे भाई–बहनों का पालन–पोषन किया.

क्रांतिकारी गांव होने के नाते कॉमरेड कमला पर भी आंदोलन का असर पड़ा. जमींदारों और आदिवासी मुखियाओं के खिलाफ उस गांव में किए गए आंदोलनों से प्रभावित होकर कॉमरेड कमला क्रांतिकारी बाल संगठन का हिस्सा बनी.

2013 में वह क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन में शरीक हो गई. महिलाओं पर अमल हो रहे दमन के खिलाफ संचालित कई कार्यक्रमों में वह शामिल हुई थी. कॉमरेड कमला दिसंबर, 2015 में पूर्णकालीन क्रांतिकारी बन गई. स्थानीय पार्टी ने उसे उसी इलाके में काम करने का सुझाव दिया. लेकिन कमला ने कहीं दूसरे रज्य में काम करने का अपना इरादा पार्टी के सामने रखा था, जिसे ध्यान में रख कर पार्टी ने 2016 अप्रैल में उसका तबादला एओबी में किया.

एओबी में उसकी नियुक्ति पीएस–2 में हुई थी. वहां उसने किचेन जिम्मेदारी संभाली. वहां की ओडिया भाषा सीखने की कोशिश करते हुए वह सभी कामों में हंसी–खुशी से भाग लेती थी.

रामागूडा में दुश्मन के हमले का सामना करते हुए वह शहीद हो गई. वह छोटी उम्र की थी. और छोटा था उसका क्रांतिकारी जीवन. लेकिन चेतना के प्रदर्शन में, अंतर्राष्ट्रीयता को ऊंचा उठाने में, दुश्मन के साथ लड़ने में, कुरबानी देने में वह किसी से छोटी नहीं थी.

कॉमरेड कमला अमर रहे!

कॉमरेड सुरेश

ओडिशा राज्य के श्रीकाकुलम–कोरापुट डिविजन के नारायणपट्ना एरिया के सामना गांव के एक गरीब आदिवासी परिवार में कॉमरेड सुरेश (नरेश) का जन्म हुआ. बचपन में ही उसने मां को खोया. बाप ने फिर से शादी की. कॉमरेड नरेश की एक सौतेली बहन है. बचपन से ही गरीबी, भूखमरी को झेलते आ रहे नरेश को नरायणपट्ना भूमि कब्जा संघर्ष ने रास्ता दिखाया. 15 वर्ष की उम्र में ही वह क्रांति की राह पकड़ कर मिलिशिया में भर्ती हुआ था. मिलिशिया में सक्रिय भूमिका निभाते हुए 2012 में पेशेवर क्रांतिकारी बन गया. उसके अनुशासन को देख कर पार्टी ने उसे एसजेडसी सदस्य के गार्ड की जिम्मेदारी सौंपी थी. उस जिम्मेदारी को निभाते हुए ही वह सभी कामों में शामिल होता था. वह शांत स्वभाव का और कुशाग्रबुद्धि वाला था. वह मितभाषी था. लेकिन जनता के साथ वह घनिष्ट संबंध बना लेता था.

2015 में उसका तबादला सीआरसी कंपनी–1 में हुआ था. वहां काम करते समय जब भी कोरापुट डिविजन के कॉमरेड्स मिलते, तो उनके गांव के बारे में, गांव में पार्टी की स्थिति के बारे में पूछता था. वह हमेशा यह आकांक्षा प्रकट करता था कि उनके गांव में पार्टी मजबूत हो. जब उसे पता चला कि उसकी छोटी बहन की शादी की कोशिश चल रही है, उसने विरोध जताया. पार्टी से आग्रह किया कि बहन को भी पार्टी में ला आए. क्रांति के कठिन मार्ग में अपनी अकेली बहन को भी लाने की उसकी कोशिश कोई साधारण बात नहीं है. *(शेष पेज 39 में...)*

देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हित में नोटबंदी–जनधन की बैंकों में जमाबंदी

(काला–सफेद के नस्लभेदी विचार को ध्यान में रखकर इस लेख में 'कालाधन' या गैर कानूनी धन लिखा गया है.)

कॉरपोरेट वर्गों के प्रधान सेवक मोदी ने अचानक 8 नवंबर की रात को 500 व 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण/नोटबंदी व उनकी जगह 500 व 2000 रुपए के नए नोटों को प्रचलन में लाने का ऐलान किया और कई नाजायज व परेशान करने वाली शर्तों के साथ बैंकों व डाक घरों में पुराने नोटों को जमा करने 30 दिसंबर तक की समय सीमा तय की थी. पुराने नोटों के बदले नए नोट उपलब्ध कराने की समुचित व पर्याप्त व्यवस्था के घोर अभाव में देश की गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग व मध्य वर्गीय जनता को अनगिनत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि देश में पहली बार 1946 में और दूसरी बार 1978 में बड़े नोटों को बंद किया गया था, लेकिन उस समय साधारण जनता को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी. क्योंकि उस वक्त अर्थ व्यवस्था में बड़े नोटों का प्रचलन सिर्फ 2 प्रतिशत था. जबकि अब देश में कुल करेंसी में से 500 रु. व 1000 रु. के नोटों का मूल्य 86.4 प्रतिशत है और कुल लेन–देन का 97 प्रतिशत नकदी के जरिए किया जाता है. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 500 व 1000 के नोटों का कुल मूल्य क्रमशः 8.2 लाख करोड़ और 6.4 लाख करोड़ रुपए है. इस तरह, 500 और 1000 रुपए के कुल करेंसी नोटों के मूल्य 14.6 लाख करोड़ रुपए का एक झटके में विमुद्रकरण कर दिया गया है जिसके चलते देश में अफरा–तफरी मच गयी.

मोदी ने नोटबंदी के क्या कारण गिनाएं?

मोदी ने नोटबंदी के तीन कारण गिनाए–अर्थ व्यवस्था से 'कालेधन' को निकाल बाहर करना, भ्रष्टाचार व नकली नोटों के प्रचलन पर रोक लगाकर आतंकवाद {कश्मीरी जनता का आन्दोलन, पूर्वोत्तर की राष्ट्रीयताओं के आन्दोलन, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आन्दोलन} का खात्मा करना.

सच्चाई क्या है?

सौ साल पहले ही कॉमरेड लेनिन ने कहा था कि शासकों के नारों के पीछे की नीतियों को यदि नहीं समझेंगे तो शासित बार–बार धोखा खाएंगे. नोटबंदी के संदर्भ में यह कथन बिल्कुल सच साबित होती है. मोदी ने नोटबंदी के जो कारण गिनाए, वो निराधार, बेबुनियाद एवं जनता को धोखा देने वाले हैं. नोटबंदी का निर्णय दरअसल जन विरोधी, देश विरोधी, फासीवादी, देश की अर्थ व्यवस्था को कमजोर करने वाला, देशी–विदेशी कॉरपोरेट घरानों को असीम फायदा पहुंचाने वाला है. साम्राज्यवादपरस्त उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नीतियों को अभूतपूर्व ढंग से लागू करने के तहत, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व वित्तीय संकट के बोझ को भारत की उत्पीड़ित व मेहनतकश जनता के कंधों पर लादने की कवायद के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं एडीबी जैसी वित्तीय संस्थाओं के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए नोटबंदी व नकद रहित अर्थ व्यवस्था की ओर आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया है.

आईएमएफ, विश्व बैंक के आदेशों का पालन करते हुए सरकार देश के अधिकांश या कहे तो सारे लोगों को कई किस्म के करों के दायरे में लाने व उनके रोजमर्रा के सारे लेन–देन को राज्यसत्ता के दायरे में लाने के लिए ही नोटबंदी व नकद रहित अर्थ व्यवस्था पर अमल कर रही है. नकद सहित से नकद रहित ऑन लाइन लेन–देन की व्यवस्था में जनता को एकबार स्वेच्छा से घसीटने के बाद स्वयमेव लोग कर प्रणाली में आ जाएंगे. सारे खरीद–फरोख्त, सारे लेन–देन ऑन लाइन होने से व्यवस्थीकृत तौर पर करों में बढ़ोत्तरी होगी जोकि मोदी की नोटबंदी के मकसद का अहम हिस्सा है.

यह सर्व विदित है कि विगत में मोदी ने बैंक पूंजी को बढ़ाने व ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ने की साजिश के तहत जन धन योजना की शुरुआत की थी जिसके तहत 26 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुल गए थे और जिन खातों में 71 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा धन जोकि देश की आम जनता की गाढ़ी कमाई है, जमा हो गया है. हालांकि यह सही है कि इनमें से कई खातों में जीरो बैलंस है. अब यह राशि बैंक पूंजी बनकर देशी, विदेशी पूंजीपतियों के हित में इस्तेमाल हो रहा है. अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना आदि तमाम योजनाएं दरअसल कॉरपोरेट लूट की जंजीर की विभिन्न कड़ियां हैं और नोटबंदी उसी जंजीर की हालिया कड़ी है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर, पूर्व वित्त मंत्री, दो बार के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को 'भारी कुप्रबंधन' कहा और इसे 'व्यवस्थित लूट और कानूनी डाके' का मामला बताते हुए राज्यसभा में कहा कि यह देश के जीडीपी को दो प्रतिशत नीचे ले जाएगा.

राजनीतिक रूप से भाजपा सरकार के नोटबंदी का निर्णय एक ओर देश की जनता की असली समस्याओं से उनका ध्यान बंटाने की साजिशाना हरकत है और अपने चुनावी लोक लुभावन वादों–'अच्छे दिन आएंगे', 'विदेशी बैंकों में जमा 'कालाधन' वापस लाकर देश के हर एक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराएंगे' आदि जुमलेबाजियों को भुलाने की नीच हरकत है. दूसरी ओर समय व संदर्भ के तौर पर देखा जाए तो पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के चुनाव के लिए स्वयं को पूरी तरह तैयार रखना और अन्य दलों के फंड्स के स्रोतों पर अंकुश लगाकर उन्हें कमजोर करना. क्यों कि भाजपा अपने खातों में नोटबंदी की घोषणा के पहले ही पुराने नोटों को जमा कर पार्टी फंड के रूप में जमा अपने 'कालेधन' को सफेद कर रखा है.

'कालाधन' क्या है? कहां है? किस रूप में है? कितना है? और किसके पास है?

किसी देश की अर्थ व्यवस्था में मौजूदा कानून व कर प्रणाली के मातहत उपार्जित आय व संचित संपत्ति को कानूनी धन या 'सफेद धन' जबकि कर न पटाकर, गलत हिसाब बताकर, गैर कानूनी तरीके से उपार्जित की गयी आय व संचित संपत्ति को 'कालाधन' या गैर कानूनी धन कहते हैं. 'कालाधन' का एक बड़ा हिस्सा वह होता है जो कहीं दर्ज नहीं होता है और न ही कर प्रणाली के दायरे में आता है. यहां हमें एक बात साफ तौर पर समझना चाहिए कि शोषणमूलक असमान सामाजिक व्यवस्था में जहां शोषण, उत्पीड़न, दमन व अन्याय द्वारा ही सामाजिक संपदा का संचय होता है, वहां 'सफेद' या कानूनी धन और 'कला' या गैर कानूनी धन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है. यह कहना सही होगा कि उत्पादन की गतिविधियों में शामिल मेहनतकशों को उनकी मेहनता का पूरा फल जब तक नहीं मिलता है तब तक पूंजीपतियों, सामंतियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास संचित सारी संपत्तियां गैर कानूनी ही हैं. 'कालेधन' की अर्थव्यवस्था को समानांतर, आभासी, भूमिगत, अघोषित, अनियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है.

1978 की नोटबंदी के समय तत्कालीन रिजर्व बैंक गवर्नर आईजे पटेल ने तत्कालीन प्रधनमंत्री मोरारजी देशाई से साफ कह दिया था कि नोटबंदी से 'कालाधन' पर रोक नहीं लगाया जा सकता है. इससे जाहिर है कि नोटबंदी के जरिए 'कालाधन' को बाहर निकाल फेंकने के मोदी का दावा बकवास ही नहीं बल्कि असली मकसद को छुपाने व जनता को दिग्भ्रमित करने की जुमलेबाजी के सिवाय और कुछ नहीं.

'दि ब्लैक इकॉनमी इन इंडिया' के लेखक प्रोफेसर अरुण कुमार के अनुसार 'काली' अर्थव्यवस्था का मौजूदा आकार करीब 90 लाख करोड़ है और यह देश में समानांतर नहीं है बल्कि 'सफेद' अर्थव्यवस्था में गुंथी–पगी है. 2012 की कीमतों पर यह 106.44 लाख करोड़ रुपए की देश की जीडीपी का 60 प्रतिशत यानी 63.9 लाख करोड़ रुपए है. लेकिन 'कालाधन' तिजोरियों, गद्दों, तकियों, स्नानघरों या पाखानों में भरा नहीं होता है. वह बड़े नोटों के रूप में भी बहुत कम ही होता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी(एनआईपीएफपी) के अनुसार 'कालेधन' का लगभग छह प्रतिशत हिस्सा ही नकदी के रूप में है यानी 3.83 लाख करोड़ रुपए. नोटबंदी के बाद चूंकि फिर से बाजार में नए बड़े नोट ला रहे हैं, इसलिए एक मोटे अनुमान के मुताबिक अधिकतम 10 प्रतिशत 'कालाधन'–38.3 हजार करोड़ रुपए ही वापस लाया जा सकता है. इससे साफ जाहिर है कि 'कालाधन' का बाकी 94 प्रतिशत अन्य रूपों में फल–फूल रहा है. असली 'कालाधन' वह है जो व्यापार में लगा तो होता है पर कर नहीं पटाता है. घूस आदि से जमा होता है. राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान के 2012 के अध्ययन–स्टडी ऑन अनअकाउंटेड इंकम/वैल्थ बोथ इन्साइड आउटसाइड दि कंट्री के अनुसार अत्यधिक मात्रा में 'कालाधन' कम कीमत पर आंकी गयी बिल्डिंग व भू–संपत्ति, बिल्डिंग व भू–संपत्ति, सोना, चांदी व अन्य कीमती धातुओं, हीरे–जवाहरात, बेनामी वित्तीय निवेश, कम आंकी व अघोषित स्टॉक्स के रूप में जबकि सीमांत रूप से कम आंकी व अघोषित एसेट,

अघोषित विदेशी संपत्ति, नकदी के रूप में है. साथ ही 'कालाधन' असल से कम या ज्यादा बिलों वाली विदेशी व्यापार गतिविधियों, उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉरपोरेट अस्पतालों, रियल एस्टेट कारोबार, खनन उद्योग में निवेशित पूंजी के रूप में है जो लगातार अपनी वृद्धि करता है. 'यहां यह गौर करने वाली बात है कि 'कालाधन' हमेशा 'काला' ही नहीं होता है. वह 'काला' से 'सफेद' और फिर 'सफेद' से 'काला' में तब्दील होते रहता है और इस दौरान उसका आकार मोटा होते जाता है. यह प्रक्रिया विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेशों के रूप में, अप्रवासी भारतीयों के द्वारा देश में पूंजी निवेश के रूप में, देश से विदेशी बैंक खातों में जमा राशि के रूप में, सत्ताधारियों द्वरा कॉरपोरेट घरानों को दी जाने वाली करों में छूट की खुली लूट के रूप में, देशी–विदेशी कॉरपोरेट घरानों के नाजायज फायदे के लिए बनाए गए कानूनों की मदद से, बहुत बड़ी मात्रा में पूंजीपतियों के बैंक कर्जों को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों(एनपीए–डूबत खातें) के नाम पर माफ करने के रूप में जारी रहती है. इस 'कालेधन' का संरक्षण स्वयं सरकारें करती हैं चाहे जिस किसी भी पार्टी की सत्ता रहे. यहां यह याद दिलाना वाजिब होगा कि मोदी सरकार ने पिछले ही साल विदेश पैसा ले जाने की सीमा बढ़ा दी थी.

यह जगजाहिर है कि बड़े औद्योगिक घरानें, भ्रष्ट राजनेता व नौकरशाह, बड़े व्यापारी, बड़े ठेकेदार, जमींदार–मालगुजार, भू माफिया, शासन–प्रशासन के संरक्षण में फलते–फूलते अन्य माफिया–गुण्डा गिरोह आदि ही 'कालेधन' के मालिक हैं.

अप्रैल, 2000–मार्च, 2011 के बीच भारत पहुंचे कुल विदेशी पूंजी निवेश का 41.8 प्रतिशत मारिशस से और 9. 17 प्रतिशत सिंगापुर से आया. न्यूनतम अर्थव्यवस्थाओं वाले छोटे देशों से इतनी बड़ी राशि कैसे आ सकती है? सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि उक्त राशि प्रवासी भारतीयों का 'कालाधन' है जिसे घुमा फिराकर वापस अपने खुद की कंपनियों तक पहुंचाया गया है.

फरवरी, 2012 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हलफनामे में यह स्पष्ट किया कि स्विस, मारिशस, ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स, सिंगापुर आदि विदेशी बैंकों में भारतीयों के खातों में 500 बिलियन डॉलर संपदा जमा है. यहां यह बताना लाजिमी होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ही मोदी सरकार ने विशेष जांच दल(एसआईटी) का गठन किया. लेकिन 'पनामा पेपर्स', 'विकीलीक्स' के जरिए उजागर 782 देशद्रोहियों जिन्होंने देश की संपत्ति को विदेशी बैंकों में जमा कराए हैं, के खिलाफ मोदी ने रत्ती भर कार्रवाई नहीं की. विदेशों से रिश्तों व विदेशी व्यापार समझौतों पर बुरा असर पड़ने का बहाना करके सारे नाम भी उजागर करने से मना कर दिया.

क्या नोटबंदी नकली नोटों के प्रचलन को बंद कर सकती है?

बिल्कुल नहीं. क्यों कि नोटबंदी के बाद बंद किए गए 500 और 1000 रुपए के नोटों की जगह नए 500 रुपए एवं 2000 रुपए के नोट आ गए हैं. यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि नोटबंदी के सप्ताह भर के भीतर ही 2000 रुपए के नकली नोट बाजार में आ गए हैं. इस मामले में रिजर्व बैंक ने खुद यह कबूल किया है कि 2000 के नए नोटों को बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा विशेषता के ही जारी किया जा रहा है. जाहिर है, सरकार को असल में नकली नोटों की कोई चिंता ही नहीं है.

कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान(आईएसआई) की रिपोर्ट के अनुसार कुल करेंसी का महज 0.02 प्रतिशत मूल्य के ही नकली नोट हैं. यानी कुल जाली नोटों का मूल्य सिर्फ 400 करोड़ रुपए है. इतनी छोटी राशि का अर्थव्यवस्था पर उतनी गंभीर असर नहीं पड़ने वाला है जितना नए नोटों को छापने पर पड़ेगा. क्योंकि 500 व 2000 के 223 करोड़ 60 लाख नए करेंसी नोटों को छापने के लिए करीबन 12 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह काम साल भर चलेगा. आईएसआई की रिपोर्ट में कभी भी नकली नोटों से निजात पाने के लिए नोटबंदी का सुझाव नहीं दिया गया था. फिर नकली नोटों के मामले को जिसकी जड़ मूलतया देश की शोषणमूलक कानून–व्यवस्था में है, नोटबंदी के लिए कारण बताना क्या उचित व सही है? कतई नहीं. यह तो बेईमानी भरा व धोखेबाजीपूर्ण कदम है.

नोटबंदी और भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार हमारे देश की शोषणमूलक आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है. नोटबंदी इसे समाप्त नहीं कर सकती है. सरकारें स्वयं इसे बढ़ावा देने में लगी रहती हैं. अपने आस्ट्रेलिया दौरे के समय मोदी ने अपने सबसे चहेते उद्योगपति गौतम अदानी को 17 नवंबर, 2014 के दिन 7 बिलियन डॉलर का खनन ठेका, एसबीआई से 1 बिलियन डॉलर का ऋण दिलाया है. मोदी ने गुजरात में अदानी को तटीय इलके में सस्ते में जमीन आबंटित करके 45 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा पहुंचाया. एक अनुमान के मुताबिक मोदी के आशीर्वाद प्राप्त 10–12 उद्योगपतियों के पास ही 'कालेधन' का आधा हिस्सा है. एक वीडियो फुटेज के मुताबिक भाजपा अध्यक्ष अमित शाह 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक 37 प्रतिशत कमीशन पर नोट बदलवाने के कारोबार में मशगुल थे.

पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के दौरान घोटालों की लहर थी तो अब भाजपा नेताओं के घोटाले एक के बाद एक और एक से बढ़कर एक उजागर हो रहे हैं. संप्रग सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपयों में तय राफाल विमान की कीमत को वर्तमान सरकार ने अनिल अंबानी के माध्यम से 1600 करोड़ तय किया है. मोदी की गुजरात सरकार ने रतन टाटा के सिर्फ 2 हजार करोड़ की नैनो कार परियोजना के लिए 30 हजार करोड़ रुपए सौंपा है. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना करते हुए मोदी सरकार ने वित्त बिल–2016 का अनुमोदन किया जिसके मुताबिक राजनीतिक पार्टियों व संस्थाओं को विदेशी कंपनियों द्वारा दी जाने वाली चंदा राशि 'फॉरिन कंट्रिब्यूशन रेग्युलेशन एक्ट 2010(एफसीआरए) के अंतर्गत नहीं आती है'. जन धन की बंदरबांट के खुले भ्रष्टाचार के ऐसे ढेरों मामलें हैं. शोषक–शासक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारें जन विरोधी नीतियों, निर्णयों व कानूनों के सहारे ही नहीं, बल्कि अपने ही बनाए कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं. 'कालेधन' को संचित करने के मुख्य तरीकों में से एक है, भ्रष्टाचार.

नोटबंदी से कैसे, किसे और क्या फायदा हुआ?

नोटबंदी से विदेशी बड़े पूंजीपति(बहुराष्ट्रीय / पारराष्ट्रीय कंपनियां), पूंजी निवेशक, बैंकर्स, अंबानी, अदानी, टाटा, बिड़ला, जिंदल, मित्तल, रूइया आदि देश के दलाल बड़े पूंजीपति बहुत खुश हैं. इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष(आईएमएफ), बिल गेट्स जैसे अरबपति, भारत के दलाल बड़े पूंजीपतियों के संगठन–फिक्की(एफआईसीसीआई), एसोचेम(एएसएसओसीएचएएम) और देश के बड़े औद्योगिक घरानों ने नोटबंदी का बढ़–चढ़कर स्वागत किया था.

नोटबंदी की घोषणा के बाद हालांकि सही आंकड़ों की घोषणा 30 दिसंबर तक सरकार ने नहीं की लेकिन एक अनुमान के मुताबिक करीबन चौदह लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा हो गए. अभी 31 मार्च बाकी है. यानी 'कालाधन' तो कुछ भी खत्म नहीं होगा या नाममात्र का. यह मान लिया जाना चाहिए कि जितना भी गैर कानूनी धन था, वह नोटबंदी के जरिए कानूनी हो गया है.

बैंकों में जमा यह राशि सस्ती ब्याज दरों पर अब देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले की जाएगी. यहां यह गौर करने वाली बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में बैंक ऋणों पर ब्याज दर में कटौती की और साथ ही बैंक डिपॉजिटों पर ब्याज दर में भी कटौती की. इससे कॉरपोरेट घरानों को आर्थिक संकट से उभारने की कोशिश में तेजी आएगी.

यह जगजाहिर है कि विगत 15 सालों में कर्ज के बोझ तले दबकर देश के 3 लाख से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की. बावजूद इसके किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी के लिए सरकार यह कहकर कतई तैयार नहीं हुई कि इससे बैंक दिवालिया हो जाएंगे. आम किसानों को फसल ऋण के लिए चप्पल घिसने तक बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता है और एक किश्त नहीं पटाने पर घर के दरवाजों की नीलामी करने बैंक और पुलिस–प्रशासनिक अधिकारी पहुंच जाते हैं. जबकि 2013–15 के बीच सरकार के कहने पर सार्वजनिक क्षेत्र के 20 वाणिज्यिक बैंकों ने करीबन 100 डिफॉल्टर कॉरपोरेट घरानों के 1,14,000 करोड़ रुपयों का ऋण माफ कर दिया है. ये बड़े घरानों के डूबत खातें हैं. वर्तमान में कॉरपोरेट कंपनियों के बैंक कर्ज का कुल बकाया राशि 13 लाख करोड़ रुपए हैं जिसे बैंकों द्वारा डूबत खाता / एनपीए माना जा रहा है और इसे वसूलने की बजाए माफ करने की साजिश चल रही है. सरकार और बैंकों ने जनता की संपत्ति पर डाका डालने वालों को बचाने का बढ़िया तरीका निकाला है. कॉरपोरेट घरानों के कर्ज को पहले एनपीए घोषित करो, फिर राइट ऑफ कर दो. जन धन को बैंकों में जमा करो. फिर से कर्जा दो.

बैंकों द्वारा कॉरपोरेट कंपनियों को दिए गए कर्ज का नजारा जरा देखें.

अनिल अंबानी–रिलायंस ग्रुप रु. 1,25,000 करोड़, अनिल अग्रवाल–वेदांता ग्रुप रु. 1,03,000 करोड़, शशि रूइया, रवि रूइया–एस्सार ग्रुप रु. 1,01,000 करोड़, गौतम अदानी–अदानी ग्रुप रु. 96,031 करोड़, मनोज गौर–जेपी ग्रुप रु. 75,163 करोड़, सज्जन जिंदाल–जेएसडब्ल्यू ग्रुप रु. 58,171 करोड़, जीएम राव–जीएमआर ग्रुप रु. 47,976 करोड़, एल मधुसूधन राव–लांको ग्रुप रु. 47,102 करोड़, वेणुगोपाल धूत–वीडियोकॉन ग्रुप रु. 45,405 करोड़, जीवीके रेड्डी–जीवीके ग्रुप रु. 33,933 करोड़. इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जन धन बैंकों से पूंजीपतियों की जेबों में कैसे पहुंचता है और वह उनकी निजी संपत्ति में कैसे तब्दील हो जाता है.

अब जरा कॉरपोरेट कंपनियों की करमाफी की कहानी देखें.

आयकर, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी आदि कॉरपोरेट करों को सरकारें बड़े पैमाने पर माफ करती हैं. 2013–14 बजट वर्ष में संप्रग सरकार ने कुल 5 लाख 32 हजार करोड़ के कॉरपोरेट करों को माफ किया जबकि 2014–15 बजट वर्ष में राजग सरकार ने 5 लाख 89 हजार करोड़ माफ किया. विगत 10 सालों में माफ किए गए कॉरपोरेट करों की कुल राशि 42 लाख करोड़ रुपए है.

सरकारें किसके हित में काम कर रही हैं, अंदाजा लगाना ज्यादा कठिन नहीं है.

एक बात और है, नोटबंदी से देश के अधिकांश लोग बैंकों से जबरन बांध दिए गए हैं. अब दसियों करोड़ जनता के बीच व उनके रोजमर्रा के लेन–देन बैंकों के जरिए ही होगा. बहुत बड़े पैमाने पर जमा राशि से बैंक पूंजी बढ़ी और बैंकों का कारोबार खूब चलेगा. बड़े पैमाने पर बैंकों को सेवाकर मिलेगा. इसके अलावा सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा.

आम जनता को अनगिनत तकलीफें

नोटबंदी की मार सबसे ज्यादा देश के गरीब, मध्य वर्गीय लोगों, दलितों, मजदूरों, रोज कमाने–खाने वालों जो सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, को झेलनी पड़ी. खासकर अंदरूनी इलाकों के आदिवासी बड़ी तकलीफ उठाने मजबूर हो गए. पचास दिनों में पैसे जमा करने व निकालने के लिए नित नए नियम बनाते व पाबंदियां लगाते हुए आम जनता को हलाकान किया गया. लोगों को अपने काम–धंधें छोड़कर बैंकों/डाक घरों का चक्कर लगाना व कई दिनों तक व कई घंटों तक लाइन में लगे रहना पड़ा. यहां गौर करने वाली बात यह है कि इन लाइनों में कहीं कोई मर्सीडीज, ऑडी नहीं दिखी. अंबानी, अदानी, रतन टाटा या और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं खड़ा दिखा.

गाय, बैल, बकरी, सुव्वर जैसे पालतू जानवारों, वनोपजों व फसलों को बेच कर, पेट बांधकर इकट्ठे किए गए रुपयों को जमा करने लोग जब बैंक गए तो बैंक अधिकारियों व पुलिस की पूछताछ, अपमानजनक व्यवहार, यहां तक की उनकी ईमानदारी पर भी सवालिया निशान लगाते हुए उनकी उंगलियों पर अमिट स्याही का निशान लगाना आदि का सामना करना पड़ा. उन्हें अपराधी के तौर पर देखा गया. संघर्षरत इलाकों में जनता खासकर आदिवासियों की गाड़ी कमाई को माओवादियों का पैसा बता कर पुलिस द्वारा जब्ती, उनकी गिरफ्तारी, उन्हें गंभीर यातनाएं देना आम बात हो गयी थी. चूंकि यहां की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ हैं इसलिए नोटबंदी के नियम कायदों से वे अनजान हैं. इसके चलते नोट बदलाना और मुश्किल बन गया था. कइयों ने तो अपने नोट बदलना ही छोड़ दिया था.

पुराने नोट बदलने के दौरान बैंकों के सामने लाइन लगने के लिए हुई भगदड़ों में, पैसे की किल्लत के चलते सही समय पर इलाज न मिल पाने, पहले से तय शादियों में आई अड़चनों को न झेल पाने की वजह से कुल मिलाकर नोटबंदी के चलते लगभग 125 से ज्यादा लोगों की दुखद मौत हुई. रिकॉर्डों में दर्ज न होने वाली मौतों का कोई हिसाब नहीं है. ये सारी मौतें दरअसल सरकार द्वारा की गई हत्याएं ही हैं.

चूंकि असंगठित रोजगार और अनौपचारिक क्षेत्र देश की कुल अर्थव्यवस्था का 90 प्रतिशत है, यह कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत पैदा करता है, नोटबंदी से और समय पर नोट बदली न होने के कारण इन्हें पैसों की भारी किल्लत झेलनी पड़ी. ऐसे में उनकी क्रय शक्ति बुरी तरह प्रभावित हुई. नतीजतन जनता को अपनी दैनिक जरूरतों को निपटाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं. खासकर रोजी मजदूरी पर निर्भर करोड़ों लोगों को चावल, दाल, साग–सब्जी आदि रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और भूख–प्यास का शिकार हो रहे हैं. शहरों में विनिर्माण सहित अन्य कई छोटे–मोटे कार्य बंद होने से उन पर निर्भर हजारों परिवारों की रोजी–रोटी छिन गयी. सिर्फ हैदराबाद शहर से नवंबर के मध्य तक ही 50 हजार परिवार शहर छोड़कर वापस चले गए थे.

नोटबंदी से छोटे व्यापार व उद्योगों को बड़ा धक्का लगा है. औद्योगिक उत्पादन पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है. नोटबंदी से कृषि क्षेत्र का और भी बुरा हाल हुआ है. देश की कुल आबादी का 67 प्रतिशत गांवों में है. इसमें से 49 प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और इसका 97 प्रतिशत अनौपचारिक है. यानी सारा लेन–देन नकदी से होता है. किसानों को एक तरफ अपने खरीफ फसल बेचने पर भी नकदी नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ इससे खाद, बीज की खरीदी न कर पाने के चलते रबी की बुआई करने में दिक्कत. साफ है यह आगामी वर्ष के कृषि उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित करेगा. कुल मिलाकर जीडीपी वृद्धि दर नीचे चली जाएगी और कृषि क्षेत्र पर इसका दूरगामी असर अवश्य पड़ेगा.

जबरन नकद रहित अर्थ व्यवस्था की ओर

आईएमएफ और विश्व बैंक की सिफारिशों के अनुरूप ही नकदी पर आधारित देश की अर्थ व्यवस्था को नकद रहित या डिजिटल अर्थ व्यवस्था की ओर जबरन ढकेला जा रहा है. बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तकनीकी मशीनरियों पर आधारित होकर इसे अमल में लाया जा रहा है. विभिन्न मोबाइल एप्स, बैंक एप्स, पेटीएम, ई–वैलेट(इलेक्ट्रॉनिक बटुए) एवं अन्यान्य तरीकों का बढ़ा–चढ़ाकर प्रचार करते हुए नगद रहित लेन–देन को बढ़ावा देने एड़ी–चोटी का जोर लगाया जा रहा है. अत्याधुनिक व विकसित अमेरिका सहित अन्य तमाम पूंजीवादी–साम्राज्यवादी देशों में भी पूरी तरह नकद रहित अर्थ व्यवस्था को लागू करना संभव नहीं हो सका है तो भारत जहां अभी भी 40 प्रतिशत निरक्षर हैं,

62 प्रतिशत आबादी गांवों में हैं, 2 लाख एटीएम मशीनों का 70 प्रतिशत और बैंकों का 65 प्रतिशत शहरी इलाकों में मौजूद हैं, इंटरनेट की सुविधा निम्न स्तर पर है, में इसे जबरन अमल करने की कोशिश का कोई औचित्य ही नहीं है. इतना ही नहीं यह बेईमानी भरा कदम है और गौर करने वाली बात यह है कि इसका इस्तेमाल कोई मुफ्त नहीं है. यह सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी को 1 से 4 प्रतिशत के बीच सेवा कर देना होता है जोकि आम आदमी के लिए बड़ी कीमत है.

माओवाद, कश्मीरी जनता की आजादी की लड़ाई, पूर्वोत्तर की राष्ट्रीयताओं के आन्दोलन–नोटबंदी से बेअसर आगे बढ़ेंगे!

मोदी का यह कहना कि माओवाद, कश्मीरी जनता का आन्दोलन और पूर्वोत्तर के राष्ट्रीयताओं के आन्दोलन नोटबंदी से कमजोर हो जाएंगे, बेबुनियाद, झूठी व धूर्ततापूर्ण बात है. ये तमाम आन्दोलन फंड्स से या फंड्स के लिए न निर्मित है और न ही संचालित है. इसलिए नोटबंदी से इन आन्दोलनों खासकर माओवादी पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. माओवादी पार्टी उत्पीड़ित जनता की पार्टी है और उनकी सेवा करने वाली है. हां, यह सही है कि नोटबंदी से आम जनता को अपार कठिनाइयां हो रही हैं. इसी मायने में जनता की तकलीफों को माओवादी पार्टी अपनी तकलीफें समझती है. अपनी तमाम जरूरतों के लिए उत्पीड़ित वर्गों की जनता पर निर्भर माओवादी पार्टी के लिए फंड्स नहीं, जनता ही निर्णायक महत्व की है. वह दुश्मन को प्रधान स्रोत के रूप में इस्तेमाल करती है और जनता पर निर्भर करके सब कुछ हासिल कर सकती है. इसलिए नोटबंदी के जरिए माओवादी पार्टी व क्रांतिकारी आन्दोलन को कमजोर करने या खत्म करने के मोदी का दिवांस्वप्न कभी पूरा नहीं होगा.

विमुद्रीकरण का विश्लेषण क्या बताता है?

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी(सीएमआईई) के नवंबर, 2016 के अध्ययन–'ट्रेंजेक्शन कॉस्ट ऑफ डीमॉनिटाइजेशन' के अनुसार नोटबंदी के फैसले की वजह से देश को 50 दिनों में कुल ट्रेंजेक्शन कॉस्ट के रूप में 1. 284 लाख करोड़ रुपए की कीमत अदा करनी होगी. नए नोट छपाई खर्च 12 हजार करोड़ इसमें जोड़े तो विमुद्रीकरण की कुल कीमत 1.404 लाख करोड़ बैठती है. जबकि विमुद्रीकरण के जरिए उगाही गयी कुल राशि 38.7 हजार करोड़ रुपए मात्र है. यानी सीधा–सीधा 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा घाटा. साथ में आम लागों को हुई परेशानी और असुविधा, कारोबारी नुकसान, कार्य के घंटों की हानि एवं अन्य सामाजिक कीमतें सो अलग. यह है, नोटबंदी का तात्कालिक नतीजा. वहीं दीर्घकालिक नतीजे के रूप में आने वाले सालों में जीडीपी विकास दर में कमी जिसे बजट–2017 पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जैट्ली ने स्वीकार भी किया, देश की अर्थव्यवस्था का मंदी में पहुंचना अपरिहार्य है. यह है, मोदी के गिनाए नोटबंदी के तीन कारणों की असलियत.

विमुद्रीकरण बनाम विपक्षी दल

कांग्रेस, सपा, बसपा, सीपीआई, सीपीआईएम, राजद, आप आदि विपक्षी संसदीय राजनीतिक पार्टियां नोटबंदी के चलते जनता के सामने उत्पन्न गंभीर समस्याओं को लेकर सरकार की कड़ी आलोचनाएं करती रहीं. लेकिन किसी ने नोटबंदी के पीछे की सच्चाई व साजिश को उजागर करने, सरकार के खिलाफ निर्णायक संघर्ष करने की कोशिश नहीं की. क्योंकि ये तमाम शासक वर्गीय पार्टियां एक ही थैली के चट्टे–भट्टे हैं.

अविराम संघर्ष, आज के वक्त की मांग है!

विमुद्रीकरण 'काली' अर्थव्यवस्था को जन्म देने वाले मूल कारणों को खत्म नहीं कर सकता है. 'कालाधन', भ्रष्टाचार, जाली करेंसी शोषणमूलक, पूंजीवादी सड़ी–गली अर्थव्यवस्थाओं का अभिन्न अंग हैं. चूंकि ये व्यवस्थागत समस्याएं हैं, इसलिए इनका समाधान भी व्यवस्था को बदलने में है. क्रांतिकारी आन्दोलन के जरिए निर्मित होने वाले शोषण विहीन समतामूलक समाज व्यवस्था में ही इनका अंत संभव है.

मोदी सरकार की नोटबंदी धोखाधड़ी है, वादाखिलाफी है, बेईमानी है. उसका फैसला नाजायज, जन विरोधी व देश द्रोही है. सिर्फ नोटबंदी ही नहीं उसके तमाम फैसले इसी श्रेणी के हैं. इसलिए मजदूरों, किसानों, मध्यम वर्गीय लोगों, आदिवासियों, दलितों व अन्य उत्पीड़ित जातियों व तबकों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, छात्र–युवाओं, बुद्धिजीवियों, लेखक–कलाकारों, मीडियाकर्मियों, वकीलों, शिक्षक–कर्मचारियों, बेरोजगारों, जनवादी, प्रगतिशील, देशभक्त संगठनों, व्यक्तियों व व्यापक जन समुदायों को एकजुट हो व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाकर शोषक–शासक वर्गों व उनका प्रतिनिधित्व करने वाली ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी संघ परिवार की भाजपा नीत केंद्र, राज्य सरकारों की नोटबंदी सहित तमाम जन विरोधी फैसलों के खिलाफ फौरन जुझारु आन्दोलन का संचालन करना चाहिए और इस शोषणमूलक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की ओर आगे बढ़ना चाहिए.

दिनांक–10 नवंबर, 2016

नंदिनी सुंदर एवं अन्य बुद्धिजीवियों के खिलाफ फर्जी केस दायर करने की कड़ी निंदा करें!

छत्तीसगढ़ की जन विरोधी फासीवादी भाजपा सरकार के मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस का तत्कालीन सरगना आईजी एसआरपी कल्लूरी ने इस साजिश के तहत कि बस्तर में जारी पुलिसिया दमन व आतंक की सच्चाई से बाहर की दुनिया अवगत न हो, कुछ समय पहले सुकमा जिले के कुम्माकोलेंग व नामा गांवों का दौरा करने वाले जांच दल जिसमें जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद, टीआईएसएस के विनीत तिवारी, सीपीआई(एम) के राज्य सचिव संजय पराते शामिल थे, के खिलाफ हत्या का फर्जी मामला दर्ज करवाया. हमारी पार्टी इस अलोकतांत्रिक, आतंकी, साजिशाना कुकृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करती है और इस साजिश के खिलाफ आवाज बुलंद करने, सड़क पर उतरने राज्य व देश की तमाम जनवादी, प्रगतिशील ताकतों, आदिवासी–गैर आदिवासी सामाजिक संगठनों, मानवाधिकार संगठनों, लेखक–कलाकारों, बुद्धिजीवियों, विपक्षी राजनीतिक दलों, वामपंथी ताकतों सहित दुनिया के बुद्धिजीवियों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से अपील करती है.

अभी यह बात सबके जेहन में ताजा ही होगी कि कुम्माकोलेंग व नामा गांवों के ग्रामीणों के नाम पर नंदिनी सुंदर के खिलाफ पुलिस थाने में माओवादियों को मदद देने व गांव में प्रस्तावित पुलिस थाने का विरोध करने हेतु ग्रामीणों पर दबाव डालने की झूठी शिकायत लिखवायी गयी थी जिसका जनपक्षधर पत्रकारों ने भण्डाफोड़ किया था. दरअसल प्रोफेसर नंदिनी सुंदर बस्तर की जनता पर जारी सरकारी दमन, महिलाओं पर सशस्त्र बलों द्वारा लगातार बढ़ते यौन अत्याचारों के खिलाफ लंबे समय से आवाज उठाती आ रही हैं. यह जगजाहिर है कि फासीवादी सैनिक, सांगठनिक दमन अभियान सलवा जुडुम के विरोध में दायर उनकी ही याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडुम व एसपीओ व्यवस्था को बंद करने का राज्य सरकार को आदेश दिया था. हालांकि सरकार ने एसपीओ व्यवस्था का नाम बदलकर उसे छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक पुलिस बल के नाम पर पुनर्गठित किया है. यहां यह भी याद दिलाना गैर वाजिब नहीं होगा कि उनकी ही याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में सशस्त्र बलों द्वारा शाला व आश्रम भवनों को अपना अड्डा न बनाने व तुरंत खाली करने का आदेश दिया था. छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह आश्वासन दिया था कि 4 महीनों के भीतर वह शाला भवनों को खाली करायेगी. लेकिन आज तक इस आदेश का बस्तर व राजनांदगांव जिलों में पूरी तरह पालन नहीं हुआ है. सुप्रीम कोर्ट की यह घोर अवमानना है.

ताडिमेट्ला आगजनी कांड पर हाल ही में सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को यह रिपोर्ट सौंपी कि ताडिमेट्ला, मोरपल्ली व तिम्मापुर गांवों के 252 घरों को आग के हवाले करने वाले कोई और नहीं, सरकारी सशस्त्र बल ही थे. इस रिपोर्ट के आधार पर नंदिनी सुंदर की ही याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि दोषियों पर छत्तीसगढ़ सरकार तुरंत कार्रवाई करे. छत्तीसगढ़ सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन करने का ढोंग करते हुए 8 एसपीओ को निलंबित किया है जोकि हास्यास्पद ही नहीं बल्कि पीड़ित आदिवासी परिवारों के साथ भद्दा मजाक है. दरअसल ताडिमेट्ला कांड मुख्य मंत्री रमण सिंह, राज्य के गृह मंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, आईजी कल्लूरी, एवं सीआरपीएफ के आला अधिकारियों की सुनियोजित साजिश था जिसके द्वारा आदिवासी जनता को आतंकित करने की कोशिश की गयी. यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि ताडिमेट्ला कांड को अंजाम देने वाले संयुक्त सशस्त्र बलों का कमांडर–इन–चीफ स्वयं मुख्य मंत्री रमण सिंह हैं. इसलिए असली दोषी व सजा के हकदार तो वो और पुलिस–प्रशासन के आला अधिकारी ही हैं. जबकि सिर्फ 8 एसपीओ को निलंबित कर पूरे मामले को रफा–दफा किया गया है.

नंदिनी सुंदर एवं अन्य के खिलाफ एफआईआर दायर करने को उपरोक्त घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखना व समझना होगा.

सरकार के नाजायज कार्यों व जन विरोधी नीतियों सहित तमाम किस्म के दमनकारी हथकंडों के खिलाफ आवाज उठाने वाले, दमन की सच्चाई की जांच करके, उन्हें उजागर करने वाले जनपक्षधर पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिला संगठनों की कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं यहां तक कि विपक्षी दलों–आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीआई(एम), कांग्रेस के नेताओं जैसे सोनी सोढ़ी, मनीष कुंजाम, संजय पराते आदि को निशाना बनाकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं. अब ऐसे लोगों पर आपराधिक मुकदमें दर्ज करने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों की देखरेख में पुलिस, डीआरजी बलों द्वारा विपक्षी राजनेताओं, सामाजिक, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, प्रगतिशील–जनवादी बुद्धिजीवियों का खुलेआम पुतला दहन, हिटलरशाही का ही परिचायक

है. यहां तक कि सलवा जुडुम के कुख्यात सरगना महेंद्र कर्मा की पत्नि देवती कर्मा पर भी माओवादी समर्थक होने का आरोप लगाकर केस दर्ज करने की पुलिस धमकी दे रही है.

जन विरोधी मुखियाओं, लंपट लोगों को इकट्ठा करके कल्लूरी ने सलवा जुडुम की तर्ज पर कुम्माकोलेंग, नामा, सौतनार आदि गांवों में टंगिया समिति का गठन करवाया है जिसका नेतृत्व जन विरोधी सामनाथ बघेल के हाथों में सौंप दिया गया था. जैसे नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है, टंगिया संगठन कोई शांति संगठन नहीं है. कुम्माकोलेंग, नामा एवं आसपास के गांवों के ग्रामीणों, माओवादी मददगारों पर हमले करके दहशत फैलाना उस संगठन का मूल मकसद है. ऐसी स्थिति में पीड़ित जनता की मांग पर सामनाथ बघेल को पीएलजीए ने विगत 4 नवंबर को मौत की सजा दी.

यह जगजाहिर है कि हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आन्दोलन, विस्थापन विरोधी जन आन्दोलनों, जनवादी–प्रगतिशील आन्दोलनों के सफाए के लिए तद्वारा देश के बहुमूल्य खनिज संसाधनों को देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने के लिए ही 2009 से प्रारंभ ऑपरेशन ग्रीन हंट जोकि असल में जनता पर जारी नाजायज जंग के सिवाय और कुछ नहीं है, के हमलें तेज कर दिए गए हैं. इन हमलों के भयावह रूप आज दण्डकारण्य खासकर बस्तर में देखने को मिल रहे हैं. झूठी मुठभेडों का सिलसिला तेज कर दिया गया है. महिलाओं का भयानक यौन उत्पीड़न बेरोकटोक जारी है. महिलाओं का सामूहिक बलात्कार व हत्या की सरकारी सशस्त्र बलों को खुली छूट दी गयी है. अपने ही कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए डीआरजी बलों सहित गोपनीय सैनिकों, सहायक आरक्षकों को यह नारा दिया गया है, 'एक लाश लाओ! एक आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाओ!'. साथ ही लाखों का ईनाम भी. कल्लूरी ने हाल ही में खुलेआम घोषणा की कि एक के बदले 12 को मारेंगे. बेकसूर आदिवासियों को मार गिराने व ईनामी माओवादी घोषित करने का खेल बस्तर में बदस्तूर जारी है.

सरकार की शह पर पुलिस व अर्ध सैनिक बल बेहिसाब राशि खर्च करते हुए, जन विरोधी व आन्दोलन के द्वारा दण्डित लोगों व लंपट तत्वों को लालच देकर, कई और तरीकों से गांवों में मुखबिर जाल बना रहे हैं. इनकी सूचनाओं पर आधारित होकर हमारे छापामार दस्तों पर सैकड़ों सशस्त्र बलों द्वारा हमले करवाए जा रहे हैं. ऐसी स्थिति में अनिवार्य रूप से कुछ ऐसे मुखबिरों जो कई बार समझाने के बावजूद नहीं सुधरते हैं, मुखबिरी नहीं छोड़ते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए पुलिस का सीधा सहयोग करने से बाज नहीं आते हैं, को जन अदालत में जनता की मांग व फैसले पर अमल करते हुए पीएलजीए द्वारा मौत की सजा दी जाती है. जनता, पार्टी व क्रांतिकारी आन्दोलन के बचाव में ऐसा कदम उठाना पड़ता है. मुखबिरों को जान से न मारने की हमसे अपील करने वाले बुद्धिजीवियों से हमारी पार्टी अपील व आग्रह करती है कि वे उपरोक्त स्थिति को समझने की कोशिश करें. हमारी पार्टी राजनीतिक व वैचारिक विरोध के लिए किसी पर कार्रवाई नहीं करती है. राजनीतिक बहस–मुबाहिसों में विश्वास करती है. उत्पीड़ित जनता को पार्टी की रचनात्मक आलोचना करने का अधि ाकार देती है. पार्टी स्वयं को स्वेच्छा से जनता की निगरानी में रखती है.

हमारी पार्टी जनता का आह्वान करती है कि वह भाजपा के ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी शासन द्वारा जारी राजकीय दमन के खिलाफ, असली लोकतंत्र के लिए व्यापक, जुझारु, संगठित जन संघर्ष के निर्माण के रास्ते में आगे बढ़ें.

विकल्प

प्रवक्ता

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट

पार्टी (माओवादी)

झूठे आत्मसमर्पण का नजारा देखें

सुकमा जिले में अक्टूबर 3 को पुलिस के सामने 350 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, बीजापुर जिले में वनमंत्री महेथ गागड़ा के सामने मुख्य धारा से जुड़ने 18 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, सुकमा जिला के तोंगपाल, फुलबगड़े थाना के अंतर्गत 450 नक्सलियों का आत्मसमर्पण. ये खबरें मीडिया में, खासकर टीवी चैनलों में खूब चली. जबकि ये सभी लोग ग्रामीण थे। इन्हें पुलिस डरा–धमकाकर जबरदस्ती थाने में ले जाकर इनका आत्मसमर्पण दिखाया गया है. पुलिस की मदद से गांवों में कुछ जनविरोधी मुखिया, भाजपा नेतागण, वनमंत्री महेथ गागड़ा के चेले ग्रामीणों को आतंकित कर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर रहे हैं. पुलिस, भाजपा मिलकर आए दिन बीजापुर, भैरमगढ़, कुटरू, सुकमा, गादीरास, तोंगपाल, पालनार, दोरनापाल, कोंटा एवं अन्य इलाकों में जबरदस्ती लोगों को इकट्ठा करके आत्मसमर्पण करने दबाव बनाते हैं। नहीं तो जान से मार देने, गांवों को जला कर राख कर देने की धमकियां देते हैं.

दिनांक–25 नवंबर, 2016

नगरनार इस्पात संयंत्र के विनिवेशीकरण एवं एनएमडीसी की प्रस्तावित पाइप लाइन के खिलाफ आन्दोलन को तेज करने की अपील!

केंद्र की जन विरोधी भाजपा सरकार द्वारा बस्तर के नगरनार स्थित एनएमडीसी के निर्माणाधीन इस्पात संयंत्र को विनिवेशीकरण के नाम पर देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों–अदानी या टाटा को कौड़ियों के भाव बेचने की साजिश की हमारी पार्टी कड़ी निंदा व विरोध करती है. उक्त संयंत्र को बेचने तथा नगरनार स्टील प्लांट में स्लरी पाइप लाइन बिछाने के खिलाफ आन्दोलनरत एनएमडीसी के मजदूरों, किसानों व तमाम जनता का तहे दिल से पूर्ण समर्थन करती है और आन्दोलन को तेज करने की अपील करती है.

इस बात से सभी वाकिफ हैं कि नगरनार में अपने इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए एनएमडीसी ने करीबन 300 आदिवासी किसानों की उपजाऊ जमीन को जोर जबरदस्ती करके अधिग्रहित किया था. अभी तक सभी प्रभावित किसानों को न ही पर्याप्त मुआवजा मिला है और न ही वादे के मुताबिक प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक व्यक्ति को संयंत्र में नौकरी. संयंत्र का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ है, कि अब सरकार अपनी जन विरोधी, आदिवासी विरोधी व पूंजीपतिपरस्त चरित्र का नंगा परिचय देते हुए संयंत्र को अदानी या टाटा के हाथों सौंपने जा रही है. दरअसल पूंजीपतियों के बड़े कारखानों के लिए अपनी जमीनें न देने के किसानों के संकल्प को देखते हुए एनएमडीसी व केंद्र सरकार ने साजिशाना तरीका अपनाया था जिसके तहत स्वयं एनएमडीसी द्वारा संयंत्र निर्माण की घोषणा की गयी थी. अब चूंकि संयंत्र के लिए जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है और संयंत्र निर्माणाधीन है, इसे बड़े पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है.

ज्ञात रहे 9 मई, 2015 को प्रधान मंत्री मोदी ने दंतेवाडा में एनएमडीसी द्वारा प्रस्तावित बचेली से नगरनार तक 138 किमी लंबी स्लरी पाइप लाइन का बिना ग्राम सभाओं की अनुमति के उद्घाटन किया था. यह पाइप लाइन करीब 4 हजार करोड़ रुपए की है और बस्तर व दंतेवाडा के 60 ग्राम पंचायतों के 100 गांवों से गजरेगी. इससे 10 से 14 टन अयस्क का परिवहन प्रस्तावित है. ग्राम सभाओं में जनसुनवाई की प्रक्रिया को सरकार अब शुरु करने जा रही है जिसका माड़पाल, मारकेल, आमागुड़ा, खूंटपदर, कुरंदी, बिलोरी, नकटी सेमरा, नगरनार सहित इलाके के कइयों गांवों के लोग विरोध कर रहे हैं. प्रस्तावित स्लरी पाइप लाइन से बस्तर का भूजल स्तर काफी घट जाएगा जोकि जन जीवन एवं पर्यावरण के लिए घातक साबित होगा. नगरनार इस्पात संयंत्र के विनिवेशीकरण की केंद्र सरकार व एनएमडीसी की कोशिशों से यह साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि उक्त स्लरी पाइप लाइन दरअसल देश के दलाल बड़े पूंजीपतियों खासकर मोदी के चहेतों को सस्ते में लौह अयस्क उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्यित है. आम जनजीवन की कीमत पर पूंजीपतियों को मनमाफिक फायदा पहुंचाने की सरकारी नीतियों का अपरिहार्य परिणाम है, यह.

एनएमडीसी के नगरनार इस्पात संयंत्र को बेचने व स्लरी पाइप लाइन के विरोध में संघर्षरत नगरनार इलाके की जनता व एनएमडीसी मजदूरों से आन्दोलन को तेज करने का हमारी पार्टी आह्वान करती है और इस आन्दोलन का समर्थन व सहयोग करने, सड़क पर उतरने, सरकार के इन नाजायज कार्यों व जन विरोधी नीतियों सहित तमाम किस्म के दमनकारी हथकंडों के खिलाफ आवाज उठाने राज्य व देश की तमाम जनवादी, प्रगतिशील ताकतों, आदिवासी–गैर आदिवासी सामाजिक संगठनों, मानवाधिकार संगठनों, विपक्षी राजनीतिक दलों, वामपंथी ताकतों से अपील करती है.

विकल्प
प्रवक्ता

मार्क्सवाद के महान शिक्षक एवं चीनी क्रांति के नेता कॉमरेड माओ त्से–टुंग अमर रहे!
(जन्मः दिसंबर 26, 1893
निधनः सितंबर 9, 1976)

कॉमरेड सर्वहारा वर्ग के वर्ग संघर्ष के दांव–पेंचों को चीनी क्रांति की ठोस परिस्थितियों के अनुरूप वैज्ञानिक ढंग से क्रियान्वयन किया. नव जनवादी क्रांति में संयुक्त मोर्चा, सशस्त्र संघर्ष व पार्टी निर्माण, इन तीनों अद्भुत हथियारों का बढ़िया समन्वय किया.

उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा व सशस्त्र संघर्ष, ये दोनों दुश्मन को हराने के दो मुख्य हथियार हैं. संयुक्त मोर्चा सशस्त्र संघर्ष के संचालन के लिए हो. संयुक्त मोर्चा, सशस्त्र संघर्ष इन दोनों हथियारों का इस्तेमाल करके दुश्मन के किलाओं को ध्वस्त करने वाली वीरयोधा ही पार्टी है. ये तीनों इस तरह एक दूसरे के साथ संबंध में रहते हैं.

नस्लीय भेदभाव व उत्पीड़न
अमेरिकी साम्राज्यवाद के चेहरे पर अमिट दाग

जैसा कि कुछ गोरे अमेरिकी कहते हैं, क्या अमेरिका में नस्लभेद समाप्त हो गया है? दिल दहला देने वाली इन घटनाओं पर नजर डालें तो जवाब खुद–ब–खुद मिल जाएगा.

जुलाई, 2016 के पहले सप्ताह में मिन्नासोटा (मिनियापोलिस) में अपनी मित्र के साथ कार में सवार एक आफ्रीकी–अमेरिकी युवक को रोककर, एक पुलिस जवान ने लाइसेंस दिखाने कहा था. लाइसेंस के लिए युवक ने जैसे ही जेब में हाथ डाला पुलिस जवान ने उसकी कनपटी पर गोली मारकर उसकी हत्या की. लूसियाना के पास एक कार पार्किंग जगह पर कुछ बेचने के संदेह में पुलिस ने दो आफ्रीकी–अमेरिकी युवकों की गोली मारकर हत्या की थी. मिस्सोरी राज्य के फेरग्यूसन शहर में 18 वर्षीय मिशेल ब्राउन को फुटपाथ की बजाए सड़क पर चलने के कारण गोरे पुलिस जवान ने 9 अगस्त, 2014 को गोली मार दी थी. ब्राउन की हत्या के खिलाफ में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में शामिल 90 साल के वृद्ध एपस्टीन की पुलिस ने बेदम पिटाई की थी. ब्राउन की हत्या के दो दिन बाद ही कालिफोर्निया में एक विक्षिप्त काले व्यक्ति की पुलिस ने गोली मारकर हत्या की. जुलाई, 2014 में एरिक गार्नर नामक काले युवक की पुलिस ने हत्या की थी. फरवरी 26, 2012 को फ्लोरिडा के शानफर्ड में 17 वर्षीय काले नस्ल के किशोर ट्रेवान मार्ट की जार्ज जिम्मरमैन नामक गोरे साइबरहुड वाचमैन ने गोली मारकर हत्या की.

अमेरिकी सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के ही मुताबिक 1 जनवरी से अक्टूबर, 2012 के बीच 120 महिला और पुरुषों की पुलिस और सुरक्षा गार्डों द्वारा हत्या की गयी. 2006–12 के बीच हर सप्ताह दो आफ्रीकी–अमेरिकी लोग गोरे अमेरिकी पुलिस अधिकारियों के हाथों मारे गए थे. 2015 में 102 निहत्थे व किसी न किसी हथियार से लैस 30 काले युवकों की छोटे–छोटे अपराधों के बहाने गोरे पुलिस वालों ने गोली मारकर हत्या की. ऑपरेशन घेट्टो स्टॉर्म के अनुसार अमेरिका में पुलिस द्वारा हर 28 घंटों में एक काला व्यक्ति मार दिया जाता है. अमेरिका में होने वाली कुल हत्याओं में 50 प्रतिशत काले नस्ल के लोगों की ही हैं.

ये हत्याएं कोई दुर्घटना नहीं हैं, न ही उपद्रवी पुलिस वालों की कार्रवाइयां हैं. काले लोगों के खिलाफ घातक ताकत का इस्तेमाल करना संयुक्त राज्य में मानक व्यवहार बन गया है. कानूनन गठित व्यवस्था के जरिए पुलिसिंग के नाम पर काले नस्ल के लोगों पर झूठे आरोप मढ़कर गोली मारना आम हो गया है. काले नस्ल के लोगों पर अघोषित युद्ध जारी है. पुलिस एवं न्याय व्यवस्था दोनों सांठगांठ के साथ इन हत्याओं की परंपरा को जारी रखी हुई हैं. न्यायालयों के फैसलें गोरे नस्ल वालों के अनुकूल ही दिए जाते हैं. 2012 में काले नस्ल के 313 लोगों का कत्ल हुआ था जबकि सिर्फ 10 गोरे पुलिस अधिकारियों और 16 सुरक्षाकर्मियों पर ही मुकदमें दर्ज किए गए हैं. ट्रेवान मार्ट के हत्यारे जिम्मरमैन के खिलाफ जनता के व्यापक दबाव के बाद केस दायर किया गया था लेकिन बाद में जुरी ने उन्हें निर्दोष घोषित किया था. पिपुल्स पवर असेंब्ली के आह्वान पर लॉस एंजेल्स से लेकर न्यूयार्क तक विरोध प्रदर्शनों की लहर उमड़ पड़ी. इस तरह के ढेरों उदाहरण हैं जिनमें आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया है. हालांकि जन विरोध व काले लोगों के जबर्दस्त आन्दोलनों के दबाव में आकर ग्राहम बनाम कारन के मामले में 1980 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि सिर्फ दो ही संदर्भों में–अपनी आत्मरक्षा, अपराधियों द्वारा किसी और की जान को फौरन खतरा उत्पन्न होने की स्थितियों में ही पुलिस गोली मार सकती है. वह भी अपराधियों को इस तरह घायल करें कि वो भाग न सके. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हमेशा धज्जियां उड़ती रहती हैं और कोर्ट मूक दर्शक बना रहता है.

पुलिस हत्याओं के खिलाफ जन उभार व प्रतिरोध

ब्राउन की हत्या के बाद पुलिस के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा. अश्रु गैस के गोलों, रबर बुलेटों की परवाह किए बगैर हत्यारे पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करके सजा दिलाने की मांग पर 100 से ज्यादा जुझारु प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनों में गोरे युवक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए. बोस्टन, डल्लास, न्यूयार्क, ओकलैण्ड, लॉस एंजेल्स, फेरग्यूसन आदि शहरों में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था. नस्लीय भेदभाव का शिकार होकर असुरक्षा, आत्महीनता के साथ काले लोग जब भी अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब उन पर सरकार अमानवीय दमन अमल करती है. ''दमन से प्रतिरोध बढ़ता है'', को सच साबित करते हुए जुलाई, 2016 के दूसरे सप्ताह में डल्लास शहर में पांच गोरे पुलिस अधिकारियों को शासन–प्रशासन व पुलिस के रवैये से खिन्न एक आफ्रीकी–अमेरीकी युवक ने गोली मार दी. कुछ दिन बाद लूसियाना के बेटनरोग में पुलिस केंद्र कार्यालय से एक मील दूरी पर एक और आफ्रीकी–अमेरीकी युवक ने तीन गोरे पुलिस अधिकारियों को गोली मार दी.

इस तरह के प्रतिरोध के भविष्य में बढ़ने की संभावना अधिक है.

उपरोक्त घटनाओं के बाद काले लोगों पर बढ़ते हमलों के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका में 'ब्लैक लाइव्ज मैटर' (काली जिंदगियां कीमती हैं) नामक एक उभरता नया मानवाधिकार आन्दोलन सुर्खियों में आया है. अभी इसका सांगठनिक ढांचा बना नहीं है. देश भर के काले दिलजलों का आन्दोलन है, यह. ट्रेवान मार्ट की हत्या के मामले में गोरे जार्ज जिम्मरमैन को कोर्ट द्वारा निर्दोष ठहराने के बाद उभरे जन विरोध के दौरान एक सोशल मीडिया ग्रुप के रूप में 'ब्लैक लाइव्ज मैटर' आन्दोलन 2013 में शुरु हुआ था. इसे काला राष्ट्रीयता की चेतना एवं दुनिया के दमित लोगों के आन्दोलनों की स्फूर्ति के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है. 'फेरग्यूसन यहां है' बैनर तले ब्राजिल के साओ पौलो में 'ब्लैक लाइव्ज मैटर' के समर्थन में हजारों लोगों ने 18 दिसंबर, 2014 को भाईचारा रैली आयोजित की थी. यह रैली काले समुदायों के खिलाफ व्यवस्थागत पुलिस हिंसा, बढ़ती हत्याओं, कालों पर घटित अपराधों के मामलों में न्यायालयों द्वारा दिए जाने वाले अन्यायपूर्ण फैसलों के खिलाफ प्रदर्शित आक्रोश था.

विकृत गोरी चेतना

अमेरिका में रह रहे चीनियों, भारतीयों, मुसलमानों के खिलाफ यह कहते हुए कि इनके चलते ही अमेरिकी युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने गोरे युवओं को अपने चुनावी प्रचार के दौरान भड़काया था. काले युवाओं व बुद्धिजीवियों में जागी चेतना–ब्लैक लाइव्ज मैटर के खिलाफ में ऐसे ही युवा यहां–वहां 'व्हाइट लाइव्ज मैटर' प्ल काड्र्स प्रदर्शित कर रहे हैं. अमेरिकी प्रतिक्रियावादी मीडिया 'ब्लू लाइव्ज मैटर'(नीली यानी पुलिस की जिंदगियां कीमती हैं) नामक कृत्रिम आन्दोलन पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहा है. हालांकि इस पर अमेरिका की जनवादी–प्रगतिशील ताकतें ध्यान नहीं दे रही हैं. लेकिन अमेरिकी सिरफिरे युवाओं जो ट्रंपनुमा विकृत गोरी चेतना से लैस हैं, द्वारा हाल ही में भारतीय मूल के लोगों की हत्याएं न केवल चिंताजनक हैं बल्कि अमेरिकी राज्यसत्ता द्वारा रंगभेद को बढ़ावा देने की कोशिशों के नतीजे के रूप में देखा जा सकता है जिसका दुनिया भर में कड़ा विरोध हो रहा है.

काले लोगों की दुस्थिति

अमेरिकी समाज में नस्लीय विवक्षा को कम करने की कोशिश की बजाए अमेरिकी शासक वर्ग उल्टे उसे बढ़ावा देते आ रहे हैं. काले लोगों को अब भी दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में, अपराधियों, हत्यारों के रूप में देखा जाता है. अमेरिकी आबादी में काले नस्ल के लोग 13 प्रतिशत हैं. उनमें से 14 प्रतिशत नशीले पदार्थों की लत से पीड़ित हैं. 37 प्रतिशत लोग नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों में शामिल गिने जाते हैं. काले नस्ल के लोग गोरों की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक सजाएं भुगत रहे हैं. एक ही तरह के अपराधों में भी गोरों की तुलना में काले लोग 10 प्रतिशत अधिक सजा भुगत रहे हैं. अमेरिकन ब्यूरो ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में जन्मे काले लोग अपने जीवनकाल में 32 प्रतिशत जेल की सजा भुगत रहे हैं. जबकि लातिनी पुरुष 17 प्रतिशत, गोरे लोग 6 प्रतिशत ही सजा भुगत रहे हैं. यहां गौर करने वाली बात है, कुल अपराधियों में से 83 प्रतिशत गोरे लोग सजा से जल्द छूट पा रहे हैं. शहरों में बढ़ते अपराधों के परिप्रेक्ष्य में तमाम काले नस्ल के लोगों को संदेह की नजर से देखा जाता है. फायरिंग की घटनाओं में न्यूयार्क शहर में 75 प्रतिशत काले नस्ल के लोग संदेह के दायरे में या दोषियों के रूप में पुलिस रिकॉर्डों में दर्ज हैं. दुनिया के सामने काले नस्ल के लोगों को अपराधियों के रूप में प्रस्तुत करने की अमेरिकी सरकार की साजिश को इससे आसानी से समझ सकते हैं.

रोजगार के क्षेत्र में सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर काले लोग हैं. सिर्फ न्यूयार्क शहर में ही काले लोगों में बेरोजगारी 48 प्रतिशत है. फेरग्यूसन में 68 प्रतिशत काले लोग हैं जबकि सिर्फ 3 प्रतिशत ही पुलिस विभाग में हैं.

आवास के मामले में आफ्रीकी–अमेरिकी लोग दुनिया में सबसे ज्यादा आवासीय अलगांव के शिकार हैं. भारत में दलित बस्तियां जिस तरह गांवों के बाहर बहिष्कृत बस्तियों के रूप में होती हैं, काले लोगों की बस्तियां भी गोरी बस्तियों से बाहर होती हैं. उन बस्तियों में न अच्छे पार्क, न अच्छे अस्पताल, आखिर न किराना दुकानें होती हैं. काले और लातिनी लोगों जिन्होंने छत पाया भी था, सब प्राइम संकट के चलते उसे भी खोया और अपना धन भी.

ब्राजिल में नस्लभेदी कत्लेआम का नजारा देखें!

ब्राजिलियन जन सुरक्षा मंच की 9 नवंबर, 2014 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ब्राजिल की पुलिस ने 2013 में 2,212 लोगों को गोली मार दी थी. साओ पौलो की आबादी का 34 प्रतिशत काले लोग हैं जबकि पुलिस द्वारा मारे गए लोगों का 58 प्रतिशत वे ही हैं. 'मैप ऑफ वॉयलेन्स 2012: दि कलर ऑफ होमिसाइड इन ब्राजिल' नामक अध्ययन के अनुसार ब्राजिल में 2002 से 2010 के बीच 2,72,422 काले लोगों की हत्या की गयी जोकि सालाना औसत 30,269 बैठता है.

स्वास्थ्य के मामले में विवक्षा बड़े पैमाने पर है. एक अमेरिकी सर्जन जनरल ने सन् 2000 में कहा था कि स्वास्थ्य विवक्षा को खत्म करने से साल भर में 85,000 काले लोगों की मौतों को रोका जा सकता था.

काले और लातिनी स्कूलों को बहुत कम आर्थिक स्रोत उपलब्ध कराए जाते हैं. 'अच्छे' स्कूलों की तुलना में यहां के बच्चों पर आधा ही खर्च किया जाता है. स्कूल गेट और कक्षाओं के दरवाजों पर मेटल डिटेक्टरों के साथ ये स्कूल जेलों की याद दिलाती हैं.

2005 में जब कत्रीना सुनामी ने तबाही मचायी थी, तब सरकार ने काले लोगों के पुनर्वास एवं अन्य मानवीय सुविधाएं उपलब्ध कराने में आपराधिक लापरवाही बरती. कत्रीना पीड़ित शरणार्थियों के राहत शिविर जहां ऐसे लोग थे जिनके कई अपने सुनामी की भेंट चढ़ गए थे, जो सब कुछ गंवा चुके थे, के बारे में दस बार कांग्रेस सदस्य रह चुके एक व्यक्ति ने बेशर्मी से कहा, 'न्यू ऑर्लियान्स में जनावासों की हमने आखिर साफ–सफाई कर दी है. हम नहीं कर सके लेकिन भगवान ने कर दिखाया'.

अमेरिका में करीबन 23 लाख लोग जेलों में हैं जिनमें से अधिकांश काले नस्ल वाले, लातिनी, एशियायी, स्थानीय रेड इंडियन हैं. और 50 लाख से ज्यादा लोग न्यायालयों का चक्कर लगाने मजबूर हैं. एक हालिया अध्ययन के अनुसार 'हर वो काला युवक जिसके पास माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र न हो, अपने 35 वें जन्म दिवस के पहले जेल में बंद किए जाने के 59 प्रतिशत संभावना है. यह जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि हर तीन में से एक आफ्रीकी–अमेरिकी युवक या तो जेल में है या न्यायिक हिरासत में.

वर्तमान अमेरिका को नस्लभेद के बाद का समाज कहना सफेद झूठ है. आज भी काले लोग चाहे वे जितना भी ऊंचा उठ चुके हों, नस्लीय घृणा से देखे जाते हैं. करीबन 50 साल पहले मैल्कॉम एक्स ने जो कहा था, 'पीएचडी(Ph.D) प्राप्त किसी काले व्यक्ति को वे क्या कहते हैं? हब्शी या नीग्रो', आज भी अक्षरशः सही है. दसियों लाख काले लोगों के लिए हालात पहले की तुलना में और बदतर हो गए हैं.

आधुनिकता, प्राद्योगिकी, संपन्नता साथी इन्सान को समान सामाजिक ओहदा देने से इन्कार कर रही हैं. यह अर्ध सामंती व अर्ध औपनिवेशिक भारत की जाति प्रथा में अनुसूचित जातियों के प्रति भेदभाव की ही तरह का है.

हालांकि अमेरिकी इतिहास में पहली बार गैर–गोरे आफ्रीकी–अमेरिकी बराक हुस्सेन ओबामा राष्ट्रपति बने थे और 2016 दिसंबर तक लगातार दो बार पद पर बने रहे लेकिन उन्होंने काले नस्ल के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, कालों की हत्या की हर घटना के बाद घड़ियाली आंसू बहाने के सिवाय. काले नस्ल के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले मुमिया अबू जमाल जैसे राजनेताओं को दशकों से सलाखों के पीछे सड़ाया जा रहा है. हाल ही में भूतपूर्व न्यूयार्क सिटी ब्लैक पैंथर पार्टी सदस्या अस्साता शकूर जो न्यूजेर्सी के एक जवान की 2 मई, 1973 को हुई हत्या के झूठे आरोप में दोषी ठहरायी गयी हैं और क्यूबा में निर्वासित जीवन बिता रही हैं, को एफबीआई ने 'मोस्ट वांटेड आतंकवादी' घोषित करके उन पर ईनाम की राशि को दोगुना 2 मिलियन डॉलर कर दिया है. ओबामा के दौर में क्रांतिकारी प्रतिरोध को अपराध घोषित करते हुए साम्राज्यवादी अमेरिका के प्रति पीड़ित राष्ट्रीयताओं की जनता की विधेयता को हासिल करने का यही तरीका रहा है. आगे जाकर यह ट्रंप के दौर में और भी विकृत रूप लेगा.

आधुनिक अमेरिका के निर्माण में गुलाम व्यापार की भूमिका ऐतिहासिक अमानवीय व्यवहार

वर्तमान अमेरिका देश की स्थापना ही मानव समाज के इतिहास के दो बड़े घृणित अपराधों–स्थानीय अमेरिकी मूलवासियों(इंडियन्स/रेड इंडियन्स, मेक्सिकनों) की युद्ध और कत्लेआम के जरिए बेदखली व उनकी जमीनों पर बेजा कब्जा करने; हमलों व अपहरण के जरिए दसियों लाख आफ्रीकियों को गुलाम बनाकर व्यापार करने एवं उनसे यहां तक कि बच्चों के साथ भी उन्हें मौत के मुंह में ढकेलने तक की मेहनत कराने की नींव पर हुआ है. अमेरिका का संपूर्ण इतिहास ही विभिन्न राष्ट्रीयताओं जैसे स्थानीय मूलवासियों, आफ्रीकियों और दिक्षिण–पश्चिमी जन जातियों के खून से तर–बतर है. इंग्लैण्ड के लंदन एवं लिवरपुल से माल से लदे जल जहाज आफ्रीका के तटवर्ती शहरों में पहुंचते और वहां माल खाली करके आफ्रीकी देहातों पर हमलें करके बंदी बनाए गए आफ्रीकियों को भरकर अमेरिका, करीबियन द्वीपों में जाते और वहां उन्हें गुलामों के रूप में बेचा जाता था. इन उपनिवेशों में गुलामों द्वारा उत्पादित कपास, चीनी, चावल एवं अन्य माल से लादकर जहाजों को फिर योरोप ले जाया जाता जहां माल को उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में या खाद्यान्न के रूप में बेचकर अथाह मुनाफा कमाया जाता था. यह सिलसिला हर दिन, हर साल, पूरे तीन सौ साल तक बेरोकटोक चलता रहा. इस गुलाम व्यापार, गुलाम आधारित अर्थ व्यवस्था के द्वारा ही जैसा कि मार्क्सवाद के महान शिक्षक कार्ल मार्क्स ने कहा, 'पूंजी के आदिम संचय का उज्वल उदय' हुआ था.

कुल मिलाकर 94 से 120 लाख आफ्रीकियों का अपहरण किया गया, उन्हें बेचा गया व गुलामों के रूप में अमेरिका भेजा गया था. 20 लाख से भी ज्यादा लोग आफ्रीका से समुद्री सफर के दौरान जान गंवाए. गुलाम बनाने के लिए किए गए युद्धों व छापेमारी तथा अपहरण

किए गए लोगों को जंजीरों में जकड़ कर तटवर्ती शहरों तक जबरन ले जाने के दौरान आफ्रीका में ही असंख्य लोग मारे गए. तटवर्ती शहरों में जल जहाजों के इंतजार में बंदीखानों में (बैराकून्स) बंद किए गए लोगों में से कम से कम 8 लाख लोग मारे गए. इस गुलाम व्यापार के पहले नारकीय साल में अमेरिका ले जाए गए आफ्रीकियों को मानसिक रूप से तोड़कर, उन्हें कमजोर करके गुलाम बनाने के लिए मौसमी कैंपों में भेजा गया था. इनमें से एक–तिहाई 1/3 लोग वहीं मौत के मुंह में समा गए.

पुंजीपति व गुलाम मालिकों ने इस बर्बर गुलामी को बाइबल का हवाला देकर न्यायोचित ठहराया. साथ ही नस्लभेद की छद्म वैज्ञानिक विचारधारा जो यह कहता है कि आफ्रीकी और स्थानीय अमेरिकी मूलवासी अनुवांशिक तौर पर निम्न प्रजाति के हैं, का प्रचार–प्रसार किया गया. गोरों का व्यापक हिस्सा जिनके पास गुलाम नहीं हैं और जिनमें सबसे ज्यादा शोषित भी हैं, को इस आधार पर कि वे गुलाम नहीं हैं, स्वयं को मालिक वर्ग के हिस्से के रूप में समझने के भ्रम में रखा गया है. इसीलिए 'गोरे श्रेष्ठ और काले अधम', यह विषैली मालिक वर्ग मानसिकता आज भी जिंदा है, नए रूपों में. यह अमेरिकी सामाजिक ढांचे में अंतःस्थापित है. गुलामी ने सामान्य तौर पर पूंजीवाद और विशेष रूप से अमेरिका की बुनियाद स्थापित करने व उसे विकसित करने में अहम भूमिका निभायी. असल में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि गुलामी के बगैर आज के संयुक्त राज्य अमेरिका की कल्पना ही नहीं की जा सकती है.

गृह युद्ध–मुक्त गुलामों के साथ गद्दारी

अमेरिकी गृह युद्ध में काले लोगों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी. गोरे सैनिकों की तुलना में काले सैनिक दोगुने, अपनी आबादी की तुलना में अनुपातहीन संख्या में मारे गए थे. गृह युद्ध के समय के अमेरिका अध्यक्ष अब्रहाम लिंकन ने आखिर 'यूनियन की सुरक्षा' खातिर गुलामी को रद्द किया. लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि उन्होंने या उत्तर के पूंजीपति या उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों ने गोरे अमेरिका में कालों के लिए आजादी व समानता स्थापित किया है. दरअसल गृह युद्ध के बाद आफ्रीकी–अमेरीकियों को समानता के आधार पर अमेरीकी समाज में आत्मसात करने का एक बढ़िया मौका था. लेकिन ऐसा न करके गुलामों के साथ उत्तर के पूंजीपतियों ने गद्दारी की. दूसरे विश्व युद्ध के बाद दक्षिण से कालों को उत्तर के उद्योगों में लाया गया था या कहे उन्हें जमीनों से छुड़ाकर उत्तर की ओर भगाया गया था. आफ्रीकी अमेरीकियों को मजदूर श्रेणियों में शामिल किया गया लेकिन सबसे कम वेतन वाली, खतरनाक, गंदी नौकरियों में. उन्हें गोरों के बगल में रहने नहीं दिया गया. अनकहे समझौतों, हिंसा, सरकारी नीतियों के सहारे उन्हें गोरों की बसाहटों से दूर बहिष्कृत बस्तियों में बसने मजबूर किया गया था.

1882 से 1964 के बीच अपहनन(समूह द्वारा किसी को बिना मुकदमा चलाए फांसी देना) की गोरे अमेरिकी परंपरा का शिकार बनाकर अपहनन गिरोहों ने 5 हजार काले लोगों की जघन्य हत्या की. युएस सरकार या कोर्ट ने कभी इन्हें रोकने या इन पर कार्रवाई करने की कोशिश तक नहीं की. यह सिर्फ कालों की जमीनें व संपत्ति हड़पने के लिए ही नहीं बल्कि उन्हें जमीनों पर मेहनत करने बाध्य करने, कालों में से किसी को राष्ट्रीय पूंजीपति बनने से रोकने व गोरों की श्रेष्ठता को कायम रखने के लिए किया जाता था.

> ***'ड्रग्स के खिलाफ युद्ध' की बानगी पर एक नजर डालें!***
>
> **21 नवंबर, 2006 की शाम. इंग्लिश एवेन्यू के उत्तर–पश्चिम अट्लाण्टा स्थित अपने घर में 92 साल की कत्रीन जॉनस्टन टीवी देख रही थी. तभी अट्लाण्टा पुलिस विभाग की 'दि रेड डॉग' युनिट 'नो–नॉक' सर्च वारंट के जरिए घर के अंदर जबरन घुस गई और 39 राउण्ड फायर करने के बाद जॉनस्टन के हाथों में बेड़ियां डालकर वहां मारिजुआना(ड्रग) भरा थैला रखकर उन्हें उसी हालत में मरने छोड़कर चली गई.**

काले राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष–ब्लैक पैंथर्स

यह एक सच्चाई है कि गुलामों ने गुलामी के खिलाफ तीखा संघर्ष किया है. सिर्फ अमेरिका में ही 200 गुलाम विद्रोह हुए. अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक रंगमंच पर रूसी क्रांति, औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों का उदय व कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन, दुसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी क्रांति आदि परिघटनाओं के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका में काले लोगों में एक नव चेतना जागृत हुई. 1950 और 1960 के दशक के पूर्वार्ध में दक्षिण में वोट देने, समान शिक्षा आदि मौलिक अधिकारों की मांग करते हुए नागरिक अधिकार आन्दोलन उभरे. 1960 के दशक में अमेरिका ने कालों का तीव्र प्रतिरोध देखा. इसी दौरान जुझारु ब्लैक पैंथर्स आन्दोलन विकसित हुआ. मैल्कम एक्स जैसे नेताओं के क्रांतिकारी दृष्टिकोण व ब्लैक पैंथर्स पार्टी जैसी ताकतों से प्रभावित होकर दसियों लाख लोग मोहल्लों व कैंपसों में उतर गए थे. सैकड़ों अमेरिकी शहरों में लोगों ने विद्रोह किया. प्रदर्शन, जुलूस आम बात बन गए थे. 60 के दशक

के आन्दोलन की सबसे मजबूत बुनियाद काले लोग थे लेकिन इसने युएस के अन्य उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं, विभिन्न राष्ट्रीयताओं के छात्रों, महिलाओं, गोरा सर्वहारा याने 'गरीब गोरों', सैनिकों को संघर्ष की प्रेरणा दी. दो दशकों तक जारी यह आन्दोलन अमेरिका में कई बदलाओं का कारण बना. काले लोगों के सिर उठाकर जीने की परिस्थितियां निर्मित की. आफ्रीकी–अमेरीकियों को महाविद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश करने के अवसर उपलब्ध कराए गए. सामाजिक कल्याण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा–प्रशिक्षण आदि के लिए बजट आबंटन का कुछ विस्तार किया गया था. राजनीति, शासन–प्रशासन में कुछेक महत्वपूर्ण स्थानों को हासिल करने में काले नस्ल के लोगों को अवसर मिले. लेकिन ये सब छोटे–छोटे सुधारों के रूप में ही. आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ. इस मायने में 60 के दशक का काले राष्ट्रीयता मुक्ति संघर्ष एक क्रांतिकारी आन्दोलन जरूर था. लेकिन क्रांति नहीं हुई. शासक वर्गों की सत्ता की नींव हिल गयी लेकिन सत्ता को उखाड़ नहीं फेंका गया था.

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारी संघर्षों व वियतनाम मुक्ति युद्ध तथा युद्ध विरोधी अमेरिकी जनता के आन्दोलनों के उभार के साथ शुरु हुआ काले राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष बाद में उनके धक्का खाने के साथ ही भीषण दमन का शिकार होकर कमजोर पड़ गया. अमेरिका के तत्कालीन अध्यक्ष निक्सन ने दो मुंही नीति बनायी. एक तरफ काले लोगों के एक तबके को सुधारों के जरिए शांत करना, गोरों के साथ एकताबद्ध करना और दूसरी तरफ भीषण दमन के सहारे आन्दोलन का सफाया करना. ब्लैक पैंथर पार्टी के 100 से ज्यादा नेताओं व मुख्य कार्यकर्ताओं को झूठे आरोपों में फंसाकर लंबी सजाएं दिलवाकर जेलों में सड़ाया गया. 20 से ज्यादा मुख्य नेताओं जैसे फ्रेड हैंप्टन और जॉर्ज जैक्सन की हत्या कर दी गयी. केंट स्टेट और मिसिसिपी के ऑल जैक्सन स्टेट के युद्ध विरोधी छात्रों की हत्या की गयी. 25 से ज्यादा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की गयी. रिपब्लिकन पार्टी ने नस्लभेद नीति को बढ़ावा दिया तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने 60 के दशक के काले कार्यकर्ताओं को बुर्जुआ चुनावी राजनीति में लाने का भरसक प्रयास किया. दोनों ही पार्टियों ने कुछ उच्च स्थानों में काले चेहरों को लाने में भिड़ गयी जो जन समुदायों व सत्ताधीशों के बीच एजेंट्स का काम करने लगे थे. काले राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष ने शासक वर्गों के सामने गोरों की श्रेष्ठता को खत्म करके कालों को अमेरिकी समाज में आत्मसात करने के सवाल को फिर एक बार सामने लाया था. लेकिन समानता के वादे को भुलाकर एक बार फिर गद्दारी की गयी. एक साथ दो परिघटनाएं होने लगी. एक तो पूंजीपतियों की जरूरतों के लिए दसियों लाख आफ्रीकी–अमेरीकियों को शहरों के मजदूर बस्तियों में तब्दील किया. दूसरी ओर गोरी श्रेष्ठता या मालिक प्रजाति की मानसिकता को आक्रामकता के साथ बरकरार रखना.

'नशीले पदार्थों के खिलाफ युद्ध'? नहीं, कालों के खिलाफ

अध्यक्ष निक्सन ने इस सोच के साथ कि काले ही असल में पूरी समस्या है, इसलिए एक ऐसी व्यवस्था की रूपकल्पना करनी चाहिए जो इस बात को चिन्हित तो करे लेकिन बाहर से न दिखे, 'ड्रग्स के खिलाफ युद्ध' प्रारंभ किया. यह छद्म युद्ध 1980 में अध्यक्ष बने रोनॉल्ड रीगन द्वारा उच्च स्तर पर ले जाया गया. इसके तहत शासक वर्गों द्वारा योजनाबद्ध ढंग से इन्नर सिटीज के काले युवकों को अत्यधिक अलगांव वाले इलाकों में जहां नौकरियों, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं का घोर अभाव था, में रहने बाध्य किया गया. आजीविका के तमाम अवसरों से जानबूझकर वंचित करके उन इलाकों में ड्रग्स के धंधे का प्रवेश कराया गया था, यहां तक कि सीआईए के गुप्त सहयोग से. इन्नर सिटीज के काले युवक जब आजीविका के लिए मजबूरन ड्रग्स के धंधे से जुड़ गए और ड्रग्स की लत उन्हें लग गया, फिर शुरु हुआ, उत्पीड़ित करने, गिरफ्तार करने, जेलों में सड़ाने यहां तक कि आजीवन बंद करके रखने, सामाजिक अलगांव का शिकार बनाने आदि का अमानवीय दौर. यह आज भी न सिर्फ जारी है बल्कि तीव्र हुआ है. 1996 में तथाकथित उदारवादी अध्यक्ष बिल क्लिंटन ने दसियों लाख गरीबों खासकर महिलाओं को उपलब्ध सामाजिक कल्याण योजनाओं को रद्द करके उन्हें कम से कम रोजी पर काम करने बाध्य किया गया. कई तो खतरनाक धंधों आखिर वेश्यावृत्ति में शामिल हो गईं ताकि खुद जीवित रहकर बच्चों का पालन–पोषण कर सके. यह अमेरिकी शासकों द्वारा हासिल एक बड़ा 'सामाजिक बदलाव' था.

काली चेतना के विभिन्न रूप

आफ्रीकी–अमेरिकी लोगों के संघर्ष व चेतना के इतिहास में एकतावाद, काला राष्ट्रीयतावाद, परिवर्तनवाद की धाराएं मौजूद रहीं. एकतावाद के अनुसार कुछ पढ़े–लिखे, धनी काले लोगों के उच्च पदों पर बैठने से नस्लीय विवक्षा, उत्पीड़न को समाप्त किया जा सकता है. आफ्रीकी–अमेरीकियों के पृथक अस्तित्व, संस्कृति को त्यागकर श्वेत संस्कृति को अपनाने की वह वकालत करता है. वह व्यक्तिगत विकास के जरिए, शिक्षा, संपत्ति अर्जित करने के जरिए, श्वेत नागरिक समाज व संस्कृति के अंतर्भाग बनने के जरिए नस्लीय विवक्षा को खत्म करना चाहता है. औपनिवेशिक अमेरिका के समय में गुलामों के रूप में आकर गोरों के साथ पूरी तरह घुल–मिल जाने वाले, अपनी भाषा, परंपराओं को भुलाने वाले ही ये एकतावादी हैं. 19 वीं सदी में फेडरिक डग्लस एकतावादियों के नेता थे.

काला राष्ट्रीयतावाद के अनुसार काले लोगों को अपने अधीन, अपनी जनता के लिए, स्वयं की विशेष व्यवस्थाओं का निर्माण करना चाहिए. इस राजनीतिक, सांस्कृतिक विचारधारा के मूल पुरुष थे, मैल्कम एक्स और मार्कस गार्वे. इन्होंने काले लोगों को संगठित करने की कोशिश की लेकिन आंतरिक अंतरविरोधों को नहीं देखा. काला राष्ट्रीयतावाद की चेतना, आफ्रीकावासियों की एकता, गोरे नस्लीय दुरहंकार के खिलाफ संघर्ष, वर्गीय शोषण के खिलाफ संघर्ष, आफ्रीकी केंद्रीयकृत संस्कृति, इनके मुख्य नारे हैं. काला राष्ट्रीयतावाद का एक तबका तमाम श्वेतों को एक ही समूह में देखता था. जबकि इलिजा मोहम्मद के नेतृत्व में मुसलमान राष्ट्र(नेशन ऑफ इस्लाम) का तबका अलग से बना. काला राष्ट्रीयतावाद में एक रैडिकल तबका भी है. क्रांतिकारी काले मजदूर फेडरेशन नामक जुझारु तबका भी था. समाजवादी व्यवस्था के निर्माण के लक्ष्य से वर्ग विश्लेषण के आधार पर सभी नस्ल के उत्पीड़ित लोगों को संगठित करने की इन्होंने कोशिश की. काला राष्ट्रीयतावाद का एक और तबका है जो काले उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए 'काला राष्ट्रीयता के उत्पादों को ही खरीदो' नारा दिया था. इस तरह काला राष्ट्रीयतावाद विविधतापूर्ण सिद्धांतों से युक्त है.

वर्गीय बुनियाद पर निर्मित एक और धारा है, परिवर्तनवाद. यह संसाधनों का पुनःबंटवारा करने, समानता के आधार पर राज्य सत्ता का लोकतांत्रीकरण की मांग करता है. 19वीं सदी के फांसी रद्द आन्दोलनकारी, पॉल राब्सन से लेकर फेन्नी लो हैमर तक के जुझारु आन्दोलनकारी इस विचारधारा के हैं. एकतावादी, काला राष्ट्रीयतावादी व परिवर्तनवादी इन तीनों में समय और संदर्भ के अनुसार बदलाव भी आते रहे. एकतावादी मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने जन जीवन के आखिरी दो सालों में परिवर्तनवादी बन गए थे. इन्होंने वियतनाम युद्ध विरोधी आन्दोलन, गरीब जनता के 'चलो वाशिंगटन' आन्दोलन, मेंफिस, टेन्निस्सी इलाकों के काले सफाईकर्मियों के आन्दोलनों को संचालित किया. इसी तरह काले राष्ट्रीयतावादी मेल्कम एक्स बाद में परिवर्तनवादी बन गए थे और 1964 में 'नेशन ऑफ इस्लाम' को छोड़कर उन्होंने आफ्रीकी–अमेरिकी एकता संस्था का गठन किया था.

अमेरिकी समाजवादी क्रांति ही असली समाधान!

आफ्रीकी–अमेरिकी लोगों की समस्या सिर्फ नस्लीय भेदभाव या काला राष्ट्रीयता की समस्या ही नहीं है. वह प्राथमिक रूप से वर्गीय प्रभुत्व से उत्पन्न हुई है. अंतिम विश्लेषण में नस्ल की जड़ों को गोरे प्रभुत्व, आर्थिक शोषण, सामाजिक आधिपत्य के निर्माण में देखना चाहिए. राष्ट्रीयता की समस्या वर्ग समस्या के मातहत ही रहता है. इसे पहचानना व समझना जरूरी है. अन्यथा काले लोगों की विमुक्ति के सारे प्रयास जो सिर्फ नस्लीय भेदभाव एवं काले लोगों के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा तक सीमित होते हैं अंततः गोरे नस्लीय दुरहंकार के वर्गीय निर्माण को ही मजबूत करेंगे. काले लोगों के संघर्ष के इतिहास में ऐसा हुआ भी.

फेरग्यूसन के जन विरोध व अशांति के संदर्भ में अमेरिकी बॉस्केट बॉल खिलाड़ी करीम अब्दुल जब्बार ने सही कहा, 'कालों की हत्याओं को सिर्फ नस्लीय भेदभाव के रूप में नहीं, वर्ग संघर्ष के रूप में देखना चाहिए. नस्ल आधारित हत्याओं के रूप में देखने से काले नस्ल के लोगों की मौलिक समस्याओं का हल संभव नहीं होगा'.

अमेरिका में करोड़ों काले लोगों व गोरे गरीबों की दुस्थिति की जड़ है, अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसकी आर्थिक, राजनीतिक व सैनिक नीतियां एवं रणनीतियां. वह हजारों इस्पाती धागों के साथ इन्हें शोषणमूलक अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ बांधा है. बेहतर शिक्षा जो वास्तव में संभव भी नहीं है, धर्म चाहे ईसाइयत हो या इस्लाम, मजबूत व परंपरागत परिवार, या अहिंसा कोई भी काले राष्ट्रीयता एवं तमाम उत्पीड़ित वर्गों की मुक्ति या बेहतर दुनिया को हासिल नहीं कर सकती हैं. शोषणविहीन समतामूलक समाज व्यवस्था में ही काले लोगों की तमाम समस्याएं हल होंगी. अमेरिकी समाजवादी क्रांति ही तमाम आफ्रीकी–अमेरिकी लोगों, अमेरिका में रह रहे करीबियन, एशियाई, अमेरिकन इंडियन, हिस्सानिक(स्पेइन, पुर्तुगाल या स्पेनिश भाषा बोलने वाले देश), अरब, कुर्द, तुर्की, ईरान राष्ट्रीयताओं सहित गोरे उत्पीड़ित तबकों की समस्याओं का असली समाधान कर सकती है. गोरी श्रेष्ठता को खत्म करके संपूर्ण समानता की स्थापना कर सकती है. काले राष्ट्रीयता के लोगों को ब्लैक बेल्ट साउथ सहित अमेरिका के काले बहुल अन्य इलाकों में स्वायत्त शासन चलाने के अधिकार के लिए, यहां तक कि ब्लैक बेल्ट साउथ में पृथक आफ्रीकी–अमेरिकी गणतंत्र स्थापित करने के अधिकार सहित आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए समाजवादी क्रांति अनिवार्य है. इसीलिए आफ्रीकी–अमेरीकियों को अमेरिकी क्रांति में एक बड़ी भूमिका निभानी होगी. यह बात सही है कि काले लोगों की व्यथा को काले ही बेहतर समझ सकते हैं. लेकिन आज के हालात में सिर्फ काले लोग लड़कर अपनी मुक्ति हासिल नहीं कर सकते हैं.

अमेरिकी मजदूर वर्ग जिसमें काले सहित तमाम अन्य राष्ट्रीयताओं के मजदूर भी शामिल हैं, के नेतृत्व में समाजवादी क्रांति को सफल करने की दिशा में अग्रसर होना ही काले लोगों सहित तमाम राष्ट्रीयताओं के उत्पीड़ित वर्गों के लोगों की असली मुक्ति का रास्ता है.

✦

फर्जी मुठभेड़ों का सिलसिला न सिर्फ जारी है बल्कि तेज हुआ है

दंडकारण्य में पुलिसिया आतंक लगातार जारी है. तत्कालीन आईजी कल्लूरी ने अपने कामयाबों का ब्योरा देते हुए मिशन–2016 में बस्तर संभाग में की गई मुठभेड़ों में 134 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया. मुठभेड़ों के नाम पर की जा रही इन जघन्य हत्याओं पर कई बार सवाल उठाए गए हैं. न सिर्फ मडकम हिडमे की फर्जी मुठभेड़ बल्कि अन्य कुछ फर्जी मुठभेड़ों तथा अत्याचार की घटनाओं के विरोध में जनाक्रोश कई बार आंदोलन का रूप ले लिया था. महिला, जनवादी, मानवाधिकार संगठनों व व्यक्तियों द्वारा कानूनी संघर्ष भी किया जा रहा है. इन प्रयासों के फलस्वरूप बीजापुर जिले में महिलाओं के साथ किए गए अत्याचारों के कुछ मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस देकर पीड़ित महिलाओं को 37 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया. इन आंदोलनों की वजह ही जन विरोधी, खुंखार आईजी कल्लूरी को छुट्टी पर भेजना पड़ा और दमनकारी संगठन 'अग्नि' को भंग करना पड़ा. जाहिर है सरकार ने अपनी दमनकारी नीति को नहीं बल्कि सिर्फ चेहरे को ही बदला है. कल्लूरी की जगह में आये सुंदरराज के बयान से ही नहीं बल्कि उनके आने के बाद घटित घटनाओं से भी इसे आसानी से समझ सकते है.

विगत छह महीनों में बस्तर संभाग ताथा राजनंदगांव व गड़चिरोली में मुठभेड़ों के नाम पर की गई कुछ नृशंस हत्याओं का ब्योरा दे रहे हैं.

10 नवंबर को कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकासखंड के गट्टाकल–गोमा के बीच के जंगलों में शिकार से घर लौट रहे लोगों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी की जिसमें गट्टाकल गांव के एक आदिवासी किसान शोबी कोवाची (38) की मौत हुई. जबकि एक अन्य ग्रामीण घायल हुए थे. अपने जघन्य अपराध को छुपाने पुलिस ने बेशर्मी से यह कह दिया कि मारा गया व्यक्ति एक आम आदिवासी किसान नहीं बल्कि जन मिलिशिया सदस्य था. मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराने, कइयों को घायल करने का मीडिया के जरिए दावा किया. इतना ही नहीं अपनी निर्मम हत्या को मुठभेड़ का रंग देने और इस तरह की क्रूर घटानाओं को बढ़ावा देने, तत्कालीन बस्तर आईजी एसआरपी कल्लूरी समेत पुलिस के कई आला अधिकारी कोयलीबेड़ा गये थे. हत्यारे बीएसएफ तथा जिला पुलिस के जवानों को बधाई दी. साथ ही मुठभेड़ में शामिल जवानों के लिए एक लाख रुपए का इनाम देने की घोषण भी कल्लूरी ने की.

पुलिस की इस गोलीकांड के विरोध में उत्तर बस्तर डिविजन के रावघाट एरिया कमेटी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के अलावा पोस्टर व बैनरों के जरिए विस्तृत प्रचार किया. नवंबर 23 को रावघाट एरिया बंद का सफल आयोजन किया गया. 1 दिसंबर को इसके खिलाफ सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में एक बड़ी रैली व सभा आयोजित की गई. जिसमें लगभग 2,500 की तादाद में जनता शामिल हुई थी. जनता की मांग है कि इस झूठी मुठभेड पर न्यायिक जांच करायी जाए. अपराधी पुलिस बलों पर एफआईआर दायर की जाए और सजा दी जाए. मृतक शोबी कोवाची के परिवार को दस लाख का मुआवजा दिया जाए.

दिसंबर, 2016 से फरवरी, 2017 के बीच माड़ क्षेत्र में पांच बार बड़े पैमाने पर दमन अभियान चलाये गये. इस दौरान जनता के साथ बेरहमी से मार–पीट की गई. पुलिस बल ने गरीब आदिवासी जनता के घरों में घुंस कर लूट–पाट, तोड़–फोड़ किया था. शहीद स्मारकों को ध्वस्त किया गया. मुडमेल गांव में जनता ना सरकार स्कूल के बच्चों के कपड़े और किताबें जलायी गयी. मुडमेल गांव के जंगल में जनता पर की गई अंधाधुंध गोलीबारी में दो महिलाएं घायल हुई.

11 दिसंबर, 2016 की रात को बीजापुर जिले के बासागुडा थाना क्षेत्र के तिम्मापुर गांव के पूनेमपारा में स्थित सीआरपीएफ कैंप के जवानों द्वारा अपने कैंप से महज तीन सौ मीटर की दूरी पर धान के कूप की रखवाली कर रहे पूनेमपारा के ही कुछ युवाओं के ऊपर अंधाधुंध गोलियां दागने पर पूनेम नंदू की मौत हुई. जबकि कक्केम लच्छू घायल हुआ. मृतक नंदू कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच पूनेम सुकलू का बेटा था. अपने जघन्य अपराध को छुपाने हेतु सीआरपीएफ जवानों ने घटना स्थल से अन्य छह युवकों – पांडू कोरसा, अवलम शंकर, सेमला सेंद्रा, कोरसा लच्छू, कोरसा बुधरू के साथ और एक युवक को पकड़ा और उन्हें कैंप ले गए.

नंदू के मारे जाने और लच्छू के घायल होने की सूचना उनके परिजनों को पुलिस ने नहीं दिया. अगले दिन सुबह किन्हीं अन्य लोगों द्वारा नंदू के पिता को यह दुखद बात का पता चला. बेटे के शव को अगले दिन शाम को उन्हें सुपुर्द किया गया. इसके पहले शव देखने के लिए भी उन्हें नहीं बुलाया गया.

घटना स्थल में पकड़े गए लोगों को बुरी तरह यातनाएं देकर अगले दिन शाम को छोड़ दिया गया. इन युवकों को धमकी दी गई कि घटना स्थल में उनके मौजूद होने की बात का खुलासा करने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. युवकों का कहना है कि उनसे गांव के लोगों को यह बताने कहा गया कि वे पुलिस के कब्जे में नहीं बल्कि जंगल में थे. इस घटना के विरोध में दो दिन के बाद जिला बंद का सफल आयोजन किया गया.

स्मरण

राजनांदगांव के अधिवक्ता नरेंद्र बन्सोड का निधन

दलितों व आदिवासियों के कानूनी अधिकारों के लिए आजीवन लड़ने वाले, मजदूरों, माओवादी कार्यकर्ताओं पर लुटेरी सरकारों द्वारा थोपे गए फर्जी मुकदमों की राजनांदगांव के जिला एवं सत्र न्यायालय में पैरवी करने वाले राजनांदगांव के अंबेडकरी नेता, अधिवक्ता नरेंद्र बन्सोड का 29 जून, 2016 को जानलेवा रक्त कैंसर बीमारी की वजह से तमिलनाडु के वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निधन हो गया. 48 वर्ष के बन्सोड का लखोली राजनांदगांव के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया. भिलाई में 26 जनवरी, 1994 को तिरंगा झंडे को उतारकर काला झंडा फहराने वाले युवा संगठन के कार्यकर्ताओं से लेकर भाकपा(माओवादी) की महाराष्ट्र राज्य कमेटी के मातहत काम करने वाले कई कार्यकर्ताओं तक के मुकदमों की पैरवी वे करते रहे. वे एक अंबेडकरी के अलावा जनपक्षधर अधिवक्ता के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी बन्सोड़ के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व सहानुभूति प्रकट करती है.

13 दिसंबर को अनील एवं रामाल नामक दो पीएलजीए कार्यकर्ताओं को पुलस ने मोहंदी गांव के पास निहत्थे पकड़ कर, उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. बाद में गोलियों से भूनकर उनकी निर्मम हत्या की गई.

16 दिसंबर को पुलिस बल द्वारा और एक घोर हत्या को अंजाम दिया गया. बीजापुर जिले के मेटापाल गांव के कुम्मा नामक एक बधिर युवक को मौत के घाट उतारा गया. कुम्मा पोटाम 15–16 दिसंबर की रात अपने दोस्तों भीमा, कारु और सुनील के साथ खेत गया था. वहां से 16 दिसंबर की सुबह लौटते वक्त वह घर के समीप ही एक पेड़ पर लाल चींटी के लिए चढ़ा. इस बीच पुलिस के जवान वहां पहुंच गए. जवानों को अपनी ओर बढ़ता देख कुम्मा के दोस्त भाग खड़े हुए. जबकि बधिर होने की वजह से कुम्मा कुछ सुन न सका. जवानों ने वहां पहुंच कर उसे पेड़ से नीचे उतारा और दोनों हाथ पीछे की ओर कर पेड़ से उसके गमछे से बांध दिया.

जवानों ने एर्रापारा, पटेलपारा और दुरोलपारा के हर घर से 2–4 लोगों को उठा लिया और मजमा सजाया. कुम्मा के पिता सोमारू और कुछ परिजनों को भी कुछ दूरी पर बिठाया गया. इस के बाद कुछ जवान कुम्मा को धारदार हथियार से रेतने लगे और प्रताड़ित किया. यह सब गांव के दर्जनों लोग देख रहे थे. इस बीच जवानों ने बंदूक निकाली और कुम्मा के कंधे, पेट और कॉलर बोन में नजदीक से एक के बाद एक तीन गोलियां मारी. कुम्मा मौके पर ही ढेर हो गया और उसके बाप सहित अन्य परिजन अवाक रह गए.

कुम्मा की मौत देख कर गांव की महिलाओं की चीख–पुकार के बीच ही जवानों ने कुम्मा की बनियान और हाफ पेंट उतारी और उसे गुरिल्ला वर्दी पहना दी. इसके बाद जवान कुम्मा का शव लेकर गंगालूर थाने गए. इतने लोगों की आंखों के सामने की गई इस क्रूर हत्या को हमेशा की तरह बेशर्मी से मुठभेड़ बताया गया.

इस हत्या के विरोध में उमड़े जनांदोलन के चलते हाईकोर्ट ने री–पोस्टमार्टम के लिए आदेश दिया. बाद में कुम्मा का शव कब्र से निकाल कर फिर पोस्टमार्टम किया गया. इस हत्या की मेजिस्ट्रियल जांच भी की जा रही है.

पुलिस बल ने 28 दिसंबर को माड़ क्षेत्र के तीन ग्रामीणों को जंगल में पकड़ कर उनके साथ बुरी तरह मार–पीट की जिसकी वजह तीन पीड़ितों में से एक युवक मासाल की मौत दस दिन के बाद हुई थी.

आगामी 8 मार्च, 2017 को

महिलाओं पर राजकीय दमन व विस्थापन के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गांवों, कस्बों व शहरों में जोरदार ढंग से मनाएं! गांव–गली में सभा–सम्मेलनों व रैलियों का शानदार आयोजन करें! राजकीय दमन के खिलाफ संगठित, व्यापक व जुझारु महिला प्रतिरोधी संघर्षों को संचालित करें!

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद!

महिला बिना क्रांति नहीं, क्रांति बिना मुक्ति नहीं

हर महिला को क्रांतिकारी गुरिल्ला बनना होगा.

पीएलजीए प्रतिरोध व जन संघर्ष

पश्चिम बस्तर

6 सितंबर, 2016 को बीजापुर जिले के तोड़का गांव पर पुलिस ने हमला किया. इस दौरान खेत में काम कर रहे ग्रामीणों पर अंधाधुंध गोलीबारी की. भागते लोगों पर भी गोलीबारी की गई. इस आतंकी बल को सबक सिखाने के लिए मिलिशिया ने ठान ली. जब पुलिस बल वापस जा रहे थे, तीर–धनुष से लैस मिलिशिया ने उन पर जोरदार हमला किया. इस हमले में सीआरपीएफ–कोबरा बटालियन का एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ. बाद में उसने रायपुर के एक अस्पताल में दम तोड़ा.

23 सितंबर, 2016 को बीजापुर जिले के मद्देड एरिया के गोरला गांव में बूबीट्राप विस्फोट होकर एक गोपनीय सैनिक मारा गया, जबकि एक सहायक आरक्षक घायल हुआ.

11 अक्टूबर, 2016 को बीजापुर जिले के नैमेड गांव में मुर्गा बाजार में पीएलजीए ने डीआरजी के जवान तेलाम लखमू पर चाकू से वार कर उसे खतम किया.

20 अक्टूबर, 2016 को बीजापुर जिले के मिरतुल गांव के नजदीक बूबीट्राप विस्फोट में पुलिस का एक जवान मारा गया.

10 नवंबर, 2016 को नेशनलपार्क एरिया के फरसेगढ़ गांव के नजदीक बूबीट्राप विस्फोट में मडरा बुधराम नाम का डीआरजी कमांडो मारा गया.

20 नवंबर, 2016 को भैरमगढ़ के नजदीक बूबीट्राप विस्फोट होकर पुलिस का एक जवान मारा गया.

25 नवंबर, 2016 को बीजापुर से गंगालूर जाने वाली पुलिस की सप्लाई गाड़ी के ऊपर हमला करके पीएलजीए ने दैनिक उपयोग की सामाग्री जब्त की.

2 दिसंबर, 2016 को गश्त पर आए पुलिस के दो जवान ट्राप में फंस कर गंभीर रूप से घायल हो गए.

दक्षिण बस्तर डिविजन

30 सितंबर, 2016 को दोरनापाल गांव के नजदीक बूबीट्राप विस्फोट में पुलिस का एक जवान घायल हुआ. 28 अक्टूबर, 2016 को जगुरगुंडा गांव के पास प्रेशर बम विस्फोट में पुलिस के दो जवान घायल हो गए. 21 नवंबर, को चिंतलनार–बुरकापाल के बीच बूबीट्राप विस्फोट में पुलिस का एक सब इन्स्पेक्टर मारा गया और दो जवान घायल हो गए. इसी दिन माराईगुड़ा के नजदीक प्रशर बम विस्फोट होकर सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया. 6 दिसंबर को जगरगुंडा एरिया के कोंडासावली–कोंदागूडेम के बीच बूबीट्राप विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान मारा गया, जबकि एक जवान घायल हो गया.

दरभा डिविजन

8 अगस्त को कांगेरघाटी एरिया के कांदाम गांव में एक गोपनीय सैनिक को पीएलजीए ने खत्म किया. अगस्त महीने में चांदामेट्टा–बडेगुडरा के बीच पीएलजीए द्वारा किए गए माइन विस्फोट में पुलिस के पांच जवान घायल हुए. 17 अगस्त को कुन्ना–डब्बा के बीच हुई मुठभेड़ में एक डीआरजी कमांडो मारा गया. 4 नवंबर को कांगेरघाटी एरिया के नामा गांव में अग्नि के नेता और टंगिया दस्ते के प्रभारी सामनाथ बघेल को खत्म किया गया.

फसल व वनोपजों के दाम बढ़ाने

27 दिसंबर को फसल व वनोपजों के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर उत्तर बस्तर डिविजन, कांकेर जिला, प्रतापपुर एरिया के आलदंड से कांदाडी तक ग्रामीणों द्वारा एक रैली निकाली गई. इसमें जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के कांदाडी व सित्रम एवं ओर्चा ब्लॉक के कोंगे व पुत्तुवेडा पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए थे. प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए करने व 300 रुपए बोनस देने, प्रति क्विंटल सरसों का समर्थन मूल्य 8000 रुपए, ज्वार का 1400 रुपए करने की मांग की गई. इसके अलावा धान खरीदी केंद्र को नजदीक यानी नदी की दूसरी ओर लाने, स्कूल और अस्पातल की सुविधा देने की मांग भी की गईं.

जोर–शोर से मना पार्टी स्थापना दिवस

सीपीआई (माओवादी) की 12वीं वर्षगांठ के मौके पर 21–27 सितंबर 2016 को दक्षिण गडचिरोली डिविजन के भाम्रागढ़ एरिया में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस दौरान डिविजन कमेटी से आई बुकलेट, पोस्टरों, बैनरों के साथ प्रचार किया गया. बाद में आरपीसी स्तर की दो, गांव स्तर की सात सभाए संचालित की गयी. इस दौरान सीएनएम कलाकारों ने नाच–गाने के साथ जनता का जोश बढ़ाया. इन सभाओं में लगभग दो हजार जनता शामिल हुई थी.

बंद के समर्थन में

ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा सरकार द्वारा देश की जनता पर जारी युद्ध – ऑपरेशन ग्रीनहंट के खिलाफ 5 से 11 अक्टूबर, 2016 तक देशव्यापी विरोध सप्ताह मनाने, 10–11 अक्टूबर को देशव्यापी बंद का सफल आयोजन करने का सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी द्वारा आह्वान किया गया. इस आह्वान को सफल बनाने के लिए दक्षिण गडचिरोली डिविजन के भाम्रागढ़ एरिया में पर्चा, पोस्टरों व बैनरों के साथ प्रचार किया गया था. दो आम सभाएं भी आयोजित की गयी, जिनमें 1200 लोग शामिल हुए.

केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर ऑपरेशन ग्रीनहंट के खिलाफ 5 से 11 अक्टूबर, 2016 तक विरोध सप्ताह 10–11 अक्टूबर को बंद आयोजित

ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा सरकार द्वारा देश की जनता पर जारी युद्ध–ऑपरेशन ग्रीनहंट के तीसरे चरण के हमलों के खिलाफ 5 से 11 अक्टूबर, 2016 तक देशव्यापी विरोध सप्ताह मनाने एवं 10–11 अक्टूबर, 2016 को दो दिनी देशव्यापी बंद का सफल आयोजन करने केंद्रीय कमेटी द्वारा दिए गए आह्वान के तहत दण्डकारण्य में विरोध सप्ताह एवं बंद आयोजित किए गए. दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की ओर से विरोध सप्ताह के दौरान जुलूस, धरना, चक्काजाम, प्रदर्शनों का आयोजन करने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ एक ब्राउचर जारी किया गया था. साथ ही जोन के विभिन्न डिविजनल व एरिया कमेटियों की ओर से पोस्टर, पर्चे के माध्यम से जनता के बीच में केंद्र, राज्य सरकारों की दमनकारी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए व्यापक प्रचार अभियान संचालित किया गया था. जगह–जगह ग्राम व पंचायत स्तर पर सभाएं व रैलियां आयोजित की गयी. बंद के तहत बस्तर संभाग की अधिकांश सड़कें सूनी रही. बंद के दौरान किरंदूल से जगदलपुर के बीच रेल मार्ग बाधित रहा. डीकेएसजडसी द्वारा ब्राउचर में निम्नांकित साप्ताहिक कार्यक्रम जारी किया गया था.

5 अक्टूबर, 2016 को क्रांतिकारी आन्दोलन पर जारी बर्बर राज्य हिंसा का जोरदार विरोध करें!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में देश में जारी क्रांतिकारी आन्दोलन के सफाए एवं तद्वारा देश की प्राकृतिक संपत्ति व संसाधनों को कौड़ियों के भाव देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने के लिए मौजूदा समय में ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा की केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा फासीवादी सैनिक दमन अभियान ग्रीनहंट जोकि देश की उत्पीड़ित–संघर्षरत जनता पर युद्ध है, के तीसरे चरण का पाशविक दमन जारी है.

इसके तहत गांवों पर लगातार हमलें, मारपीट, लूटपाट, आगजनी, तोड़फोड़, अवैध गिरफ्तारियां, झूठे मामलों में फंसाकर जेलों में ठूंसना, मुठभेडें, झूठी मुठभेडें, नरसंहार, झूठा आत्मसमर्पण, झूठा व जहरीला प्रचार, महिला उत्पीड़न, संघर्षरत जनता पर जारी दमन के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना, प्रताड़ित करना, डराना–धमकाना, जानलेवा हमलें करना, वायुसैनिक हेलिकॉप्टरों द्वारा हवाई हमलों के ड्रिल्स, दिन–रात ड्रोनों की निगरानी आदि बेरोकटोक जारी है. सरकार के मार्गदर्शन में पुलिस संरक्षण व प्रत्यक्ष भागीदारी में 'अग्नि' जैसे प्रतिक्रांतिकारी संगठनों के जरिए प्रगतिशील–जनवादी ताकतों को आतंकित किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में मिशन–2016 के नाम पर यह सब जारी है. पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए, जनता ना सरकारें, जन संगठन व दण्डकारण्य की जनता अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस राज्य हिंसा का विरोध–प्रतिरोध कर रही है.

आएं! संघर्षरत जनता की मदद में आगे हाथ बढ़ाएं! जनता पर जारी पाशविक दमन का हर संभव तरीके में विरोध करें, आवाज बुलंद करें, सड़क पर उतरें.

6 अक्टूबर, 2016 को कश्मीरी जनता पर जारी पाशविक दमन के खिलाफ आवाज बुलंद करें!

नवजवान कश्मीरी आन्दोलनकारी बुरहान मुजफ्फर वानी एवं उनके दो अन्य साथियों की भारत सरकार के सशस्त्र बलों द्वारा झूठी मुठभेड में हत्या के बाद कश्मीरी जनता 8 जुलाई से लगातार आन्दोलनरत है. खासकर किशोर व नवजवान कर्फ्यू को धिक्कारते हुए रोज हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं. भारतीय सशस्त्र बलों ने आन्दोलनरत लोगों पर पैल्लेट गन का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हुए विगत दो महीनों में 12,000 लोगों को घायल किया है जिनमें से 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोयी जबकि 80 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई. अंधाधुंध गिरफ्तारियां, लोगों के घरों को आग के हवाले करने जैसी अमानवीय हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. 7 लाख सेना के लौह बूटों तले कश्मीरियों की आजादी की आकांक्षा को रौंदा जा रहा है. कश्मीरी अवाम पैल्लेट गनों का जवाब पत्थरों से देते हुए अपने प्रतिरोध को जारी रखी हुई है जिसमें पुलिस, अर्ध–सैनिक व सैन्य बलों के 5,000 जवानों के घायल होने की बात कही जा रही है. दूसरी ओर कश्मीरी आन्दोलनकारी थानों, कैंपों पर हमले करते हुए हथियार जब्त कर रहे हैं. हाल ही में सेना के 19 जवानों

को खत्म करके 20 को घायल किया गया है.

कश्मीरी जनता की आजादी की आकांक्षा और उनके संघर्ष को खून की नदी में डुबोने वाली भारत सरकार के पाशविक दमन के खिलाफ देश भर में आवाज उठाने की जरूरत है. कश्मीर सहित तमाम राष्ट्रीयताओं के अलग होने सहित आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करें. बुलंद आवाज से ऐलान करें ''कश्मीरी लोगों! तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं.''

7 अक्टूबर, 2016 को दलितों पर हमलों व अत्याचारों के खिलाफ व्यापक व जुझारु आन्दोलन खड़ा करें!

ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी ताकतों के केंद्र में सत्तारूढ़ होने के बाद से देश के दलितों पर हमलें व अत्याचार बढ़ गए हैं. गुजरात के ऊना में मरे हुए मवेशियों के खाल उधेड़ने के परंपरागत पेशे के तहत काम कर रहे दलित युवकों की कथित गो–रक्षकों ने निर्मम पिटाई की थी. उसके बाद एक जबर्दस्त दलित आन्दोलन उठ खड़ा हो रहा है. मरे हुए मवेशियों को न उठाने के निर्णय के साथ अब दलित अपनी आजीविका के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं. दलितों का आन्दोलन दरअसल आत्मसम्मान की लड़ाई है.

ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी संघ परिवार, उसके अनुषांगिक संगठन गो–रक्षा, घर वापसी के नाम पर भाजपा सरकारों के संरक्षण में दलितों पर हमलों, अत्याचारों व जबरन धर्मांतरण को लगातार अंजाम दे रहे हैं. दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के खान–पान की आदतों पर पाबंदी लगा रहे हैं. उनका उपहास उड़ा रहे हैं. अपमानित कर रहे हैं. गो मांस रखने या खाने का आरोप लगाकर हत्या कर रहे हैं. हमारे देश में दलित समस्या बुनियाद में जातीय उत्पीड़न व भूमि समस्या है.

आएं! ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद के खिलाफ जारी दलित आन्दोलन को मजबूत व व्यापक बनाएं! आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, प्रगतिशील–जनवादी धर्म निरपेक्ष ताकतों के साथ मिलकर एक जुझारु संयुक्त मोर्चे का निर्माण करें.

8 अक्टूबर, 2016 को संघर्षरत इलाकों की महिलाओं पर पुलिस, अर्ध–सैनिक बलों द्वारा सामूहिक बलात्कार, हत्या व अत्याचारों के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज करो!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी संघर्ष के इलाकों में पुलिस, अर्ध–सैनिक बलों द्वारा महिलाओं पर अत्याचारों को दमन के औजार के रूप में बेरोकटोक इस्तेमाल किया जा रहा है. जन विरोधी सरकारों द्वारा इसकी खुली छूट दी गयी है. गांवों पर हमलों के समय अवयस्क बच्चियों, युवतियों से लेकर 70 साल की बूढ़ी महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार, उनकी हत्याओं, उन पर अमानवीय यौन उत्पीड़न को अंजाम दिया जा रहा है. गांव में सार्वजनिक रूप से बलात्कार करना, बेदम पिटाई करना, गिरफ्तार महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाते, घसीटते हुए थाना/कैंपों तक ले जाना, ग्रामीण व माओवादी महिलाओं में फर्क करने के नाम पर छातियों को निचोड़कर दूध निकालने जैसे नीच व घृणित हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. मुठभेडों में शहीद होने वाली हमारी महिला कॉमरेडों की लाशों की अश्लील वीडियो क्लिप्स बनाकर इंटरनेट में अपलोड किए जा रहे हैं.

आइए! सरकारी सशस्त्र बलों के इन शर्मनाक, बर्बर, पाशविक कारनामों के खिलाफ एक देशव्यापी जबर्दस्त विरोध आन्दोलन खड़ा करें. संघर्षरत इलाकों की महिलाओं के प्रतिरोधी आन्दोलन की हर संभव मदद करें.

9 अक्टूबर, 2016 को सैनिक सुविधाओं की आपूर्ति समझौते को रद्द कराने आन्दोलन की राह अपनाओ!

लंबे समय से चर्चा व विवादों में रहे इस समझौते पर भारत व अमेरिका ने हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं. यह भारत की संप्रभुता को पूरी तरह अमेरिका के पास गिरवी रखने वाला समझौता है. देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है. महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठानों, युद्ध आपूर्तियों सहित, वायु सैनिक अड्डों, बंदरगाहों की निगरानी, देखरेख एवं युद्ध के समय उनके इस्तेमाल की पूर्ण अनुमति देने वाले इस समझौते से रणनीतिक साझेदार के नाम पर भारत पूरी तरह अमेरिका का पछिलग्गु बन गया है. यह दरअसल दक्षिण एशिया में भारत के विस्तारवादी मंसूबों को मजबूती देते हुए चीन को घेरने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है. दुनिया पर अपने प्रभुत्व को कायम करने की अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए देश एवं जनता के हितों की बलि चढ़ाने वाला समझौता है, यह.

आएं! देश व जनता के हितों के लिए घातक इस समझौते को रद्द कराने, देश की असली संप्रभुता को कायम करने और देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की देशद्रोही नीतियों के खिलाफ एक देशव्यापी मजबूत जन आन्दोलन का निर्माण करें.

✦

(... 18 पेज का शेष)

इससे उसकी राजनीतिक चेतना, क्रांति के प्रति उसका दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता को समझ सकते हैं.

कॉमरेड नरेश अमर रहे!

कॉमरेड पाइके

छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले के मनकिल गांव के एक गरीब आदिवासी परिवार में करीबन 24 वर्ष पहले कॉमरेड पाइके (चिलका) का जन्म हुआ था. जमीन कम होने के चलते उसके परिजन मजदूरी भी करते थे. कॉमरेड चिलका सभी कामों में अपने मां–बाप का हाथ बंटाती थी. उसकी बड़ी बहन और बड़े भाई पेशेवर क्रांतिकारी हैं. उनके प्रभाव से और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति उसकी अभिरुचि की वजह से वह सीएनएम में भर्ती हुई थी. कुछ वक्त के लिए उसमें काम करने के बाद दिसंबर, 2009 में पूर्णकालीन कार्यकर्ता के तौर पर वह क्रांति में आ गई. मार्च, 2010 में उसका तबादला एओबी में हुआ था. वहां सीआरसी कंपनी–1 की सदस्या बनी. वहां की जनता की कुवी भाषा सीख कर वह जनता से जुड़ गई. गांवों में संचालित सभाओं में वह गाना गाती थी. सामूहिक काम, पढ़ाई और व्यायाम में वह सक्रिय रहती थी. जनता, पार्टी और पीएलजीए कतारों के साथ वह मिल–जुलकर रहती थी. ओडिया सीख कर वह ओडिया गाना गाती थी.

2016 में कॉमरेड चिलका का तबादला पीएस–2 में हुआ था. उसके अनुशासन, सैनिक क्षमता और सेवा भावना को ध्यान में रख कर उसे एसजेडसी सदस्य कॉमरेड बाकूरी वेंकट रमणा जो रामागूडा हमले में ही शहीद हुए थे, की गार्ड की जिम्मेदारी दी गई. उस जिम्मेदारी लेने के सिर्फ दो ही महीने में उसने शहादत को पाया. रूमागूडा हमले में घायल होकर, न हिलने की अवस्था में वह चार दिन के बाद पुलिस बलों के हाथ लग गयी. पुलिस गुंडों ने उसे खूब यातनाएं देकर जनता की आंखों के सामने ही 28 अक्टूबर को उसकी निर्मम हत्या की.

कॉमरेड चिलका अमर रहे!

(...आखिरी पेज का शेष)

अर्थात, पार्टी के नेतृत्व में प्रति एक–दो दिनों में एक कार्रवाई को पीएलजीए, जन मिलिशिया बल और क्रांतिकारी जनता द्वारा संचालित करने, जनता व जनमिलिशिया को विभिन्न आर्थिक व राजनीतिक संघर्षों व राज्यहिंसा के खिलाफ प्रतिरोध संघर्षों में संगठित कर सक्रिय रूप से एकजुट करके दुश्मन के दमन के बीच ही हमने क्रांतिकारी आन्दोलन को टिकाकर रख पाये हैं. संक्षिप्त में, इस समयकाल में हमारे द्वारा हासिल हुई सफलताएं इस प्रकार हैं :

1.) कठिन परिस्थितियों में पार्टी कमेटियां, पीएलजीए और संयुक्त मोर्चों की मंचों पर एकजुट होकर संचालित किये गये छोटी, मझौली व बड़ी कार्यनीतिक जवाबी हमलों द्वारा पुलिस, अर्धसैनिक और विभिन्न कमांडो बलों को एक हद तक नुकसान पहुंचाकर, उनकी आक्रामकता पर रोक लगाने के जरिए, जनता व जनमिलिशिया को विभिन्न आर्थिक व राजनीतिक संघर्षों व राज्यहिंसा के खिलापफ प्रतिरोधी संघर्षों में संगठित कर एकजुट करने के जरिए क्रांतिकारी आन्दोलन को बचाया गया. दुश्मन के मनोवैज्ञानिक युद्ध पर क्रांतिकारी प्रचार के जरिए पलटवार करने का प्रयास किया गया.

2.) हम पार्टी, पीएलजीए, विभिन्न स्तर के आरपीसीयों और क्रांतिकारी जन संगठनों को सापेक्षिक तौर पर मजबूत करते हुए, क्रांतिकारी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए लिये गये बोल्शेवीकरण, फील्ड ट्रेनिंग अभियानों को सफल बनाने के जरिए कुछ इलाकों में एक हद तक पार्टी, पीएलजीए और संयुक्त मोर्चो के नेतृत्वकारी शक्तियों व कैडर तथा लाल कमांडरों व योद्धाओं का बोल्शेवीकरण किया गया.

3.) बदलती सामाजिक परिस्थितियों के मुताबिक लोकयुद्ध की कार्यनीतियों को विकसित करने के लक्ष्य से पार्टी के नेतृत्वकारी कतारों द्वारा सामाजिक अध्ययन किया गया. पीएलजीए में पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए राजनीतिक–फौजी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए.

4.) लोकयुद्ध को आगे बढ़ाने के लक्ष्य से राज्य स्तर से लेकर एरिया स्तर तक प्लीनमों को आयोजित कर आंदोलन का सही संश्लेषण और परिस्थितियों का सही आकलन किया गया तथा उचित व्यावहारिक योजना बनायी गयी.

5.) ऑपरेशन ग्रीन हंट के तीसरे चरण के तहत तीव्र स्तर पर जारी वर्गयुद्ध में शोषक–शासक वर्गों की सत्ता को उखाड़ कर हमारे छापामार आधरों (गुरिल्ला बेसों)–विभिन्न स्तरों पर जनसत्ता की इकाइयों के तौर पर जिन इलाकों में आरीपीसीयों की स्थापना की गयी, वहां शोषक–शासक वर्गों द्वारा फिर से अपनी सत्ता पुनःस्थापित करने के लिए कई साजिशें की जा रही हैं. उनका मुकाबला करते हुए विभिन्न स्तरों की आरपीसीयों को बचाया गया और पुनरनिर्माण किया गया. कुछ इलाकों में आरपीसीयों के नेतृत्व में भूमि समतलीकरण अभियान सफल किया गया. कुछ इलाकों में नयी शक्तियों को क्रांतिकारी आंदोलन में – पीएलजीए में उल्लेखनीय संख्या में भर्ती किया गया.

6.) लाल प्रतिरोध वाले इलाकों, गुरिल्ला जोनों व गुरिल्ला बेसों में हजारों जनता द्वारा जल–जंगल–जमीन–इज्जत और अधिकार के लिए, आर्थिक समस्याओं पर, राज्यहिंसा और ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ, विस्थापन के खिलाफ, ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद के खिलाफ कई आन्दोलन चलाये गये.

पीएलजीए के कार्यभार

हमारी पार्टी की एकता कांग्रेस–9वीं कांग्रेस द्वारा लिए

गए केन्द्रीय, प्रधन और फौरी कर्तव्य – डीके, बीजे इलाकों को आधार इलाकों में, गुरिल्ला युद्ध को चलायमान युद्ध में, पीएलजीए को पीएलए में विकसित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, आन्दोलन के नए विस्तार इलाकों को लाल प्रतिरोध इलाकों में, लाल प्रतिरोध इलाकों को गुरिल्ला जोनों में, विकसित गुरिल्ला जोनों को आधार इलाकों में विकसित करना हमारा फौरी कर्तव्य होगा.

पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए द्वारा निम्न लिखित किर्तव्यों को निभाना होगाः

1.) ऑपरेशन ग्रीन हंट के तीसरे चरण, इसके तहत चलाए जा रहे बस्तर मिशन–2016, सारंडा एक्शन प्लान जैसी योजनाओं को परास्त करें! केंद्रीय कर्तव्य को अमल करने के तहत लोकयुद्ध में अधिक सफलताएं हासिल करने के लक्ष्य से आगे बढ़ें!

दुश्मन के केन्द्रीकृत हमले का सामना करने वाले प्रत्येक पीएलजीए कमीशन, कमान और इकाई में उच्च स्तर की आक्रामक स्फूर्ति हमेशा होनी चाहिए. हमारे छापामार बलों के लिए अनुकूल टेर्रेन में जब दुश्मन प्रवेश करता है, तब उस पर अंदर घुसने के बाद या आकर्षित कर हमला करना चाहिए.

2.) सभी स्तरों की पार्टी कमेटियों को बोल्शेवीकरण अभियान के जरिए मजबूत करें! पीएलजीए को बोल्शेवीकरण अभियान और राजनीतिक–फौजी नेतृत्व को विकसित करने की योजना के जरिए मजबूत करें!

3.) महान सर्वहारा वर्ग की सांस्कृतिक क्रांति और ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र विद्रोह की 50वीं वर्षगांठ समारोह, दुनिया को हिला देने वाली रूसी समाजवादी क्रांति के शताब्दी वर्षगांठ समारोह और अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के मार्क्सवादी महान शिक्षक कार्ल मार्क्स की द्वि शताब्दी जयंती उत्सवों को बहुत ही क्रांतिकारी जोशखरोश और स्फूर्ति के साथ मनाएं!

4.) साम्राज्यवादी नयी उदारवादी नीतियों के खिलाफ विस्थापन आदि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं पर बड़े पैमाने पर जनता को राजनीतिक आंदोलनों में एकजुट करें! उन्हें लोकयुद्ध के साथ जोड़ें! क्रांतिकारी व जनवादी संगठनों, शक्तियों, व्यक्तियों और व्यापक जनता को गोलबंद करते हुए व्यापक व मजबूत जन आंदोलन का निर्माण करें!

5.) ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद के खिलाफ क्रांतिकारी शक्तियों, जनवादियों, प्रगतिशील शक्तियों, संगठनों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और धर्मनिरपेक्षतावादियों को एकजुट कर मजबूत और जुझारू आंदोलन का निर्माण करें!

6.) जनवादी मूल्यों की रक्षा करें! मानवाधिकारों को पाशविक रूप से कुचलने और घोर उल्लंघन कर रहे वर्दीवाले दुश्मन के बलों को और सादे वर्दीवाले उनके प्रतिक्रांतिकारी व प्रतिक्रियावादी संगठनों को सजा दें! उनके खिलाफ जनता और जनवादी ताकतों को गोलबंद कर संघर्ष करें!

हमारी पार्टी जनवाद और मानवाधिकार के मूल्यों को ऊंचा उठाते हुए, उनकी रक्षा करती है व प्रोत्साहन देती है. वह सभी तरह की मौलिक स्वतंत्राताओं और प्राथमिक अधिकारों का, खासकर विचारों को प्रकट करने की आजादी, बैठक करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, न्याय के लिए खड़े होने व लड़ने के अधिकारों का सम्मान करती है.

7.) पीएलजीए को संगठित करें!

पार्टी नेतृत्व में पीएलजीए को यह भरोसा देना और प्रयास करना चाहिए कि उसके लाल कमांडर और योद्धा एक निश्चित समयावधि के अंदर पार्टी सदस्य के रूप में विकसित हो जाएं, निश्चित कालावधि में राजनीतिक–फौजी प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि दैनिक राजनीतिक शिक्षा भी हासिल करें, ताकि वे उच्च क्रांतिकारी मनोबल विकसित कर सकें और वर्तमान बदलवों को क्रांतिकारी दिशा के अनुसार समझ सकें.

8.) प्रत्येक स्तर पर पूरी कमीशन व कमान व्यवस्था को विकसित करें!

पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के मार्गदर्शन में सीएमसी समूचे देश में जनयुद्ध के स्तर को विकसित करने के लिए दिशानिर्देशन जारी करती है, पूर्वी एवं मध्य रीजनल ब्यूरो स्तरों की ऑपरेशन की कमानों और एसएएमसी/एसएमसीयों को समन्वय करती है, जहां कैडर और साजो–सामान की कमी है, उसको भेज कर मजबूत करने के लिए मदद करती है.

फौजी कमिशन व कमान का संचालन अवश्य ही सही ढंग से करना होगा. कमिशन और कमान के जिम्मेदार सदस्यों को अपने विभाग की जिम्मेदारी को प्राथमिकता देते हुए उसे पालन करना होगा.

9.) पीएलजीए के बलों को राजनीतिक–सैनिक प्रशिक्षण दें!

पीएलजीए में नए रंगरूटों, लाल कमांडरों एवं इकाइयों के ज्ञान, तकनीकी स्तर तथा कौशल (स्किल) को समयानुकूल बढ़ाने के लिए राजनीतिक– सैनिक पाठ्यक्रम तय करके शिक्षा देनी होगी. इसे नियमित व समय–समय पर संचालित करना होगा. नए रंगरूटों के लिए प्राथमिक शिक्षा जिला/जोनल कमेटियों द्वारा दे सकते हैं या लाल योद्धाओं के लिए जरूरी अनुशासन व स्किल्स सिखाने के लिए कमीशनों व कमानों द्वारा संचालित करनेवाली शिक्षा पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षित कर सकते हैं. सभी स्तरों की कमानों के लिए विशेष पाठ्यक्रमों को बनाकर उन्हें राजनीतिक–सैद्धांतिक प्रशिक्षण देना होगा. महिला कमांडरों को तैयार और विकसित करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम को बनाकर राजनीतिक–सैद्धांतिक प्रशिक्षण देना होगा.

सभी लाल कमांडरों और योद्धाओं को सैनिक सिद्धांत, बुनियादी सैनिक पाठ्यक्रम–बीएमसी, फील्ड ट्रैनिंग गाइड, एक्सप्लोजिव व इंप्रूवाइजड एक्सप्लोजिव, फायर एण्ड मूवमेंट, रात्रि युद्ध, अर्बन कंबैट, एम्बुश, रेड और शार्ट सरप्राइज एटैकों पर, जनयुद्ध, गुरिल्ला युद्ध के उसूलों, पीएलजीए के संविधान, पीएलजीए हैण्ड बुक पर प्राथमिक ज्ञान जरूर

उपलब्ध करवाना होगा.

10.) हमेशा सतर्क रहें!

हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, रुटीन कार्यक्रमों में डूबकर लापरवाही बरतना नहीं चाहिए. हमने ऐलान किया है कि हम जरूर ऑपरेशन ग्रीन हण्ट को हराएंगे. इसलिए उससे संबंधित सभी पहलुओं– कारपेट सेक्युरिटी, किलेबंदी कैंपों, मनोवैज्ञानिक युद्ध, इंटेलिजेन्स, झूठा सुधार, सैनिक हमले, प्रतिक्रांतिकारी गुटों से हमें बचना होगा. हम जब एक कार्यनीतिक जवाबी हमले को सफल करते हैं तब और सतर्क रहना होगा.

पीएलजीए हमेशा दुश्मन की साजिशों और धोखों के बारे में, उनके सशस्त्र हमलों के बारे में, उनके सभी तरह के 'मीठे' बमों के बारे में और भीतरघात से सतर्क रहना होगा. दुश्मन की किसी भी तरह के हमले–धोखे से जनता के हित, पार्टी के लक्ष्य को, पार्टी नेतृत्व को सुनियोजित तरीके से बचाना पीएलजीए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है.

हमें हमारे राजनीतिक, सांगठनिक, सैनिक और सांस्कृतिक कर्तव्यों को निभाने में धैर्य व साहसिकता दिखानी होगी और अवांछित कोई भी शक्ति अंदर न घुसे–ऐसी सतर्कता बरतनी होगी.

सेन्ट्रल मिलिटरी कमीशन का आह्वान :

प्रिय कामरेडो व मित्रों!

हमें हमारे देश के लिए असली आजादी हासिल करना अभी भी बाकी है. भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में संगठित जनता और मजबूत जनसेना ही उसे हासिल कर सकती है. कृषि क्रांति को ही धुरी बनाकर, हमारे देश का शोषण करने वाले साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीपति और बड़ा सामंती वर्गों को दीर्घकालीन लोकयुद्ध के जरिए उखाड़ फेंककर, नव जनवादी क्रांति को सफल करके ही हम उत्पीड़ित जनता की वास्तविक मुक्ति हासिल कर सकते हैं. इसके लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है. संसदीय मार्ग द्वारा व्यवस्था में कोई मौलिक बदलाव संभव नहीं है, जिसे इतिहास ने कई बार साबित किया है. देश में रोज–रोज गहराता जा रहा अर्ध–औपनिवेशिक और अर्ध–सामंती शासन व्यवस्था का फासीवादी स्वभाव व चरित्र नव जनवादी क्रांति की जीत को सुनिश्चत कर रहा है और भौतिक आधर तैयार कर रहा है.

सर्वहारा के नेतृत्व में मजदूर–किसान, निम्न पूंजीपति एवं देशीय पूंजीपति वर्गों को संगठित करके सशस्त्र संघर्ष को प्रधन संघर्ष के रूप में, जनसेना को प्रधन सांगठनिक रूप में और अन्य सभी संघर्ष तथा सांगठनिक रूपों को समन्वय करके लड़ते हुए भारतीय अर्ध–औपनिवेशिक और अर्ध–सामंती व्यवस्था को कब्र में डाल कर, चार उत्पीड़ित वर्गों की लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित कर सकते हैं, सभी उत्पीड़ित वर्गों, राष्ट्रों, तबकों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली नव जनवादी क्रांति के कार्यक्रम को लागू कर सकते हैं. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज साम्राज्यवाद निर्देशित एल.आई.सी. रणनीति के तहत हमारी पार्टी और जनयुद्ध को पूरी तरह सफाया करने के लिए दुश्मन द्वारा जारी ऑपरेशन ग्रीन हण्ट को हराने के लिए हमारी पूरी ताकत को झोंक दें , केन्द्रित करें! इसके लिए रुकावट बने प्रत्येक पहलू से पार पाने हेतु दृढ़निश्चय व आत्मबलिदान की चेतना के साथ प्रयास करें!

मजदूर–किसान, मध्यम वर्ग आदि उत्पीड़ित जनता! छात्रा–युवा, बुद्धिजीवियों–कलाकारों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों! जनवादी–प्रगतिशील शक्तियों! जनहितैषियों, देशभक्तों! आइए, देश के विकास में बड़ी रुकावट बनी साम्राज्यवादी, सामंतवादी शोषण के जंजीरों को तोड़ने के लिए सर्वहारा वर्ग की पार्टी भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में वीरतापूर्वक लड़ें! हजारों लाखों की संख्या में युवती–युवक भर्ती होकर हमारी पार्टी व पीएलजीए को मजबूत करें! सभी तरह के संशोधनवादियों व प्रतिक्रांतिकारियों के खिलाफ लड़ते हुए, पहले ही कई अनुभवों से संपन्न भारतीय जनयुद्ध की लाइन को और विकसित करते हुए नव जनवादी क्रांति को जीत की ओर आगे बढ़ाएं! जनता– जनता–जनता ही इतिहास का निर्माता है! अजेय है! जनयुद्ध अजेय है! इस न्यायपूर्ण युद्ध में फासीवादी शोषक वर्ग अंत में अपनी हार और विनाश से बच नहीं सकते! व्यापक उत्पीड़ित जनता उठ खड़े हो, तो शोषणकारी किलाओं को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं. उनकी हार और जनता की जीत अनिवार्य है!

- ✦ ऑपरेशन ग्रीन हंट को परास्त करें! लोकयुद्ध में अधिकाधिक विजय हासिल करते हुए केन्द्रीय कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ें!
- ✦ पीएलजीए को संगठित कर व्यापक इलाकों में विस्तार करने के लक्ष्य से दुश्मन का सफाया कर हथियार जब्त करें!
- ✦ सभी स्तरों में पार्टी कमेटियों, पीएलजीए फारमेशनों और जन निर्माणों को बोल्शेवीकरण अभियान के जरिए मजबूत करें!
- ✦ सशस्त्रा कृषि क्रांति में व्यापक किसान जनता को गोलबंद करें!
- ✦ सामंतवाद और साम्राज्यवाद विरोधी वर्ग संघर्ष में मजदूर–किसान आदि व्यापक उत्पीड़ित जनता को एकजुट करें!
- ✦ ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद के खिलाफ मजबूत और जुझारू आंदोलन का निर्माण करें!
- ✦ पीएलजीए को पीएलए के रूप में विकसित करने के लिए बड़ी संख्या में युवक–युवतियों को भर्ती करें!
- ✦ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) जिन्दाबाद!
- ✦ मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद जिन्दाबाद!

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ,

सेन्ट्रल मिलिटरी कमीशन,

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

देशभर में छापामार युद्ध–लोकयुद्ध को तेज व व्यापक करें!

ऑपरेशन ग्रीन हण्ट को परास्त करें!

[पीएलजीए की 16वीं वर्षगांठ के अवसर पर सेन्ट्रल मिलिटरी कमीशन (सी.एम.सी.), भाकपा (माओवादी) द्वारा जारी संदेश के कुछ महत्वपूर्ण अंश]

प्रिय कामरेडों व मित्रों!

2 दिसम्बर, 2016 को पीएलजीए की स्थापना को 16 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस 16वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की तरफ से सेन्ट्रल मिलिटरी कमीशन (सी.एम.सी.) की ओर से सभी पार्टी कमेटियों व सदस्यों, सैनिक कमीशनों–कमानों, पीएलजीए के लाल कमांडरों व योद्धाओं, जनमिलिशिया बलों, क्रांतिकारी जन सरकारों के प्रतिनिधियों तथा क्रांतिकारी जनसंगठनों के नेता व कार्यकर्ताओं को लाल सलाम पेश किया जाता है. साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीपति व बड़े सामंती वर्गों के खिलाफ नव जनवादी क्रांति को सफल बनाने के लिए संघर्षरत भारतीय जनता की सेवा में कठिन परिश्रम और साहसिक संघर्षों के जरिए इस सालभर में आपके द्वारा हासिल जीतों के लिए आप सभी का सीएमसी लाल अभिवादन पेश करती ह. सीएमसी समूचे देश में छापामार युद्ध–जनयुद्ध को तेज व व्यापक करते हुए दुश्मन का चौतरफा हमला–आपरेशन ग्रीन हण्ट को हराने के लिए जनता को बड़े पैमाने पर राजनीतिक आन्दोलनों व प्रतिरोधी संघर्षों में गोलबंद करने के लक्ष्य से पीएलजीए की 16वीं वर्षगांठ को दिसम्बर 2 से 8 तक व्यापक ग्रामीण इलाकों और शहरों व कस्बों में क्रांतिकारी उत्साह के साथ जोरशोर से मानने का आहवान करती है.

कामरेडों! हमारी पार्टी के संस्थापक नेता, शिक्षक व भारतीय क्रांति के महान नेता कामरेड चारु मजुमदार और कामरेड कन्हाई चटर्जी द्वारा निर्देशित दीर्घकालीन लोकयुद्ध की राह पर हमारी पीएलजीए आगे बढ़ रही है। विश्व समाजवादी क्रांति में यह एक अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग की सैन्य टुकड़ी के रूप में भारतीय नव जनवादी क्रांति की राह पर सामना करने वाली नई चुनौतियों का बराबर जवाब देने के लिए पार्टी के नेतृत्व में अपने–आप को ढालने के लिए अथक प्रयास कर रही है. हमारे प्रिय नेता और अमर शहीद कामरेड श्याम, महेश और मुरली के सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते हुए, हजारों शहीदों के खून से सींची राह पर आगे बढ़ रही है.

ऑपरेशन ग्रीन हंट के तीसरे चरण के तहत फासीवादी केन्द्र एवं राज्यों के सरकारी सशस्त्रा बलों द्वारा क्रांतिकारी इलाकों में क्रांतिकारियों और क्रांतिकारी जनता पर जारी पाशविक हमलों का साहस के साथ मुकाबला करते हुए पिछले साल भर में इस धरती के 183 उत्तम पुत्र–पुत्रियों और क्रांतिकारी जनता ने (सीआरबी–3, दंडकारण्य–132, बिहार–झारखण्ड–19, एओबी–10, ओड़िशा–11, तेलंगाना–7, पंजाब–1) अपनी अनुमोल जानों की कुरबानी दी. इनमें 42 वीरांगनाएं शामिल हैं. कुल मिलाकर इस साल भर में हुए नुकासान बहुत ज्यादा हैं. सेन्ट्रल मिलिटरी कमीशन अपना सिर झुकाकर इन अमर शहीदों को शत्–शत् लाल अभिवादन पेश करती है. समूचे पार्टी कतारों, पीएलजीए बलों और जननिर्माणों का सीएमसी आहवान करती है कि वे इनके क्रांतिकारी लक्ष्य, इनके द्वारा स्थापित आदर्शों को ऊंचा उठावें व इनके द्वारा दर्शायी गयी राह पर आगे कदम बढ़ावें और लक्ष्य हासिल करने के लिए अंतिम दम तक संघर्षपथ पर डटे रहें, क्रांतिकारी आंदोलन को अगली मंजिल तक आगे बढ़ाने की कसम खाएं!

राजनीतिक–फौजी क्षेत्रों में हासिल प्रगति :

इस सालभर में हमारी पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए बलों द्वारा खासकर राजनीतिक–फौजी क्षेत्रों में हासिल हुई प्रगति इस प्रकार है :

दुश्मन के पाशविक हमले का विभिन्न कार्यनीतिक जवाबी अभियानों और कार्रवाइयों द्वारा हमारी पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए बलों ने व्यापक जनता की मदद से मुकाबला किया. पीएलजीए द्वारा पिछले दिसम्बर से अभी तक विभिन्न छापामार जोनों और लाल प्रतिरोध इलाकों में 228 छापामार कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया. इनमें 103 कार्रवाइयां सीधे दुश्मन के बलों पर संचालित की गयी, जिनमें से 4 बड़ी कार्रवाइयां, 5 मझौले कार्रवाइयां, 94 छोटी कार्रवाइयां शामिल हैं. इन छोटी कार्रवाइयों में उल्लेखनीय बात यह है कि इनमें से 23 कार्रवाइयां बूबीट्रैप की कार्रवाइयां हैं. कुल मिलाकर इन पूरी कार्रवाइयों में पीएलजीए द्वारा 75 अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों का सफाया किया गया और 170 को घायल किया गया.

इसी तरह राज्य प्रायोजित प्रतिक्रांतिकारी खुफिया गिरोहों को, पुलिस मुखबिर–कोवर्टों की जाल को, जनविरोधी राजनेताओं और वर्ग दुश्मनों का सफाया करने के लिए पीएलजीए द्वारा 75 कार्रवाइयां चलायी गयी, जिनमें 80 लोगों का सफाया किया गया. इस तरह की कार्रवाइयों और जन अदालतों में जनता के फैसले के मुताबिक कई जनविरोधियों को घायल किया गया या शारीरिक दंड दिया गया.

(शेष पेज 39 में...)